रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एन.)—73

REGISTERED NO. D. (D. N.)—73

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 44] नई दिल्ली, शनिवार, नवम्बर 1, 1986/कार्तिक 10, 1908
No. 44] NEW DELHI, SATURDAY, NOVEMBER 1, 1986/KARTIKA 10, 1908

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

(रक्षा मंत्रालय को छोड़ कर) भारत सरकार के मंत्रालयों द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं
Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence)

विधि और न्याय मंत्रालय

(विधि कार्य विभाग)

नई दिल्ली, 17 अक्तूबर, 1986

सूचना

का० आ० 3707.—नोटरीज नियम, 1956 के नियम 6 के अनुसरण में सक्षम प्राधिकारी द्वारा यह सूचना दी जाती है कि श्री के० वी० शिव प्रसाद एडवोकेट ने उक्त प्राधिकारी को उक्त नियम के नियम 4 के अधीन एक आवेदन इस बात के लिए दिया है कि उसे बंगलूर व्यवसाय करने के लिए नोटरी के रूप में नियुक्त किया जाए।

2. उक्त व्यक्ति को नोटरी के रूप में नियुक्ति पर किसी भी प्रकार का आक्षेप इस सूचना के प्रकाशन के चौदह दिन के भीतर लिखित रूप में मेरे पास भेजा जाए।

[सं 5 (43)/85—न्या०]

MINISTRY OF LAW & JUSTICE

(Department of Legal Affairs)

New Delhi, the 17th October, 1986

NOTICE

S.O. 3707.—Notice is hereby given by the Competent Authority in pursuance of rule 6 of the Notaries Rules, 1956, that application has been made to the said Authority, under rule 4 of the said Rules, by Shri K. V. Shiva Prasad Advocate for appointment as a Notary to practise in Banglore.

2. Any objection to the appointment of the said person as a Notary may be submitted in writing to the undersigned within fourteen days of the publication of this Notice.

[No. F. 5(43)/85-Judl.]

नई दिल्ली, 20 अक्टूबर 1986

सूचना

का० आ० 3708.—नोटरीज नियम, 1956 के नियम 6 के अनुसरण में सक्षम प्राधिकारी द्वारा यह सूचना दी जाती है कि श्री के एल सिंघल, एडवोकेट ने उक्त प्राधिकारी को उक्त नियम के नियम 4 के अधीन एक आवेदन इस बात के लिए

दिया है कि उसे कुतुब रोड एरिया/रामनगर/पहाड़गंज/देशबंधु गुप्ता रोड में व्यवसाय करने के लिए नोटरी के रूप में नियुक्त किया जाए ।

2. उक्त व्यक्ति की नोटरी के रूप में नियुक्ति पर किसी भी प्रकार का आक्षेप इस सूचना के प्रकाशन के चौदह दिन के भीतर लिखित रुप में मेरे पास भेजा जाए ।

[सं० 5(68)/86-न्या०]

New Delhi, the 20th October, 1986

NOTICE

S.O. 3708.—Notice is hereby given by the Competent Authority in pursuance of rule 6 of the Notaries Rules, 1956, that application has been made to the said Authority, under rule 4 of the said Rules, by Shri K. L. Singhal, Advocate for appointment as a Notary to practise in Qutab Road, Ram Nagar Paharganj/Desh Bandhu Gupta Road.

2. Any objection to the appointment of the said person as a Notary may be submitted in writing to the undersigned within fourteen days of the publication of this Notice.

[No. F. 5(68)/86-Judl.]

का० आ० 3709.—नोटरीज नियम, 1956 के नियम 6 के अनुसरण में सक्षम प्राधिकारी द्वारा यह सूचना दी जाती है कि श्री शिव शंकर व्यास, एडवोकेट ने उक्त प्राधिकारी को उक्त नियम के नियम 4 के अधीन एक आवेदन इस बात के लिए दिया है कि उसे बीकानेर व्यवसाय करने के लिए नोटरी के रूप में नियुक्त किया जाए ।

2. उक्त व्यक्ति की नोटरी के रूप में नियुक्ति पर किसी भी प्रकार का आक्षेप इस सूचना के प्रकाशन के चौदह दिन के भीतर लिखित रूप में मेरे पास भेजा जाए ।

[सं० 5(71)/86-न्या०]

आर० एन० पोद्दार, सक्षम प्राधिकारी

S.O 3709.—Notice is hereby given by the Competent Authority in pursuance of rule 6 of the Notaries Rules, 1956, that application has been made to the said Authority, under rule 4 of the said Rules, by Shri Shiv Shanker Vyas Advocate for appointment as a Notary to practise in Bikaner.

2. Any objection to the appointment of the said person as a Notary may be submitted in writing to the undersigned within fourteen days of the publication of this Notice.

[No. F. 5(71)/86-Judl.]

R. N. PODDAR, Competent Authority

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली, 23 अक्तूबर, 1986

आदेश

का० आ० 3710.—केन्द्रीय सरकार, दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना, अधिनियम 1946 (1946 का 25) की धारा 6 के साथ पठित धारा 5 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राजस्थान सरकार की सहमति से, भारतीय दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) की धारा 302 के अधीन दंडनीय अपराधों के और उक्त अपराध के संबंध में या उससे संबंधित प्रयत्नों, दुष्प्रेरणों और षड़यंत्रों के तथा महंत प्रकाश पुरी की हत्या के बारे में पुलिस थाना सोजत सिटी (पाली) राजस्थान में रजिस्ट्रीकृत मामला सं 139/86, तारीख 12 जुलाई, 1986 के संबंध में वैसे ही तथ्यों से उद्भूत वैसे ही संव्यवहार के अनुक्रम में किए गए अन्य अपराधों के अन्वेषण के लिए दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना के सदस्यों की शक्तियों और अधिकारिता का विस्तार संपूर्ण राजस्थान राज्य पर करती है ।

[सं 228/24/86-ए० वी० डी० II]

जी सीतारमन, अवर सचिव

(Department of Personnel & Training)

New Delhi, the 23rd October, 1986

ORDER

S.O. 3710.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 5 read with section 6 of the Delhi Special Police Establishment Act, 1946 (25 of 1946), the Central Government, with the consent of Government of Rajasthan, hereby extends the powers and jurisdiction of the members of the Delhi Special Police Establishment to the whole of the State of Rajasthan for the investigation of offence punishable u/s. 302 of the Indian Penal Code, 1860 (45 of 1860) and attempts, abetments and conspiracies in relation to, or in connection with, the said offence and any other offence committed in the course of the same transaction arising out of the same facts in regard to case No. 139/86 registered at Police Station Sojat City (Pali) on 12-7-1986 in connection with the murder of Mahant Prakash Puri.

[No. 228/24/86-AVD.II]

G. SITARAMAN, Under Secy.

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

(बैंकिंग प्रभाग)

नई दिल्ली, 16 अक्तूबर, 1986

का० आ० 3711.—बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) की धारा 53 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक की सिफारिश पर, एतद्द्वारा यह घोषणा करती है कि उक्त अधिनियम की धारा 9 के उपबंध बारी दोआब बैंक लिमिटेड पर दिनांक 14 सितम्बर 1987 तक उस सीमा तक लागू नहीं होंगी, जहां तक उनका संबंध उसके द्वारा प्रेमगढ़, जिला होशियारपुर पंजाब में धारित भू-संपत्ति से है ।

[संख्या 15/26/83-बी ओ -III]

एम० एस० सीतारमन, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

(Banking Division)

New Delhi, the 16th October, 1986

S.O. 3711.—In exercise of the powers conferred by section 53 of the Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949) the Central Government, on the recommendation of the Reserve Bank of India, hereby declares that the provisions of section 9 of the said Act shall not apply to Bari Doab Bank Ltd.

for a period upto the 14th September, 1987 in respect of the landed property held by it at Premgarh, Hoshiarpur District, Punjab.

[No. 15/26/83-B.O. III]

M. S. SEETHARAMAN, Under Secy.

वाणिज्य मंत्रालय

(मुख्य नियंत्रक, आयात एवं निर्यात का कार्यालय)

नई दिल्ली, 17 अक्तूबर, 1986

आदेश

आ०3712.—मैसर्स एस० एन० गोयनका एण्ड कम्पनी (प्रा०) लि०, नई दिल्ली गोयनका हाऊस, 44, कम्युनिटी सैन्टर, जमरुदपुर, कैलाश कालौनी एक्सटेंशन, नई दिल्ली को जी० सी० ए० से डैमिनार बैनी के अतिरिक्त पुर्जों/संघटकों का आयात करने के लिए 12,00,000/- (बारह लाख रु० मात्र) मूल्य का एक आयात लाइसेंस सं० पी/ए0492192, दिनांक 29-11-85 दिया गया था।

2. पार्टी ने उपर्युक्त लाइसेंस की अनुलिपि प्रति जारी किए जाने का इस आधार पर आवेदन किया है कि मूल विनिमय नियंत्रण प्रति बैंक को साख पत्र के प्रयोजन के लिए भेजे जाने के दौरान खो गई है। कुल राशि जिसके लिए विनिमय नियंत्रण प्रति अपेक्षित है वह 12,00,000 (बारह लाख रु० मात्र) है। मैसर्स एस० एन० गोयनका एण्ड कम्पनी (प्रा) लि , नई दिल्ली इस बात से सहमत है और वचन देते हैं कि यदि मूल लाइसेंस बाद में मिल जाता है तो वह उसे इस कार्यालय को रिकार्ड के लिए लौटा देंगें ।

3. अपने तर्क के समर्थन में आवेदक ने 1985—88 की आयात-निर्यात प्रक्रिया पुस्तक के अध्याय 2 के पैरा-36 में यथा अपेक्षित शपथ पत्र दाखिल किया है । मैं, तदनुसार संतुष्ट हूं कि पार्टी द्वारा मूल लाइसेंस सं० पी/ए/0492192 दिनांक 29-11-85 (विनियम नियंत्रण प्रति) खो गई है। यथासंशोधित आयात नियंत्रण आदेश 1955 दिनांक 7-12-1955 की उप धारा 9 (गग) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए मैसर्स एस० एन० गोयनका एण्ड कम्पनी (प्रा०) लि०, नई दिल्ली को जारी किया गया लाइसेंस सं० पी/ए/0492192, दिनांक 29-11-85 की उक्त विनिमय नियंत्रण प्रति को तदनुसार रद्द किया जता है।

4. पार्टी को उक्त मूल लाइसेंस के उपलक्ष्य में आयात लाईसेंस की अनुलिपि प्रति (केवल विनिमय नियंत्रण प्रति) को अलग से जारी किया जा रहा है।

[फा० सं० 8-एस/एआर/85-86/जी०एल०एस०]

पाल बैक, उप मुख्य नियंत्रक, आयात एवं निर्यात

कृते मुख्य नियंत्रक, आयात एवं निर्यात

MINISTRY OF COMMERCE

(Office of the Chief Controller of Imports and Exports)

New Delhi, the 17th October, 1986

ORDER

S.O. 3712.—M/s. S. N. Goenka & Co. (P) Ltd., New Delhi, Goenka House, 44-Community Centre, Zamrudpur, Kailash Colony Extn., New Delhi was granted an Import Licence No. P|A|0492192 dt. 29-11-85 for Rs. 12,00,000|- (Rupees Twelve Lakhs only) for the import of spare|components of Daimler Beny from G.C.A.

2. The party has applied for issue of duplicate copy of the above mentioned licence on the ground that the original Exchange Control copy has been lost in transit which being sent to the Bank for L|C purpose. The total amount for which the Exchange Control Copy is required is Rs. 12,00,000|- (Rupees twelve lakhs only). M|s. S. N. Goenka & Co (P) Ltd., New Delhi agrees and undertakes to return the original licence if traced later on to this office for record.

3. In support of their contention, the licence has filed an affidavit as required in Para 86 of chapter II of Hand Book of Import & Export Procedures 85—88. I am accordingly satisfied that the original Import Licence No. P|A|0492192 dt. 29-11-85 (E.C. Copy) has been lost by the party. In exercise of the power conferred under sub-clause 9 (CC) of Import Control Order, 1955 dt. 7-12-1955 as amended the said Exchange Control Copy of the Import Licence No. P|A|0492192 dt. 29-11-85 issued to M|s. S. N. Goenka & Co. (P) Ltd., New Delhi is hereby cancelled.

4. A duplicate import licence (Exchange Control Copy only) is being issued to the party in lieu of original said above.

[F. No. 8-S|Air|85-86|GLS]

PAUL BECK, Dy. Chief Controller of Imports & Exports

For Chief Controller of Imports & Exports

(संयुक्त मुख्य नियंत्रक आयात एवं निर्यात का कार्यालय)

(केन्द्रीय लाइसेंस क्षेत्र)

नई दिल्ली, 23 सितम्बर, 1986

रद्द करने का आदेश

का० आ०3713.—सर्वश्री जाकू इलैक्ट्रानिक्स, दुकान नं 4 के पीछे, गुड़ मंडी, दिल्ली-7 को ए० टी० रिकार्डस इत्यादि का उत्पादन करने के लिए दिनांक 19-12-83 को 162870/-रु का लाइसेंस नं० पी०एस०/1959824 प्रदान किया गया था ।

आवेदक ने सूचित किया है कि लाइसेंस सं० पी/एस/1959824 दिनांक 19-12-83 राशि 162870/- जो कि ए० एम० 84 की अवधि के लिए जारी किया गया था उसकी मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रति कहीं गुम हो गई है/अस्थानास्थ हो गई है ।

5 संतुष्ट हूं कि मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रति गुम/अस्थानास्थ हो गई है ।

आयात व्यापार नियंत्रण आदेश 1955 दिनांक 7-12-55 (यथा संशोधित अद्यायतन के उपधारा 9 (डी) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए लाइसेंस सं -पी/एस/

1959824 दि० 19-12-83 राशि 1,62,870/-रु० की मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रतिलिप के रद्द करने के आदेश एतद् द्वारा पारित किये जाते हैं ।

[सं० दिल्ली/जे-11/आटो/ए० एम०-84/ए० यू०-1/सी०एल०ए०/3305]

डा० आर० के० धवन, उप मुख्य नियंत्रक आयात एवं निर्यात कृते संयुक्त मुख्य नियंत्रक, आयात एवं निर्यात

(Office of the Joint Chief Controller of Imports and Exports)

(Central Licensing Area)

New Delhi, the 23rd September, 1986

CANCELLATION ORDER

S.O. 3713.—M/s. Jaku Electronics, Behind Shop No. 4, Gur Mandi Delhi-7, were granted import licence No. P/S/1959824 dt. 19-12-83 for Rs. 1,62,870/- for manufacturing of A.T. recorders etc.

The applicant has reported that Exchange Control copy of the licence No. P/S/1969824 dt. 19-12-83 for Rs. 162870/- issued for the period of AM. 84 has been lost/misplaced.

I am satisfied that the Exchange Control copy of the licence have been lost/misplaced.

In exercise of the power conferred on me under Sub-Clause 9(d) of the Import Trade Control Order, 1955 dated 7-12-1955 as amended upto date, Exchange control copy of the licence No. P/S/1959823 dt. 19/12/83 for Rs. 1,62,870/- is hereby cancelled.

[F. No. Delhi/J-11/Auto/AM.84/AU.I/CLA/3305]

DR. R. K. DHAWAN, Dy. Chief Controller of Imports & Exporsts for Jt. Chief Controller of Imports & Exports.

कृषि मंत्रालय

(कृषि और सहकारिता विभाग)

नई दिल्ली, 14 अक्तूबर, 1986

का०आ० 3714—केन्द्रीय सरकार, बहु राज्य सहकारी समिति अधिनियम, 1984 (1984 का 51) की धारा 4 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा भारत सरकार की अधिसूचना सं एल० 11012/1/85-एल एण्ड एम दिनांक 18 अगस्त, 1986 का अधिक्रमण करते हुए कृषि मंत्रालय (कृषि और सहकारिता विभाग) में संयुक्त सचिव श्री एस० सोम को आगामी आदेशों तक सहकारी समितियों के केन्द्रीय रजिस्ट्रार के पद पर नियुक्त करती है ।

[सं० एल०-11012/1/85-एल एण्ड एम]

आर०डी० मित्तल, अवर सचिव

MINISTRY OF AGRICULTURE

(Department of Agriculture and Co-operation)

New Delhi, the 14th October, 1986

S.O. 3714.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the Multi-State Co-operative Socities Act, 1984 (51 of 1984) and in supersession of the Notification of the Government of India No. L-11012/1/85-L&M dated the 18th August, 1986, the Central Government hereby appoints Shri S. Som, Joint Secretary in the Ministry of Agriculture (Department of Agriculture and Co-operation) as the Central Registrar or Co-operative Societies, until further orders.

[No. L-11012/1/85-L&M]

R. D. MITTAL, Under Secy.

उद्योग मंत्रालय

(कम्पनी कार्य विभाग)

नई दिल्ली, 21 अक्तूबर, 1986

का० आ० 3715.—एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 (1969 का 54) की धारा 26 की उपधारा (3) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा इस अधिसूचना के अनुलग्नक में उल्लिखित उपक्रमों, जो कथित अधिनियम के अन्तर्गत विलय, समामेलन, समापन एवं राष्ट्रीयकरण के कारण अब अस्तित्व में नहीं है, के पंजीकरण के निरस्तीकरण को अधिसूचित करती है ।

[सं 16/12/86-एम०-3]

एल० सी० गोयल, अवर सचिव

अधिसूचना सं० 16/12/86-एम -III का अनुलग्नक

1.	अल्कली एंड केमिकल कार्पोरेशन आफ इंडिया लि	25/70	विलय
2.	बेकर ग्रे एंड कम्पनी लि	1119/75	राष्ट्रीयकृत
3.	क्रीसेन्ट डाइज एंड केमिकल्स लि० [पहले आई सी आई (इंडिया) लि०]	175/75	विलय
4.	ग्रीव्स इन्टरनेशनल लि	1271/76	विलय
5.	हुस्टिग्स मिल्स लि	79/70	समामेलित
6.	इंडिया ट्रेडिंग (होल्डिंग) प्रा० लि०	478/70	विघटित
7.	पुडुकोटाई कम्पनी (प्रा०) लि०	578/70	परिनिर्धारित
8.	पुडुकोटाई कार्पोरेशन प्रा० लि०	564/70	परिनिर्धारित
9.	टैंट कैप्स इलक्ट्रोनिक्स लि०	1683/84	समामेलित
10.	नव भारत टुबाको कम्पनी लि	1682/84	समामेलित

MINISTRY OF INDUSTRY

(Department of Company Affairs)

New Delhi, the 21st October, 1986

S.O. 3715.—In pursuance of Sub-Section (3) of Section 26 of the Monopolies and Restrictive Trade Practices Act, 1969 (54 of 1969), the Central Government hereby notifies the cancellation of the registration of the undertakings mentioned in the Annexure to this Notification which are no longer in existence on account of merger, amalgamation, liquidation and nationalisation under the said Act.

[No. 16/12/86-M-III]

L. C. GOYAL, Under Secy.

Annexure to the Notification No- 16/12/86 M. III

1.	Alkali & Chemical Corporation of India Ltd.	25/70	Merged
2.	Becker Gray Co. Ltd.	1119/75	Nationalised
3.	Crescent Dyes and Chemicals Ltd. [Formerly I.C.I. (India) Ltd.]	175/75	Merged
4.	Greaves International Ltd.	1271/76	Merged
5.	Hastings Mills Ltd.	79/70	Amalgamated
6.	India Trading (Holding) Private Ltd.	478/70	Dissolved
7.	Puddukottai Co. (P) Ltd.	578/70	Liquidated
8.	Puddukottai Corporation Private Ltd.	564/70	Liquidated
9.	Tata Cap; Electronics Ltd.	1683/84	Amalgamtd
10.	Nava Bharat Tobacco Co. Ltd.	1682/84	Amalgamated

इस्पात और खान मंत्रालय

(खान विभाग)

नई दिल्ली, 10 सितम्बर 1986

आदेश

का० आ० 3716:—केन्द्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 1965 के नियम 13 के उप नियम (i) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति द्वारा निदेश दिया जाता है कि इस आदेश की संशोधित अनुसूची के कालम (2) में उल्लिखित सामान्य केन्द्रीय सेवा समूह "क" पदों के बारे में उक्त अनुसूची के कालम (3) में संबंधित प्रविष्टि में उल्लिखित प्राधिकारी उक्त पदों को धारण करने वाले सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ अनुशासनिक कार्यवाही करने के लिए सक्षम प्राधिकारी होगा।

अनुसूची

क्रम सं.	पद का विवरण	अनुशासनिक कार्यवाही करने के लिए सक्षम प्राधिकारी
1	2	3
1.	भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण में अधिकतम 1600/– रुपये वेतनमान वाले पद	महानिदेशक, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण
2.	भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण में अधिकतम 1600/—रुपये से अधिक और 2500/– रुपये तक वेतनमान वाले पद	सचिव, भारत सरकार, खान विभाग

नोट — यद्यपि कालम (3) में उल्लिखित प्राधिकारी अनुशासनिक कार्यवाही करने के लिए सक्षम है तथापि, केन्द्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 1965 के नियम 15 के अधीन जांच रिपोर्ट पर कार्यवाही राष्ट्रपति द्वारा की जायेगी।

[संख्या ए-36019/1/86-एम-II(i)]

जे० बी० मुनिराजुलु, अवर सचिव

MINISTRY OF STEEL & MINES

(Department of Mines)

New Delhi, the 10th Sept., 1986

ORDER

S.O. 3716.—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 13 of the Central Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules, 1965 the President hereby directs that in respect of the posts in the General Central Service Group 'A' specified in column (2) of the Schedule annexed to this order, the authority specified in the corresponding entry in column (3) of the said Schedule shall be the authority competent to initiate disciplinary proceedings against the Government servants holding the said posts.

SCHEDULE

S. No.	Description of post	Authority competent to initiate disciplinary proceedings
1	2	3
1.	Posts in the Geological Survey of Indian in the Scale of pay carrying the maximum of Rs. 1600.	Director General, Geological Survey of India.
2.	Posts in the Geological Survey of Indian in the scale of pay carrying maximum exceeding Rs. 1600 and upto Rs. 2500.	Secretary to the Government of India in the Department of Mines.

Note :— Though the authorities mentioned in column (3) are competent to initiate disciplinary proceedings, the action on the inquiry report under rule 15 of the Central Civil Service (Classification, Control and Appeal) Rules, 1965, shall be taken by the President.

[No. A-36019/1/86-M-II (i)]

J. B. MUNIRAJULU, Under Secy.

संचार मंत्रालय

(दूरसंचार विभाग)

नई दिल्ली, 17 अक्तूबर, 1986

का. आ. 3717:—स्थायी आदेश संख्या 627, दिनांक 8 मार्च, 1960 द्वारा लागू किए गए भारतीय तार नियम, 1951 के नियम 434 के खंड III के पैरा (क) के अनुसार महानिदेशक, दूरसंचार विभाग ने उसिलमपट्टी तथा चेलमपट्टी टेलीफोन केन्द्र, तमिलनाडु सर्किल, में दिनांक 1-11-1986 से प्रमाणित दर प्रणाली लागू करने निश्चय किया है।

[संख्या 5/33/86 पी एच बी]

के. पी. शर्मा, सहायक महानिदेशक (पी.एच.बी.)

MINISTRY OF COMMUNICATIONS

(Department of Telecommunications)

New Delhi, the 17th October, 1986

S.O. 3717.—In pursuance of para (a) of Section III of Rule 434 of Indian Telegraph Rules, 1951, as introduced by S.O. No. 627 dated 8th March, 1960, the Director General, Department of Telecommunications, hereby specified 1-11-1986 as the date on which the Measured Rate System will be introduced in Usilampatti and Cheliampatti Telephone Exchange, Tamil Nadu Circle.

[No. 5-33|86-PHB]

K. P. SHARMA, Assistant Director General (PHB)

परिवहन मंत्रालय

(नागर विमानन विभाग)

नई दिल्ली, 15 अक्तूबर, 1986

शुद्धि-पत्र

का.आ. 3718 :—इस विभाग की दिनांक 25 सितम्बर, 1986 की अधिसूचना संख्या एवी-18013/3/86-ए.सी. में निम्नलिखित शुद्धि की जाती है :—

क्रम संख्या 7

श्री जैड० आर० रंगूनवाला के स्थान पर

श्री जैड० जी० रंगूनवाला पढ़ें

[सं० एवी०-18013/3/86-एसी]

आर.एन. भार्गव, अवर सचिव

MINISTRY OF TRANSPORT

(Department of Civil Aviation)

New Delhi, the 15th October, 1986

CORRIGENDUM

S.O. 3718.—In this Department's Notification No. Av. 18013/3/86-AC dated the 25th September, 1986, the following correction is made :--

S. No. 7 :

For Shri Z. R. Rangoonwala,

Read Shri Z. G. Rangoonwala.

[No. Av. 18013/3/86-AC]

R. N. BHARGAVA, Under Secy.

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

नई दिल्ली, 16 अक्तूबर, 1986

का. आ. 3719:—यत: केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में दहेज से पालेज तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पाइपलाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए।

और यत: यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिये एतद्उपाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

अत: अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइपलाइन बिछाने के लिए आक्षेप, सक्षम प्राधिकारी तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग, निर्माण और देखभाल प्रभाग, मकरपुरा रोड, बडोदरा-9 को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टत: यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत।

अनुसूची

दहेज से पालेज तक पाइप लाइन बिछाने के लिए।

राज्य : गुजरात जिला : भरूच तालुका : भरूच

गांव	सर्वे नं	हैक्टर	आरे	सेन्टीयर
1	2	3	4	5
टंकारीया	694	0	07	00
	695	0	03	00
	696	0	18	00
	727	0	02	00
	726	0	11	00
	724	0	05	00
	723	0	12	00
	722	0	03	00
	721	0	05	00
	720	0	06	00
	717	0	04	00
	728	0	14	00
	713	0	32	00
	715	0	03	00
	714	0	17	00
	649	0	12	00
	651	0	20	00
	652	0	05	00
	653	0	27	00
	958	0	04	00
		0	10	00
	757	0	10	00
	755	0	16	00

1	2	3	4	5
	756	0	05	00
	754	0	26	00
	753	0	08	00
	588	0	08	00
	581	0	18	00
	582	0	07	00
	579	0	15	00
	कार्ट ट्रक	0	02	80
	643	0	04	00
	639	0	28	00
	650	0	12	00
	463	0	10	00
	464	0	34	00
	465	0	11	00
	475	0	08	00
	474	0	19	00
	471	0	14	00
		0	02	00

[सं. ओ-12016/165/86-ओएनजी-डी-4]

MINISTRY OF PETROLEUM & NATURAL GAS

New Delhi, the 16th October, 1986

S.O. 3719.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from Dahej to Palej in Gujarat State pipeline should be laid by the Oil & Natural Gas Commission.

And whereas, it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto :

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the said land to the Competent Authority, Oil & Natural Gas Commission, Construction & Maintenance Division, Makarpura Road, Vadodara. (390 009).

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be hear in person or by legal practitioner.

SCHEDULE

Pipeline from Dahej to Palej

State : Gujarat District & Taluka : Bharuch

Village	Survey No.	Hect-	Are	Centi-are
1	2	3	4	
Tankariya	694	0	07	00
	695	0	03	00
	696	0	18	00
	727	0	02	00
	726	0	11	00
	724	0	05	00
	723	0	12	00
	722	0	03	00
	721	0	05	00
	720	0	06	00
	717	0	04	00
	718	0	14	00
	713	0	32	00
	715	0	03	00
	714	0	17	00
	649	0	12	00
	651	0	20	00
	652	0	05	00
	653	0	27	00
		0	04	00
	958	0	10	00
	757	0	10	00
	755	0	16	00
	756	0	05	00
	754	0	26	00
	753	0	08	00
	588	0	08	00
	581	0	18	00
	582	0	07	00
	579	0	15	00
	Cartt track	0	02	80
	643	0	04	00
	639	0	28	00
	650	0	12	00
	463	0	10	00
	464	0	34	00
	465	0	11	00
	475	0	08	00
	474	0	19	00
	471	0	14	00
		0	02	00

[No.O-12016/165/86-ONG-D-4]

का.आ. 3720—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में जो.जो.एस-XI से जो.जो.एस.-I तक पट्रोलियम के परिवहन के लिये पाइपलाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए।

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिये एतदुपाबद्ध अनुसूची में वर्णित (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति उस भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग निर्माण और देखभाल प्रभाग, मकरपुरा रोड बड़ौदरा-9 को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन करेगा कि क्या वह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत ।

अनुसूची

जी.जी.एस. XI से जी.जी.एस. I तक पाइप लाइन बिछाने के लिए ।

राज्य गुजरात : जिला व तालुका : गांधीनगर

गांव	ब्लाक नं.	हैक्टेयर	आरे	सेन्टीयर
अडालज	553	0	00	70
	547	0	19	60
	546	0	22	20
	542	0	46	40
	541	0	16	20
	538	0	25	40
	539	0	07	80
	531	0	41	00
	530	0	22	00

[सं. ओ–12016/166/86–ओएनजी डी–4]

S.O. 3720.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that the transport of petroleum from G.G.S. XI to G.G.S.I. in Gujarat State pipeline should be laid by the Oil & Natural Gas Commission.

And whereas, it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto :

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein :

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the said land to the Competent Authority, Oil & Natural Gas Commission, Construction & Maintenance Division, Makarpura Road, Vadodara. (390 009).

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be hear in person or by legal practitioner.

SCHEDULE

PIPELINE FROM GGS XI TO GGS I.

State : Gujarat District & Taluka : Gandhinagar.

Village	Block No.	Hectare	Are	Centiare
1	2	3	4	5
Adalaj	553	0	00	70
	547	0	19	60
	546	0	22	20
	542	0	46	40
	541	0	16	20
	538	0	25	40
	539	0	07	80
	531	0	41	00
	530	0	22	00

[No. O-12016/166/86-ONG-D-4]

का.आ. 3721—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में झालोरा–53 से झालोरा–51 तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पाइपलाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए ।

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिये एतदुपाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है ।

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है ।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग निर्माण और देखभाल प्रभाग, मकरपुरा रोड़ बड़ोदरा-9 को इस अधिसूचना को तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा ।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन करेगा कि क्या वह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत ।

अनुसूची

झालोरा 53 से झालोरा–51 तक पाइप लाइन बिछाने के लिए ।

राज्य : गुजरात जिला : मेहसाना तालुका : कडी

गांव	सर्वे नं.	हैक्टेयर	आर	सेंटीयर
मेरडा	158/1	0	27	0

[सं.ओ–12016/167/86–ओएनजीडी-4]

S.O. 3721.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from Jhalora-53 to Jhalora-51 in Gujarat State pipeline should be laid by the Oil & Natural Gas Commission.

And whereas, it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto :

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein :

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the said land to the competent Authority, Oil & Natural Gas Commission, Construction & Maintenance Division, Makarpura Road, Vadodara. (390 009).

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be hear in person or by legal practitioner.

SCHEDULE

PIPELINE FROM JHALORA 53 TO JHALORA-51

State : Gujarat District : Mehsana Taluk : Kadi

Village	Survey No.	Hectare	Are	Centriare
1	2	3	4	5
Merda	158/1	0	27	0
	224	0	04	00
	225	0	10	10
	226	0	09	00
	227	0	07	70
	228	0	07	50
	230	0	29	10
	2	0	45	00
	3	0	25	20
	5	0	08	50
	9	0	07	20
	8	0	08	70
	30	0	15	60

[No. O-12016/167/86-ONG-D4]

का.आ. 3722—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाईप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना का. आ. सं. 2768 तारीख 23-7-86 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था ।

और यतः समक्ष प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है ।

और आगे, यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है ।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है ।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में विहित होने के बजाय तेल और प्राकृतिक गैस आयोग में, सभी बाधाओं से मुक्त रूप में, घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा ।

अनुसूची

डब्लू.एस.एस.ए. से जी.जी.एस. सोब 1 तक पाइप लाइन बिछाने के लिए ।

राज्य : गुजरात जिला व तालुक : मेहसाना

गांव	सर्वे नं.	हैक्टेयर	आर	सेंटीयर
हेडवा हनुमन्त	161	0	06	10
	221	0	01	40
	223	0	03	60

[सं. ओ-12016/108/86-ओएनजीडी-4]

S.O. 3722.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum & Natural Gas S.O. 2768, dated 23-7-86 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline.

And whereas, the Competent Authority has under Subsection (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further, whereas the Central Government has, after considering the said report decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further, in exercise of power conferred by subsection (4) of the section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Oil & Natural Gas Commission free from encumbrances.

SCHEDULE

Pipeline from WSSA to GGS SOB. 1

State : Gujarat District & Taluka : Mehsana

Village	Survey No.	Hectare	Are	Centiare
1	2	3	4	5
Hedvai—Hanmant	161	0	06	10
	221	0	01	40
	223	0	03	60
	224	0	04	00
	225	0	10	10
	226	0	09	00
	227	0	07	70
	228	0	07	50
	230	0	29	10
	2	0	45	00
	3	0	25	20
	5	0	08	50
	9	0	07	20
	8	0	08	70
	30	0	15	60

[No. O-12016/108/86-ONG-D-4

का० आ० 3723—यतः पैट्रोलियम और खनिज पाइपलाईन भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना का०आ०सं० 4283 तारीख 7-8-85 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उक्त अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग के अधिकार को पाइपलाईनों को बिछाने के लिये अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था ।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है ।

और आगे, यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है ।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाईन बिछाने के प्रयोजन के लिये एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है ।

और आगे उक्त धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने की बजाय तेल और प्राकृतिक गैस आयोग में, सभी बाधाओं से उक्त रूप में, घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

अनुसूची

कूप नं झालोरा -44, से झालोरा-10 तक पाइप लाइन बिछाने के लिये ।

राज्य : गुजरात जिला : मेहसाना तालुका : कड़ी

गांव	सर्वे नं	हैक्टेयर	आर	सैन्टीयर
आद्रज	1893	0	05	00
	1892/1	0	03	75
	कार्ट ट्रक	0	01	50
	1856	0	03	50
	1857	0	19	05
	1858	0	04	50
	1859	0	07	50
	1862	0	07	50

[सं. ओ-12016/97/85-ओ एन जी डी-4]

S.O. 3723.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum & Natural Gas S.O. 4283, dated 7-8-85 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pirelines (Acquisition of Right of User in Land) Act 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule anpended to that notification for the purpose of laying pipeline.

And whereas, the Competent Authority has under Subsection (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further, whereas the Central Government has, after considering the said report decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further, in exercise of power conferred by subsection (4) of the section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Oil & Natural Gas Commission free from encumbrances.

SCHEDULE

Pipelne from well No. Jhalora 44 to Jhalora-10

State : Gujarat District : Mehsana Taluka : Kadi

Village	Survey No.	Hectare	Aro	Centiare
1	2	3	4	5
Adraj	1893	0	05	00
	1892/1	0	03	75
	Cart Track	0	01	50
	1856	0	03	50
	1857	0	19	05
	1858	0	04	50
	1859	0	07	50
	1862	0	07	50

[No. O-12016/97/85-ONGD-4]

का०आ० 3724—यतः पैट्रोलियम और खनिज पाइपलाईन भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के भारत सरकार के पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना का०आ० सं० 3491 तारीख 17-7-85 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग के अधिकार को पाइपलाईनों को बिछाने के लिये अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था ।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है ।

और आगे, यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है ।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाईन बिछाने के लिये प्रयोजन के लिये एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है ।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने की बजाय तेल और प्राकृतिक गैस आयोग में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा ।

अनुसूची

कूप नं जे आर आई (जे-29) से जी जी एस–झालोरा 2 तक पाइपलाईन बिछाने के लिये ।

राज्य : गुजरात जिला : मेहसाना तालुका : कड़ी

गांव	सर्वे नं	हैक्टेयर	आर	सैन्टीयर
आदराज	1327	0	09	72
	1145/1	0	05	00
	1145/2	0	03	10
	1143	0	07	53
	1141/1	0	09	22
	1141/2	0	02	64
	1136/1	0	08	79
	1135	0	05	77
	1134	0	09	07

[सं O-12016/80/85-ओ एन जी-डी-4]

S.O. 3724.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum & Natural Gas S.O. 3491, dated 17-7-85 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline.

And whereas, the Competent Authority has under Subsection (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further, whereas the Central Government has, after considering the said report decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further, in exercise of power conferred by sub-section (4) of the section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Oil & Natural Gas Commission free from encumbrances.

SCHEDULE

PIPELINE FROM WELL NO. JRI (J-29) TO GGS JHALORA-II

State : Gujarat District : Mehsana Taluka : Kadi

Village	Survey No.	Hectare	Are	Centtiaer
1	2	3	4	5
Adraj	1327	0	09	72
	1145/1	0	05	00
	1145/2	0	03	10
	1143	0	07	53
	1141/1	0	09	22
	1141/2	0	02	64
	1136/1	0	08	79
	1135	0	05	77
	1134	0	09	07

[No. O-12016/80/85-ONG D-4]

का आ 3725—यतः पैट्रोलियम और खनिज पाइपलाईन भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना का०आ० सं 3492 तारीख 17-7-85 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग के अधिकार को पाइपलाईनों को बिछाने के लिये अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था ।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है ।

और आगे, यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है ।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाईन बिछाने के प्रयोजन के लिये एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है ।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने की बजाय तेल और प्राकृतिक गैस आयोग में, सभी बाधाओं से मुक्त रूप में, घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा ।

अनुसूची

जी जी एस झालोरा II से मेन ट्रंक लाइन तक लाइन बिछाने के लिये ।

राज्य : गुजरात जिला : मेहसाना तालुका : कड़ी

गांव	सर्वे नं	हैटेक्यर	आर	सैन्टीयर
आद्रज	1103/1	0	03	60
	1103/2	0	06	60
	1105	0	14	32
	1106	0	02	40
	1107/1	0	03	90
	1107/2	0	02	40

[सं O-12016/81/85-ओ एन जी डी-4]

S.O. 3725.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum & Natural Gas S.O. 3492 dated 17-7-85 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline.

And whereas the Competent Authority has under Sub-Section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of the section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Oil & Natural Gas Commission free from encumbrances.

SCHEDULE

PIPELINE FROM GGS JHALORA II TO MAIN TRUNK LINE

State : Gujarat Disrtrict : Mehasana Taluka : Kadi

Village	Survey No.	Hectare	Are	Centiare
1	2	3	4	5
Ad raj	1103/1	0	03	60
	1103/2	0	06	60
	1105	0	14	32
	1106	0	02	40
	1107/1	0	03	90
	1107/2	0	02	40

[No. O-12016/81/85-ONGD-4]

का०आ० 3726—यतः पैट्रोलियम और खनिज पाइपलाईन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय पैट्रोलियम विभाग की अधिसूचना का०आ०सं० 2767 तारीख 23-7-86 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाईनों को बिछाने के लिये अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था ।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है ।

और आगे, यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है ।

अब' अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाईन बिछाने के प्रयोजन के लिये एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है ।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में विहित होने के बजाय तेल और प्राकृतिक गैस आयोग में, सभी बाधाओं से मक्त रूप में, घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा ।

अनुसूची

एस०एन० मी० आई०-एस० एन० सी० एस-एस एन० सी० बी० से एस० एन० ए० के० तक पाइप लाईन बिछाने के लिए ।

राज्य : गुजरात जिला : व तालुका : मेहसाना

गांव	ब्लाक नं	हैक्टेयर	आर०	सेन्टीयर
कसकपुरा	483	0	05	64
	478	0	08	16
	475	0	22	56
	476	0	12	12
	कार्ट ट्रेक	0	02	04
	432	0	06	72
	कार्ट ट्रेक	0	02	04
	632	0	00	84
	634	0	10	20
	645	0	09	12
	645	0	08	16
	651	0	09	96

[सं ओ -12016/109/86-ओ एनजीडी-4]

S.O. 3726.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum & Natural Gas S.O. 2767 dated 23-7-86 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline.

And whereas the Competent Authority has under Sub-Section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report decided to acquire the right of of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of the section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Oil & Natural Gas Commission free from encumbrances.

SCHEDULE

PIPELINE FROM SNCI-SNCS -SNCB TO SNAK

State : Gujarat District & Taluka : Mehsana

Village	Block No.	Hectare	Are	Centiare
1	2	3	4	5
Kasalpura	483	0	05	64
	478	0	08	16
	475	0	22	56
	476	0	12	12
	Cart Track	0	02	04
	432	0	06	72
	Cart Track	0	02	04
	632	0	00	84
	634	0	10	20
	645	0	09	12
	645	0	08	16
	651	0	09	96

[No. O-12016/109/86-ONGD-4]

का०आ० 3727—यतः पैट्रोलियम और खनिज पाइपलाईन भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन अधिनियम 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना का०आ०सं० 1827 तारीख 26-5-86 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनों को बिछाने के लिये अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे, यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाईन बिछाने के लिये एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने की बजाय तेल और प्राकृतिक गैस आयोग में, सभी बाधाओं से मुक्त रूप में, घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

अनुसूची

जे०आर०एन० से झालोरा -22 तक पाइप लाईन बिछाने के लिये।

राज्य : गुजरात जिला : मेहसाना तालुका : कड़ी

गांव	सर्वे नं	हैक्टेयर	आर	सैन्टीयर
मानीपुर	184	0	06	30
	183	0	08	70
	182	0	12	75

[सं० ओ-12016/31/84-ओ एन जी डी -4]

S.O. 3727.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum & Natural Gas S.O. 1827 dated 26-5-84 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline.

And whereas the Competent Authority has under Sub-Section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of the section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Oil & Natural Gas Commission free from encumbrances.

SCHEDULE

Pipeline From JRN To Jhalora-22

State : Gujarat District : Mehsana Taluka : Kadi

Village	Survey No.	Hectare	Are	Centiare
1	2	3	4	5
Manipur	184	0	06	30
	183	0	08	70
	182	0	12	75

[No. O-12016/31/84-ONGD-4]

का. आ. 3728—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में गंधार से पखाजन तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पाइपलाईन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए ।

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाईनों को बिछाने के प्रयोजन के लिये एतत्पाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है ।

अतः अब पट्रोलियम और खनिज पाइपलाईन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है ।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइप लाईन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग, निर्माण और देखभाल प्रभाग, मकरपुरा रोड, बडोदरा–9 को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा ।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन करेगा कि क्या वह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत ।

अनुसूची

गंधार से पखाजन तक पाइपलाईन बिछाने के लिए

राज्य : गुजरात जिला : भरूच तालुका : वागरा

गांव	ब्लोक नं.	हेक्टयर	आर.	सैंटीआर
1	2	3	4	5
केशवान	756	0	04	00
	769	0	34	40
	771	0	14	80
	772	0	09	20
	774	0	58	00
	773	0	00	20
	780	0	25	40
	778	0	28	00
	779	0	07	80
	800	0	17	00
	801	0	06	80
	802	0	18	80
	806	0	25	00
	807	0	10	20
	815	0	07	00
	1032	0	28	40
	1033	0	05	40
	1031	0	20	00
	1030	0	10	40
	866	0	00	20
	867	0	41	60
	875	0	22	40
	877	0	11	40
	878	0	22	40
	879	0	21	60
	883	0	10	60
	886	0	16	00
	844	0	29	60
	920	0	19	80
	918	0	06	00
	916	0	34	00
	917	0	14	00
	963	0	11	60
	965	0	13	60
	964	0	15	20
	971	0	34	80
	972	0	18	40
	1003	0	20	78
	973	0	00	90
	1002	0	16	60
	998	0	28	00
	989	0	04	37
	992	0	17	00
	991	0	09	00
	990	0	03	40
	993	0	00	50

[सं. O–12016/158/86-ओ एन जी डी–4]

S.O. 3728.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from Gundhar to Pakhujan in Gujarat State pipeline should be laid by the Oil & Natural Gas Commission.

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the said land to the Competent Authority, Oil & Natural Gas Commission, Construction and Maintenance Division, Makarpura Road, Vadodara-(390 009).

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be hear in person or by legal practitioner.

SCHEDULE

PIPELINE FROM GANDHAR TO PAKHAJAN

State : Gujarat District : Bharuch Taluka : Vagara

Village	Block No	Hectare	Are	Centiare
1	2	3	4	5
Keshwan	756	0	04	00
	769	0	34	40
	771	0	14	80
	772	0	09	20
	774	0	58	00
	773	0	00	20
	780	0	25	40
	778	0	28	00
	779	0	07	80
	800	0	17	00
	801	0	06	80
	802	0	18	80
	806	0	25	00
	807	0	10	20
	815	0	07	00
	1032	0	28	40
	1033	0	05	40
	1031	0	20	00
	1030	0	10	40
	866	0	00	20
	867	0	41	60
	875	0	22	40
	877	0	11	40
	878	0	22	40
	879	0	21	60
	883	0	10	60
	886	0	16	00
	844	0	29	60
	920	0	19	80
	918	0	06	00
	916	0	34	00
	917	0	14	00
	963	0	11	60
	965	0	13	60
	964	0	15	20
	971	0	34	80
	972	0	18	40
	1003	0	20	78
	973	0	00	90
	1002	0	16	60
	998	0	28	00
	989	0	04	37
	992	0	17	00
	991	0	09	00
	990	0	03	40
	993	0	00	50

[No. O-12016/158/86-ONGD-4]

का. आ. 3729:—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में कूप नं० एन-87 से नाईका कोलोनी तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पाइपलाईन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए ।

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिये एतत्पश्चात् अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है ।

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अर्जन का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है ।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग, निर्माण और देखभाल प्रभाग, मकरपुरा रोड, बडोदरा-9 को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा ।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन करेगा कि क्या वह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या कि किसी विधि व्यवसायी की मार्फत ।

अनुसूची

कूप नं. एन. 87 से इनाइका कोलोनी तक पाइप लाईन बिछाने के लिए

राज्य : गुजरात जिला: खेडा तालुका : मातर

गांव	सर्वेक्षण नं.	हे०	आर.	सें.
नाइका	1469	0	31	65
	1461/ए	0	18	75

[सं. O-12016 / 168 / 86-ओ एन जी डी-4]

S.O. 3729.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from Well No. N-87 to Naika Colony in Gujarat State pipeline should be laid by the Oil & Natural Gas Commission.

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the said land to the Competent Authority, Oil & Natural Gas Commission, Construction and Maintenance Division, Makarpura Road, Vadodara-(390 009).

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be hear in person or by legal practitioner.

SCHEDULE

PIPELINE FROM WELL NO. N-87 TO NAIKA COLONY

State : Gujarat District : Kaira Taluka : Matar

Village	Survey No.	Hectare	Are	Centiare
Naika	1469	0	31	65
	1461/A	0	18	75

[No. O-12016/168/86-ONGD-4]

शुद्धि पत्र

का. आ. 3630—भारत सरकार के राजपत्र भाग II खंड 3, उपखंड (ii) दिनांक 4 सितम्बर, 1982 पृष्ठ क्रमांक 3122 और 3123 का. आ. संख्या क्रमांक 12016/26/82 – प्रोड–II के अंतर्गत भारत सरकार पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय (पेट्रोलियम विभाग) का अधिसूचना संख्या क्रमांक 3085 दिनांक 4 सितम्बर, 1982 के अंतर्गत पेट्रोलियम और खनिज पाईप लाईन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम 1962 का धारा 3 उपधारा (1) के अधीन वर्णित गांव – 1. वाकसाई 2. वरसोली 3. लोणावला 4. वलवण तहसिल – मावल जिला – पुणे महाराष्ट्र के अंतर्गत अधिसूचना में वर्णित भूमि में खसरा नम्बर, हिस्सा नम्बर, क्षेत्रफल कालम 1 के बदले अनुसूची में खसरा नम्बर, हिस्सा नम्बर क्षेत्रफल कालम 2 में दी गई अनुसूची को पढ़े।

निम्नलिखित अनुसूची के भाग 2 में वर्णित भूमि में पाईप लाईन बिछाने का प्रयोजन अलाईनमेंट बदलने से अब न रहा है। अब अतः निम्नलिखित अनुसूची के भाग 2 में वर्णित भूमि धारा 3 के उपधारा (i) के अधिसूचना को अनुसूची से कम कर दी गई है।

अनुसूची

भाग-I

कालम 2 पढ़ें | कालम 1 के लिए

गांव	खसरा नम्बर	हिस्सा नम्बर	क्षेत्रफल	गांव	खसरा नम्बर	हिस्सा नम्बर	क्षेत्रफल
वाकसाई	132	3	00-39-45	वाकसाई	132	का भाग	00-29-00
	132	2	00-01-00				
	133	1+2	00-08-30		133	"	00-17-00
		3+4अ					
	134	1+2+3					
		4+5+6	00-12-60		134	"	00-17-00
	135	1	00-18-90		135	"	00-04-00
	139	2+3+4	00-14-60		139	"	00-31-00
	139	5	00-12-60				
	140	अ–2	00-15-85		140अ	"	00-21-00
	140	अ–1	00-15-48				
	145	1+2+3	00-50-40		145	"	00-13-00
	149 }	4 }	00-04-80		149	"	00-04-00
	160 }	4 }					
	150	1	00-00-80		150	"	00-13-00
	160	2	00-05-94		160	"	00-13-00

भाग – II

गांव	खसरा नं.	हिस्सा नं.	क्षेत्रफल
वाकसाई	141	का भाग	00-09-00
	148	"	00-11-00
	144	"	00-48-00

अनुसूची

भाग – I

कालम 2 पढ़े				कालम 1 के लिए			
गांव	खसरा नम्बर	हिस्सा नम्बर	क्षेत्रफल	गांव	खसरा नम्बर	हिस्सा नम्बर	क्षेत्रफल
वरसोली	23	1क	00-05-76	वरसोली	23	का भाग	00-37-00
	23	2	00-15-60				
	23	1अ	00-31-90				
	24	2अ					
	24	2ब	00-28-80		24	,,	00-27-00
	47	1	00-54-00		47	,,	00-59-00
	60	3	00-04-32				
	60	1	00-05-55		60	,,	00-59-00
	60	2	00-27-72				
	49	1	00-09-36		49	,,	00-40-00

भाग – II

गांव	खसरा नं.	हिस्सा नं	क्षेत्रफल
वरसोली	63	का भाग	00-04-60

अनुसूची

भाग – I

कालम 2 पढ़े						कालम 1 के लिए			
गांव	खसरा नम्बर	हिस्सा नम्बर	सीटीएस नम्बर	प्लाट नम्बर	क्षेत्रफल	गांव	खसरा नम्बर	हिस्सा नम्बर	क्षेत्रफल
लोणावला	144	—	176अ/अ	4	00-04-05	लोणावला	144अ	का भाग	00-24-00
	144	—	176-अ/4	5	00-07-38		144	,,	00-18-00
	169	1+2	169	—	00-03-42		169	,,	00-20-00
	145	—	181	9	00-01-98		145	,,	00-04-00

भाग – II

गांव	खसरा नम्बर	हिस्सा नम्बर	सीटीएस नम्बर	क्षेत्रफल
लोणावला	144	ब	176अ/4	00-05-00

अनुसूची

भाग 1

कालम II पढ़ें				कालम I के लिए			
गांव	खसरा नम्बर	हिस्सा नम्बर	क्षेत्रफल	गांव	खसरा नम्बर	हिस्सा नम्बर	क्षेत्रफल
वलवण	14	2 से 10	00-07-78	वलवण	14	का भाग	00-37-00
	33	का भाग	00-05-98		33	"	00-20-00
	34	1	00-04-41		34	"	00-11-00
	35	0	00-01-08		35	"	00-04-00
	41	अ			41अ	"	00-05-00
	41	ब	00-08-23		41ब	"	00-18-00
	189				189	"	00-16-00
	42	0	00-09-54		42	"	00-05-00
	43	3	00-13-50		43	"	00-16-00
	44	का भाग			44	"	00-13-00
	50	1	00-33-12		45	"	00-11-00
	45	1			50	"	00-20-00
	50	2					
	45	2	00-17-64				
	51	2	00-09-00		51	"	00-20-00
	52	1	00-05-40		52	"	00-16-00
	65	का भाग			65	"	00-31-00
			00-25-56				
	66	"			66	"	00-13-00
	80	1					
	80	2	00-13-50		80	"	00-13-00
	80	3					
	83	3	00-05-40		83	"	00-38-00
	83	4					
	83	6	00-07-02				
	94	1					
	94	2	00-37-08		94	"	00-18-00
	95	2	00-05-94		95	"	00-22-00

भाग –II

गांव	खसरा नम्बर	हिस्सा नम्बर	क्षेत्रफल
वलवण	38	का भाग	00-05-00
	15	"	00-04-00
	40	"	00-04-00
	70	"	00-05-00

[सं O—12016/26/82-प्रोड]

CORRIGENDUM

S.O. 3730.—In the Notification of Government of India, Ministry of Petroleum, Chemicals & Fertilizer's (Department of Petroleum) No. 12016|26|82-Prod-II dated 4th September 1982 published under S.O. No. 3085 in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-Section (ii) at page 3122 & 3123 issued under Section 3 Sub-Section (i) of the Petroleum & Minerals Pipe Lines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 in respect of villages (1) Waksai, (2) Warsoli, (3) Lonawala, (4) Walvan for S. Nos. and areas shown in the Column No. 1 of the Schedule appended to this corrigendum, read and S. Nos. and areas as shown in column No. 2 of the said schedule.

Lands mentioned in the Part II of the appended schedule, however do not come under the Pipe Line Project due to change in the alignment and therefore, they are delected from the schedule appended to the Notification under section 3 Sub Section (i) referred to above.

SCHEDULE

(Read) (Col – II) For (Col – I)

PART — I

Village	S. No. / G. No.	H. No.	Area	Village	S. No. / G. No.	H. No.	Area
Wakasai.	132	3	00-39-45	Wakasai	132	(pt)	00-29-00
	132	2	00-01-00				
	133	1 + 2					
		3 + 4B	00-08-30		133	(pt)	00-17-00
	134	1 + 2 + 3					
		4 + 5 + 6	00-12-60		134	(pt)	00-17-00
	135	1	00-18-90		135	(pt)	00-04-00
	139	2 + 3 + 4	00-14-60		139	(pt)	00-31-00
	139	5	00-12-60				
	140	A-2	00-15-85		140A	(pt)	00-21-00
	140	A-1	00-15-48				
	145	1 + 2 + 3 + 4	00-50-40		145	(pt)	00-13-00
	149	4					
	160	—4	00-04-80		149	(pt)	00-04-00
	150	1	00-00-80		150	(pt)	00-13-00
	160	2	00-05-94		160	(pt)	00-13-00

PART — II

Village	S. No. / G. No.	H. No	Area
Wakasai	141	(pt)	00-09-00
	148	(pt)	00-11-00
	144	(pt)	00-48-00

Read (Col — II) For (Col. — I)

PART — I

Village	S. No. / G. No.	H. No.	Area	Village	S. No. / G. No.	H. No.	Area
Varsoli	23	1-C	00-05-76	Varsoli	23	(pt)	00-37-00
	23	2	00-15-60				
	23	1-A	00-31-20				
	24	2A					
	24	2B	00-28-80		24	(pt)	00-27-00
	24	1					
	47	1	00-54-00		47	(pt)	00-59-00
	60	3	00-04-32				
	60	1	00-05-55		60	(pt)	00-59-00
	60	2	00-27-72				
	49	1	00-09-36		49	(pt)	00-40-00

PART — II

Village	S. No. / G. No.	H. No.	Area
Varsoli	63	(pt)	00-04-00

Read (Col. - II) For (Col - I)

PART - I

Village	S. No.	H. No.	CTS No.	Plot No.	Area	Village	S. No. G.No.	H. No.	Area
Lonavala.	144	A	176A/3	4	00-04-05	Lonavala.	144A	(pt)	00-24-00
	144	—	176A/4	5	00-07-38		144	(pt)	00-18-00
	169	1+2	169	—	00-03-42		169	(pt)	00-20-00
	145	—	181	9	00-01-98		145	(pt)	00-04-00

PART—II

Village	S. No.	H. No.	CTS. No.	Area
Lonavala.	144	B	176A-6/4	00-05-00

(Read (Col - II) For (Col - I)

PART — I

Village	S. No. G. No.	H. No.	Area	Village	S. No. G. No.	H. No.	Area
Walvan.	14	2 to 10	00-07-78	Walvan.	14	(pt)	00-37-00
	33	(pt)	00-05-78		33	(pt)	00-20-00
	34	1	00-04-41		34	(pt)	00-11-00
	35	0	00-01-08		35	(pt)	00-04-00
	41	A	00-08-23		41A	(pt)	00-05-00
	41	B			41B	(pt)	00-18-00
	189				189	(pt)	00-16-00
	42	0	00-09-54		42	(pt)	00-05-00
	43	3	00-13-50		43	(pt)	00-16-00
	44	(pt)			44	(pt)	00-13-00
	50	1	00-33-12		45	(pt)	00-11-00
	45	1			50	(pt)	00-20-00
	50	2	00-17-64				
	45	2					
	51	2	00-09-00		51	(pt)	00-20-00
	52	1	00-05-40		52	(pt)	00-16-00
	65	(pt)	00-25-56		65	(pt)	00-31-00
	66	(pt)			66	(pt)	00-13-00
	80	1					
	80	2	00-13-50		80	(pt)	00-13-00
	80	3					
	83	3					
	83	4	00-05-40		83	(pt)	00-38-00
	83	6	00-07-02				
	94	1					
	94	2	00-37-08		94	(pt)	00-18-00
	95	2	00-05-94		95	(pt)	00-22-00

PART — II

Village	S. No.	H. No.	Area
Walvan.	38	(pt)	00-05-00
	15	(pt)	00-04-00
	40	(pt)	00-04-00
	70	(pt)	00-05-00

[No. O 12016/26/82-Prod.]

शुद्धि-पत्र

का आ 3731.—भारत सरकार के राजपत्र भाग II, खण्ड 3, उपखण्ड (ii) दिनांक 5 फरवरी 1983 पृष्ठ क्रमांक 673, 674 और 675 का० आ० संख्या क्रमांक O-12016/26/82-प्रोड-II के अंतर्गत भारत सरकार, ऊर्जा मंत्रालय (पेट्रोलियम विभाग) की अधिसूचना संख्या क्रमांक 777 दिनांक 5 फरवरी 1983 के अंतर्गत पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 की धारा 6 उपधारा (1) के अधीन वर्णित, गांव—1. वाकसई, 2. वरसोली, 3. लोनावला, 4. वलवण, तहसिल—मावल, जिला—पुणे, महाराष्ट्र के अंतर्गत अधिसूचना में वर्णित भूमी में खसरा नम्बर, हिस्सा नम्बर, क्षेत्रफल कॉलम 1 के बदले अनुसूची में खसरा नम्बर, हिस्सा नम्बर, क्षेत्रफल कॉलम 2 में दी गई अनसूची को पढ़े ।

निम्नलिखित अनुसूची के भाग 2 में वर्णित भूमी में पाइप लाइन बिछाने का प्रयोजन अलाईनमेंट बदलने से अब न रहा है। अब अतः निम्नलिखित अनुसूची के भाग 2 में वर्णित भूमी धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना को अनुसूची से हटा दिया गया है ।

अनुसूची

भाग— I

कॉलम 2 पढ़ें				कॉलम 1 के लिए			
गांव	खसरा नम्बर	हिस्सा नम्बर	क्षेत्रफल	गांव	खसरा नम्बर	हिस्सा नम्बर	क्षेत्रफल
वाकसाई	132	3	00-39-45	वाकसाई	132	का भाग	00-29-00
	132	2	00-01-00				
	133	1+2 3+4अ	00-08-30		133	,,	00-17-00
	134	1+2+3 4+5+6	00-12-60		134	,,	00-17-00
	135	1	00-18-90		135	,,	00-04-00
	139	2+3+4	00-14-60		139	,,	00-31-00
	139	5	00-12-60				
	140	अ-2	00-15-85		140अ	,,	00-21-00
	140	अ-1	00-15-48			,,	00-48-00
	145	1+2+3+4	00-50-40		145	,,	00-13-00
	148				148	,,	00-11-00
	149	4	00-04-80		149	,,	00-04-00
	160	4					
	150	1	00-00-80		150	,,	00-13-00
	160	2	00-05-94		160	,,	00-13-00

भाग-II

गांव	खसरा नं	हिस्सा नं	क्षेत्रफल
वाकसाई	141	का भाग	00-09-00
	148	,,	00-11-00
	144	,,	00-48-00

अनुसूची

भाग—I

कॉलम II पढ़ें | कॉलम I के लिए

गांव	खसरा नम्बर	हिस्सा नम्बर	क्षेत्रफल	गांव	खसरा नम्बर	हिस्सा नम्बर	क्षेत्रफल
वरसोली	23	1क	00-05-26	वरसोली	23	का भाग	00-37-00
	23	2	00-15-60				
	23	1अ	00-31-90				
	24	2अ					
	24	2ब	00-28-80		24	,,	00-27-00
	24	1					
	47	1	00-54-00		47	,,	00-59-00
	60	3	00-04-32				
	60	1	00-05-55		60	,,	00-59-00
	60	2	00-27-72				
	49	1	00-09-36		49	,,	00-40-00

भाग—II

गांव	खसरा नं	हिस्सा नं	क्षेत्रफल
वरसोली	63	का भाग	00-04-60

अनुसूची

भाग—I

कॉलम II पढ़ें | कॉलम I के लिए

गांव	खसरा नम्बर	हिस्सा नम्बर	सी टी एम नम्बर	प्लाट नम्बर	क्षेत्रफल	गांव	खसरा नम्बर	हिस्सा नम्बर	क्षेत्रफल
लोणावला	144	—	176अ	4	00-04-05	लोणावला	144अ	का भाग	00-24-00
	144	—	3 / 176-अ / 4	5	00-07-38		144	,,	00-18-00
	169	1+2	169	—	00-03-42		169	,,	00-20-00
	143	—	181	9	00-01-98		145	,,	00-04-00

भाग—II

गांव	खसारा नम्बर	हिस्सा नम्बर	क्षेत्रफल
लोणावला	144	—	00-05-00

अनुसूची

भाग—I

कॉलम II पढ़ें				कॉलम I के लिए			
गांव	खसारा नम्बर	हिस्सा नम्बर	क्षेत्रफल	गांव	खसरा नम्बर	हिस्सा नम्बर	क्षेत्रफल
वलवण	14	2 से 10	00—07—78	वलवण	14	का भाग	00—37—00
	33	का भाग	00—05—98		33	,,	00—20—00
	34	1	00—04—41		34	,,	00—11—00
	35	0	00—01—08		35	,,	00—04—00
	41	अ			41 अ	,,	00—05—00
	41	ब	00—08—23		41 ब	,,	00—18—00
	189				189	,,	00—16—00
	42	0	00—09—54		42	,,	00—05—00
	43	3	00—13—50		43	,,	00—16—00
	44	का भाग			44	,,	00—13—00
	50	1	00—33—12		45	,,	00—11—00
	45	1			50	,,	00—20—00
	50	2	00—17—64				
	45	2					
	51	2	50—09—00		51	,,	00—20—00
	52	1	00—05—40		52	,,	50—16—00
	65	का भाग	00—25—56		65	,,	00—31—00
	66	,,			66	,,	00—13—00
	80	1					
	80	2	00—13—50		80	,,	00—13—00
	80	3					
	83	3	00—05—40		83	,,	00—38—00
	83	4					
	83	6	00—07—02				
	94	1	00—37—08		94	,,	00—18—00
	94	2					
	95	2	00—05—94		95	,,	00—22—00

भाग—II

गांव	खसरा नम्बर	हिस्सा नम्बर	क्षेत्रफल
वलवण	38	का भाग	00—05—00
	15	,,	00—04—00
	40	,,	00—04—00
	70	,,	00—05—00

[सं O—12016/26/82-प्रोड -I]

पी के राजगोपालन, डैस्क अधिकारी

CORRIGENDUM

S.O. 3731.—In the Notification of Government of India, Ministry of Energy (Department of Petroleum) No. O-12016/26/82-Prod-II dated 5-2-1983 published under S.O. No. 777 in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-Section (ii) at page 673, 674 & 675 issued under Section 6 Sub-Section (i) of the Petroleum & Minerals Pipe Lines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 in respect of villages 1. Waksai 2. Warsoli 3. Lonawala 4. Walvan for S. Nos. and areas shown in the Column No. 1 of the Schedule appended to this corrigendum, read S. Nos. and areas as shown in column No. 2 of the said Schedule.

Lands mentioned in the Part II of the appended schedule, however do not come under the Pipe Line Project due to change in the alignment and therefore the are deleted from the schedule appended to the Notification under section 6 Sub Section (i) referred to above.

PART—I

Read (Col-II)				For (Col-I)			
Village	S. No. / G. No.	H. NO.	Area	Village	S. No. / G. No.	H. No.	Area
1	2	3	4	5	6	7	8
Waksai	132	3	00-39-45	Waksai	132	(pt)	00-29-00
	132	2	00-01-00				
	133	1+2+3+4B	00-08-30		133	(pt)	00-17-00
	134	1+2+3+4+5+6	00-12-60		134	(pt)	00-17-00
	135	1	00-18-90		135	(pt)	00-04-00
	139	2+3+4	00-14-60		139	(pt)	00-31-00
	139	5	00-12-60				
	140	A-2	00-15-85		140A	(pt)	00-21-00
	140	A-1	00-15-48				
	145	1+2+3+4	00-50-40		145	(pt)	00-13-00
	149	4	00-04-80		149	(pt)	00-04-00
	160	4					
	150	1	00-00-80		150	(pt)	00-13-00
	160	2	00-05-94		160	(pt)	00-13-00

PART—II

Village	S. No.	H. No.	Area
Waksai	141	(pt)	00-09-00
	148	(pt)	00-11-00
	144	(pt)	00-48-00

PART- I

Read (Col-II)				(For Col-I)			
Village	S. No. / G. No.	H. No.	Area	Village	S. No. / G. No.	H. No.	Area
1	2	3	4	5	6	7	8
Varsoli	23	1-C	00-05-76	Varsoli			
	23	2	00-15-60		23	(pt)	00-37-00
	23	1-A	00-31-20				
	24	2A	00-28-80		24	(pt)	00-27-00
	24	2B					
	24	1					
	47	1	00-54-00		47	(pt)	00-59-00
	60	3	00-04-32				
	60	1	00-05-55		60	(pt)	00-59-00
	60	2	00-27-72				
	49	1	00-09-36		49	(pt)	00-40-00

PART—II

Village	S. No.	H. No.	Area
Varsoli	63	(pt)	00-04-00

PART—I

Read (Col-II)						For (Col-I)			
Village	S. No. / G. No.	H.No.	CTNo.	Plot No.	Area	Village	S. No. / G. No.	H. No.	Area
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Lonavala	144	—A	176A/3	4	00-01-05	Lonavala	144A	(pt)	00-24-00
	144	—	176A/4	5	00-07-38		144	(pt)	00-18-00
	169	1+2	169	—	00-03-42		169	(pt)	00-20-00
	145	—	181	9	00-01-98		145	(pt)	00-04-00

PART—II

Village	S. No.	H. No.	CTS No.	Plot	Area
Lonavala	144	B	176A-6/4		00-05-00

PART—I

Read (Col-II)					For (Col-I)		
Village	S. No. / G. No.	H. No.	Area	Village	S. No. / G. No.	H. No.	Area
1	2	3	4	5	6	7	8
Walvan	14	2 to 10	00-07-78	Walvan	14	(pt)	00-37-00
	33	(pt)	00-05-98		33	(pt)	00-20-00
	34	1	00-04-41		34	(pt)	00-11-00
	35	0	00-01-08		35	(pt)	00-04-00
	41	A	00-08-23		41-A	(pt)	00-05-00
	41	B			41-B	(pt)	00-18-00
	189				189	(pt)	00-16-00
	42	0	00-09-54		42	(pt)	00-05-00
	43	3	00-13-50		43	(pt)	00-16-00
	44	(pt)	00-33-12		44	(pt)	00-13-00
	50	1					
	45	1					
	50	2	00-17-64		45	(pt)	00-11-00
	45	2			50	(pt)	00-20-00
	51	2	00-09-00		51	(pt)	00-20-00
	52	1	00-05-40		52	(pt)	00-16-00
	65	(pt)	00-25-56		65	(pt)	00-31-00
	66	(pt)			66	(pt)	00-13-00
	80	1	00-13-50		80	(pt)	00-13-00
	80	2					
	80	3					
	83	3	00-05-40		83	(pt)	00-38-00
	83	4					
	83	6	00-07-02				
	94	1	00-37-08		94	(pt)	00-18-00
	94	2					
	95	2	00-05-94		95	(pt)	00-22-00

PART—II

Village	S. No. / G. No.	H. No.	Area
Walvan	38	(pt)	00-05-00
	15	(pt)	00-04-00
	40	(pt)	00-04-00
	70	(pt)	00-05-00

[No. O-12016/26/82-Prcd.I]
P.K. RAJAGOPALAN, Desk Officer

नई दिल्ली, 17 अक्तूबर, 1986

का आ 3732.—तेल उद्योग (विकास) अधिनियम, 1974 (1974 का 47) के खण्ड 3 के उप-खण्ड (3) की धारा (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक आयल इंडिया लिमिटेड को दो वर्षों तक के लिए तेल उद्योग में कार्यरत निगमों का प्रतिनिधित्व करने के लिए तेल उद्योग विकास बोर्ड के सदस्य के रूप में पुन: नियुक्त करती है ।

[संख्या-7/9/85-वित्त II]

एम कुमारस्वामी, निदेशक

New Delhi, the 17th October, 1986

S.O. 3732.—In exercise of the powers conferred by clause (c) of sub-section (3) of section 3 of the Oil Industry (Development) Act, 1947 (47 of 1947), the Central Government hereby reappoints, with immediate effect and for a period not exceeding two years, Maj. Gen. S. C. N. Jatar, Chairman and Managing Director Oil Inda Limited, as a member of the Oil Industry Development Board to the represent corporation engaged in oil industry.

[No. 7|9|85-Fin. II]

M. KUMARASWAMI, Director

नई दिल्ली, 20 अक्तूबर, 1986

का० आ० 3733:—यत: केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में झालोरा-22 से जी० जी० एस० झालोरा-I तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइप लाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए ।

और यत: यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्पाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है;

अत: अब पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है ।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग, निर्माण और देखभाल प्रभाग मकरपुरा रोड, बडोदरा-9 को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा ।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टत: यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत ।

अनुसूची

झालोरा-22 से जी० जी० एस० झालोरा-1 तक पाइप लाइन बिछाने के लिए

राज्य : गुजरात जिला : मेहसाना तालुका : कड़ी

गांव	सर्वे नं	हेक्टयर	आरे	सेन्टीयर
मनीपुर	173	0	15	00

[सं. O-12016/170/86 - ओ एन जी डी- 4]

New Delhi, the 20th October, 1986

S.O. 3733.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from Jhalora-22 to G.G.S. Jhalora-I in Gujarat State pipeline should be laid by the Oil & Natural Gas Commission.

And whereas, it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the said land to the Competent Authority, Oil & Natural Gas Commission, Construction & Maintenance Division, Makarpura Road, Vadodara, (390009).

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be hear in person or by legal practitioner.

SCHEDULE

Pipeline From Jhalora-22 TO GGS Jhalora-I

State : Gujarat District : Mehsana

Taluka : Kadi

Village	Survey No.	Hectare	Are	Contitire
Manipur	173	0	15	00

[No. O-12016/170/86-ONG D-4]

का० आ० 3734:—यत: केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में अहमदाबाद-12 से अहमदाबाद-18 तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइपलाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए ।

और यत: यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लए एतद्पावद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है ।

अत: अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962

का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग निर्माण और देखभाल प्रभाग, मकरपुरा रोड, बड़ोदरा-9 को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत।

अनुसूची

अहमदाबाद—12 से अहमदाबाद—18 तक पाइप लाइन बिछाने के लिए

राज्य : गुजरात जिला : अहमदाबाद तालुका : दसक्राई

गांव	सर्वे नं	हेक्टेयर	आर	सेन्टीयर
वसत्राल	808	0	04	50
	807	0	01	80
	804	0	10	50
	775	0	16	80
	774	0	11	10
	759	0	13	65
	753	0	10	05
	752	0	07	05

[सं O-12016/169/86-ओ एन जी-डी4]

S.O. 3734.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from Ahmedabad-12 to Ahmedabad-18 in Gujarat State pipeline should be laid by the Oil & Natural Gas Commission.

And whereas, it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the said land to the Competent Authority, Oil & Natural Gas Commission, Construction & Maintenance Division, Makarpura Road, Vadodara, (390009).

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be hear in person or by legal practitioner.

SCHEDULE

Pipeline from Ahmedabad-12 to Ahmedabad-18

State : Gujarat District : Ahemedabad Taluka : Dascroi

Village	Survey No	Hecta-are	Are	Centi-are
Vastral	808	0	04	50
	807	0	01	80
	804	0	10	50
	775	0	16	80
	774	0	11	10
	759	0	13	65
	753	0	13	05
	752	0	07	05

[No. O—12016/169/86-ONGD-4]

का०आ० 3735.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में कूप नं एन – 87 से नाइका कालोनी तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइप लाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए।

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए एतदुपाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग, निर्माण और देखभाल प्रभाग मकरपुरा रोड, बडोदरा—9 को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत।

अनुसूची

कूप नं एन – 87 से नाइका कालोनी तक पाइप लाइन बिछाने के लिए

राज्य : गुजरात जिला : खेड़ा तालुका : मातर

गांव	सर्वे नं	हेक्टयर	आरे	सेन्टीयर
1	2	3	4	5
चलिद्रा	13	0	04	50
	14	0	03	00
	11	0	13	00

1	2	3	4	5
चलिद्रा	9	0	13	50
	8/1	0	04	50
	8/2	0	07	50
	8/4	0	05	25
	8/6	0	06	00
	8/8	0	01	25
	8/9	0	03	50
	8/11	0	03	00
	214/1	0	01	00
	214/2	0	01	25
	214/3	0	01	50
	215/1	0	01	50
	215/2	0	01	50
	215/3	0	01	50
	215/4	0	02	50
	213	0	10	50
	209	0	09	00
	206/1	0	01	00
	206/2	0	04	00
	184/1	0	06	00
	186/6	0	01	00
	187/3	0	01	50
	193/1	0	06	50
	194/1	0	01	00
	192/1	0	06	00
	190/	0	06	00
	173/1	0	09	00
	174	0	12	00
	132/1	0	06	00
	132/2	0	03	00
	129/1	0	10	00
	129/2	0	02	50
	142/3	0	05	00
	142/4	0	08	00

[सं० O-12016/171/86-ओ एम जी-डी 4]

S.O. 3735.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from Well No. N-87 to Naika Colony in Gujarat State pipeline should be laid by the Oil & Natural Gas Commission.

And whereas, it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the said land to the Competent Authority, Oil & Natural Gas Commission, Construction & Maintenance Division, Makarpura Road, Vadodara, (390009).

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be hear in person or by legal practitioner.

SCHEDULE

Pipeline from Well No. N 87 to Naika Colony

State : Gujarat District : Kaira Taluka : Matar

Village	Survey No.	Hectare	Are	Centiare
1	2	3	4	5
Chalindra	13	0	04	50
	14	0	03	00
	11	0	13	00
	9	0	13	50
	8/1	0	04	50
	8/2	0	07	50
	8/4	0	05	25
	8/6	0	06	00
	8/8	0	01	25
	8/9	0	03	50
	8/11	0	03	00
	214/1	0	01	00
	214/2	0	01	50
	214/3	0	01	50
	215/1	0	01	25
	215/2	0	01	50
	215/3	0	01	50
	215/4	0	02	50
	213	0	10	50
	209	0	09	00
	206/1	0	01	00
	206/2	0	04	00
	184/1	0	06	00
	186/6	0	01	00
	187/3	0	01	50
	193	0	06	50
	194/1	0	01	00
	192/1	0	06	00
	190/1	0	06	00
	173/1	0	09	00
	174	0	12	00
	132/1	0	06	00
	132/2	0	03	00
	129/1	0	10	00
	129/2	0	02	50
	142/3	0	05	00
	142/4	0	08	00

[No. O—12016/171/86-ONG-D4]

का. आ. 3736—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में एस एम बी आर (एस 93) से एस एम बी पी (पुरानी लाइन एस एम आई) से एस एस सी टी एफ तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइपलाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए।

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्पाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग, निर्माण और देखभाल प्रभाग, मकरपुरा रोड, बडोदरा-9 को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत।

अनुसूची

एस एन बी आर (एस –93) एस एन बी पी (पुरानी लाइन एस एन आई) से एस एस सी टी एफ तक पाइप लाइन बिछाने के लिए।

राज्य : गुजरात जिला : मेहसाना तालुका : मेहसाना

गांव	सर्वे नं.	हेक्टेयर	आरे.	सेन्टीयर
जुटाना	1244	00	03	00
	1245	00	09	36
	1246	00	14	64
	1349	00	05	64
	1351	00	11	16
	1352	00	03	60

[सं. O–12010/172/86–ओ एन जी–डी4]

S.O. 3736.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from SNBR (S. 93) to SNBP (old line SNI) to S.S.C.T.F in Gujarat State pipeline should be laid by the Oil & Natural Gas Commission.

And whereas, it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the said land to the Competent Authority, Oil & Natural Gas Commission, Construction & Maintenance Division, Makarpura Road, Vadodara, (390009).

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be hear in person or by legal practitioner.

SCHEDULE

Pipe Line from ROU for SNBR (S-93) to SNBP (Old Line SNI to SS CTF)

State : Gujarat District : Mehsana Taluka : Mehsana

Village	Survey No.	Hectare	Are	Centiare
Jotana	1244	00	03	00
	1245	00	09	36
	1246	00	14	64
	1349	00	05	64
	1351	00	11	16
	1352	00	03	60

[No. O 12016/172/86-ONG-D4]

का. आ. 3737—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में जी जी एस 11 से जी जी एस – 1 तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइपलाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए।

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्पाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा, प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग, निर्माण और देखभाल प्रभाग, मकरपुरा रोड, बडोदरा-9 को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत।

अनुसूची

जी. जी. एस. 11 से जी. जी. एस. 1 तक पाइप लाइन बिछाने के लिए

राज्य : गुजरात जिला व तालुका : गांधीनगर

गांव	ब्लाक नं	हेक्टेयर	आरे.	सेन्टीयर
तारापुर	134	0	09	60
	144	0	10	40
	143	0	15	80
	144	0	10	60
	145	0	09	60
	204	0	07	80

1	2	3	4	5
तारापुर	205	0	24	00
	206	0	16	40
	208	0	14	60
	कार्ट ट्रेक	0	02	40

[सं. O – 12016/173/86 – ओ एन जी – डी 4]

S.O. 3737.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from G.G.S. XI to G.G.S. I, in Gujarat State pipeline should be laid by the Oil & Natural Gas Commission.

And whereas, it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the said land to the Competent Authority, Oil & Natural Gas Commission, Construction & Maintenance Division, Makarpura Road, Vadodara, (390009).

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be hear in person or by legal practitioner.

SCHEDULE

Pipe line from GGS XI to GGS I.

State : Gujarat District & Taluka : Gandhinagar

Village	Block No.	Hect-are	Are	Conti-are
Tarapur	131	0	09	60
	144	0	10	40
	143	0	15	80
	144	0	10	60
	145	0	09	60
	204	0	07	80
	205	0	24	00
	206	0	16	40
	208	0	14	60
	Cart track	0	02	40

[No. O—12016/173/86-ONG-D4]

का. आ. 3738.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में जी. जी. एस – XI से जी. जी. एस. I तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइपलाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए।

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्पाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी तेल तथा तथा प्राकृतिक गैस आयोग, निर्माण और देखभाल प्रभाग मकरपुरा रोड, बडोदरा-9 को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत।

अनुसूची

जी जी एस XI से जी जी एस I तक पाइप लाइन बिछाने के लिए।

राज्य : गुजरात जिला व तालुका : गांधीनगर

गांव	ब्लाक नं	हेक्टेयर	आरे.	सेन्टीयर
उवारसद	941	0	03	70
	944	0	29	40
	943	0	02	20
	945	0	22	80
	946	0	17	80
	947	0	16	00

[सं. O–12016/174/86 – ओ एन जी – डी 4]

S.O. 3738.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from G.G.S. XI to G.G.S. I in Gujarat State pipeline should be laid by the Oil & Natural Gas Commission.

And whereas, it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the said land to the Competent Authority, Oil & Natural Gas Commission, Construction & Maintenance Division, Makarpura Road, Vadodara, (390009).

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

SCHEDULE

Pipeline from GGS XI to CGS I.

State : Gujarat District & Taluka : Gandhinagar.

Village	Block No.	Hectare	Are	Centiare
Uvarsad	941	0	03	70
	944	0	29	40
	943	0	02	20
	945	0	22	80
	946	0	17	80
	947	0	16	00

[No. O—12016/174/86-ONG-D4]

का. आ. 3739—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में अहमदाबाद – 12 से अहमदाबाद 1–18 तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइपलाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए।

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्पाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग, निर्माण और देखभाल प्रभाग, मकरपुरा रोड, बडोदरा – 9 को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत।

अनुसूची

अहमदाबाद–12 से अहमदाबाद से 18 (हाजर आर. ओ यू.) तक पाइप लाइन बिछाने के लिए।

राज्य : गुजरात जिला : अहमदाबाद तालुका : धसकोई

गांव	सर्वे नं.	हेक्टेयर	आरे.	सेन्टीयर
रामोल	12	0	13	05
	15	0	18	25
	23	0	14	10
	22	0	19	95

[सं. O–12016/175/86–ओएनजी–डी4]

S.O. 3739.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from A'bad-12 to A'bad 1 to 18 in Gujarat State pipeline should be laid by the Oil & Natural Gas Commission.

And whereas, it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the said land to the Competent Authority, Oil & Natural Gas Commission, Construction & Maintenance Division, Makurpura Road, Vadodara, (390009).

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

SCHEDULE

Pipeline from Ahemedabad-12 to A 'BAD 1 to 18 (Existing ROU)

State : Gujarat District : Ahmedabad Taluka : Dascroi

Village	Survey No.	Hectare	Are	Centiare
Ramol	12	0	13	05
	15	0	17	25
	23	0	14	10
	22	0	19	95

[No. O—12016/175/86-ONG-D4]

नई दिल्ली 21 अक्तूबर, 1986

शुद्धि पत्र

का.आ. 3740:—भारत सरकार के राजपत्र भाग 2, खण्ड 3, उपखण्ड (ii) दिनांक 4 सितम्बर, 1982 पृष्ठ क्रमांक 3135 का.आ. संख्या क्रमांक 12016/32/82–ओड–II के अंतर्गत भारत सरकार, पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय (पेट्रोलियम विभाग) की अधिसूचना संख्या क्रमांक 3093 दिनांक 4 सितम्बर, 1982 के अंतर्गत पेट्रोलियम और खनिज पाईप लाईन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम 1962 की धारा 3 उपधारा (1) के अधीन वर्णित गांव—शिलाटणे, तहसील—मावल, जिला—पुणे महाराष्ट्र के अंतर्गत अधिसूचना में वर्णित भूमि में खसरा नम्बर, हिस्सा नम्बर, क्षेत्रफल कॉलम 1 के बदले अनुसूची में खसरा नम्बर, हिस्सा नम्बर, क्षेत्रफल कॉलम 2 में दी गई अनुसूची को पढ़ें।

निम्नलिखित अनुसूची के भाग 2 में वर्णित भूमि में पाईप लाईन बिछाने का प्रयोजन अलाईनमेंट बदलने से अब न रहा है। अब अतः निम्नलिखित अनुसूची के भाग 2 में वर्णित भूमि धारा के 3 उपधारा (1) के अधिसूचना को अनुसूची से कम कर दी गई है।

अनुसूची

भाग—1

कॉलम 2 पढ़ें।				कॉलम 1 के लिए			
गांव	खसरा नम्बर	हिस्सा नम्बर	क्षेत्रफल	गांव	खसरा नम्बर	हिस्सा नम्बर	क्षेत्रफल
शिलाटणे	4	का भाग	00-27-00	शिलाटणे	4	का भाग	00-14-00
	5	"	00-18-00		5	"	00-19-00
	6	"	00-09-00		6	"	00-26-00
	7	"	00-16-20		7	"	00-15-00
	8	"	00-30-60		8	"	00-01-00
	10	"	00-27-00		10	"	00-03-00
	165	"	00-06-48		165	"	00-18-00
	187	"	00-17-28		187	"	00-18-00
	188	"	00-09-72		188	"	00-12-00
	189	"	00-09-72		189	"	00-09-00
	190	"	00-09-90		190	"	00-12-00
	192	"	00-09-54		192	"	00-09-00
	193	"	00-10-80		193	"	00-04-00
	195	"	00-10-08		195	"	00-21-00
	195 197	"	00-40-32		197	"	00-05-00
	198	"	00-14-94		198	"	00-17-00
	200	"	00-10-80		200	"	00-07-00
	201	"	00-15-14		201	"	00-16-00
	215	"	00-14-76		215	"	00-13-00
	216	"	00-05-40		216	"	00-04-00
	219	"	00-11-88		219	"	00-24-00

भाग—2

गांव	खसरा नं.	हिस्सा नं.	क्षेत्रफल
शिलाटणे	199	का भाग	00-01-00
	200	"	00-01-00

[सं. O-12016/32/82-प्रोड]

New Delhi, the 21st October, 1986

CORRIGENDA

S.O. 3740.—In the Notification of Government of India, Ministry of Petroleum, Chemicals & Fertilizer's (Department of Petroleum) No. 12016|32|82-Prod-II dated-14th September 1982 published under S.O. No. 3093 in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-Section (ii) at page 3135 issued under Section 3 Sub-Section (i) of the Petroleum & Minerals pipe Lines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 in respect of village Shilatane for S. Nos. and areas shown in the Column No. 1 of the Schedule appended to this corrigendum, read and S. Nos. and areas as shown in column No. 2 of the said schedule.

Lands mentioned in the Part II of the appended schedule, however do not come under the Pipe Line Project due to change in the alignment and therefore, they are deleted from the schedule appended to the Notification under section 3 Sub-Section (i) referred to above.

SCHEDULE

Read (Col-II)				For (Col-I)			
PART-I							
Village	S. No. / G. No.	H. No.	Area	Village	S. No. / G. No	H. No	Area
Shilatan	4	(pt)	00-27-00	Shilatane	(pt)	(pt)	00-14-00
	5	(pt)	00-18-00		5	(pt)	00-19-00
	6	(pt)	00-09-00		6	(pt)	00-26-00
	7	(pt)	00-16-20		7	(pt)	00-15-00
	8	(pt)	00-30-60		8	(pt)	00-01-00
	10	(pt)	00-27-00		10	(pt)	00-03-00
	165	(pt)	00-06-48		165	(pt)	00-18-00
	187	(pt)	00-17-28		187	(pt)	00-18-00
	188	(pt)	00-09-72		188	(pt)	00-12-00
	189	(pt)	00-09-72		189	(pt)	00-09-00
	190	(pt)	00-09-90		190	(pt)	00-12-00
	192	(pt)	00-09-54		192	(pt)	00-09-00
	193	(pt)	00-10-80		193	(pt)	00-04-00
	195	(pt)	00-10-08		195	(pt)	08-21-00
	195 197		00-40-32		197	(pt)	00-05-00
	198	(pt)	00-14-94		198	(pt)	00-17-00
	200	(pt)	00-10-80		200	(pt)	00-07-00
	201	(pt)	00-15-14		201	(pt)	00-16-00
	215	(pt)	00-14-76		215	(pt)	00-13-00
	216	(pt)	00-05-00		216	(pt)	00-04-00
	219	(pt)	00-11-88		219	(pt)	00-24-00

PART - II

Village	S. No.	H. No.	Area
Shilatane	199	(pt)	00-01-00
	205	(pt)	00-01-00

[No. O-12016/32/82-Prod.]

का.आ. 3741:—भारत सरकार के राजपत्र भाग 2, खण्ड 3, उपखण्ड (ii) दिनांक 4 सितम्बर, 1982 पृष्ठ क्रमांक 3134 और 3135 का.आ. संख्या क्रमांक 12016/32/82 प्रोड-I के अंतर्गत भारत सरकार, पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय (पेट्रोलियम विभाग) की अधिसूचना संख्या क्रमांक 3092 दिनांक 4 सितम्बर, 1982 के अंतर्गत पेट्रोलियम और खनिज पाईप लाईन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम 1962 की धारा 3 उपधारा (1) के अधीन वर्णित गांव-1, मुंढावरे 2. बलक 3. वडिवरे 4. नायगांव तहसील—मावल जिला—पुणे महाराष्ट्र के अंतर्गत अधिसूचना में वर्णित भूमि में खसरा, नम्बर हिस्सा नम्बर, क्षेत्रफल कॉलम 1 के बदले अनुसूची में खसरा नम्बर, हिस्सा नम्बर, क्षेत्रफल कॉलम 2 में दी गई अनुसूची को पढ़ें।

निम्नलिखित अनुसूची के भाग 2 में वर्णित भूमि में पाईप लाईन बिछाने का प्रयोजन अलाईनमेंट बदलने से अब न रहा है। अब अतः निम्नलिखित अनुसूची के भाग 2 में वर्णित भूमि, धारा 3 के उपधारा (1) के अधिसूचना को अनुसूची से कम कर दी गई है।

अनुसूची

भाग—1

कालम 2 पढ़ें — कॉलम 1 के लिए

गांव	खसरा नम्बर	हिस्सा नम्बर	क्षेत्रफल	गांव	खसरा नम्बर	हिस्सा नम्बर	क्षेत्रफल
मुंढावरे	77	का भाग	00-45-00	मुंढावरे	77	का भाग	00-45-00
	91	1	00-10-80		91	"	00-21-00
	96	4	00-21-60		96	"	00-11-00
	102	2	00-02-88				
	102	3	00-06-30		102	"	00-22-00
	102	4	00-07-20				
	101	2-2	00-05-40				
					101	"	00-28-00
	101	2-1	00-07-38				
	101	1	00-15-30				
	110	का भाग	00-05-76		110	"	00-26-00
	111	1	00-05-40		111	"	00-08-00
	112	2	00-36-00		112	"	00-33-00
	113	4	00-13-50				
	113	2	00-05-04		113	"	00-27-00
	96	2					
	113	3	00-01-35				
	114	का भाग	00-06-12		114	"	00-01-00
	80	"	00-10-80		80	"	00-14-00
	85	9	00-10-80				
	85	7	00-08-10		85	"	00-49-00
	85	5	00-04-05				
	85	11	00-08-10				

भाग—2

गांव	खसरा नं.	हिस्सा नं.	क्षेत्रफल
मुंढावरे		का भाग	
	93	"	00-13-00
	94	"	00-01-00
	125	"	00-01-00

अनुसूची

भाग–I

कालम 2 पढ़ें — कॉलम 1 के लिए

गांव	खसरा नम्बर	हिस्सा नम्बर	क्षेत्रफल	गांव	खसरा नम्बर	हिस्सा नम्बर	क्षेत्रफल
वडिवले	10	1	00-03-60	वडघिसे	10	का भाग	00-23-00
	10	2	00-03-60				
	10	3	00-03-96				
	10	4	00-03-60				
	10	6	00-21-60				
	15	1 + 2 + 3	00-18-72		15	"	00-20-00
	17	का भाग	00-23-94		17	"	00-23-00
	18	4	00-03-60		18	"	00-03-00
	23	2	00-01-80		23	"	00-03-00
	24	4	00-29-52		24	"	00-21-00
	25	4	00-15-30		25	"	00-37-00
	25	1 + 2 + 3	00-06-84				
	28	4	00-26-46		28	"	00-19-00
	28	2	00-17-10				

भाग–II

गांव	खसरा नं.	हिस्सा नं.	क्षेत्रफल
वडिवले	16	का भाग	00-16-00
	27	"	00-05-00

अनुसूची

भाग–I

कॉलम 2 पढ़ें — कॉलम 1 के लिए

गांव	खसरा नम्बर	हिस्सा नम्बर	क्षेत्रफल	गांव	खसरा नम्बर	हिस्सा नम्बर	क्षेत्रफल
वलाख	86	का भाग	00-13-50	वलाख	86	का भाग	00-14-00
	87	"	00-10-80		87	"	00-26-00

भाग–II

कुछ नहीं

अनुसूची

भाग–I

कालम 2 पढ़ें							कालम 1 के लिए
गांव	खसरा नम्बर	जूना नम्बर	क्षेत्रफल	गांव	खसरा नम्बर	हिस्सा नम्बर	क्षेत्रफल
मायगांव	273	86	00-49-14	मायगांव	86	का भाग	00-54-00
	282	86	00-11-52				
	323	86	00-10-80				
	281	87	00-06-48				
	300	87	00-03-28		87	"	00-12-00
	326	88	00-21-00		88	"	00-16-00
	325	89	00-10-08		89	"	00-26-00
	324	89	00-19-62				
	322	135	00-11-70		135	"	00-43-00
	422	135	00-10-62				
	423	136	00-16-20		136	"	00-08-00
	424	136	00-11-34				
	425	148	00-10-80		148	"	00-22-00

भाग–II

गांव	खसरा नं.	हिस्सा नं.	क्षेत्रफल
मायगांव	81	का भाग	00-06-00
	149	"	00-21-00

[सं. O–12016/32/82–प्रोड-1]

S.O. 3741.—In the Notification of Government of India, Ministry of Petroleum, Chemicals & Fertilizer's (Department of Petroleum) No. 12016/32/83-Prod-I dated the 4th September 1982, published under S.O. No. 3092 in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-Section (ii) at page 3134 & 3135 issued under Section 3 Sub-Section (i) of the Petroleum & Minerals Pipe lines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 in respect of villages (1) Murdhaware (2) Valakh (3) Wadivale (4) Naigaon, for S. Nos. and areas shown in the Column No. 1 of the Schedule appended to this corrigendum read and S. Nos. and areas as shown in column No. 2 of the said schedule.

Lands mentioned in the Part II of the appended schedule, however do not come under the Pipe Line Project due to change in the alignment and therefore, they are deleated from the schedule appended to the Notification under section 3 Sub-Section (i) referred to above.

PART–I

Read (Col–II)				For (Col–I)			
Village	S. No. G. No.	H. No.	Area	Village	S. No. G. No.	H. No.	Area
Mundhavare	77	(pt)	00–45–00		77	(pt)	00–45–00
	91	1	00–10–80		91	,,	00–21–00
	96	4	00–21–60		96	(pt)	00–11–00
	102	2	00–02–88				
	102	3	00–06–30		102	(pt)	00–22–00
	102	4	00–07–20				
	101	2–2	00–05–40				
	101	2–1	00–07–38		101	(pt)	00–28–00
	101	1	00–15–30				
	110	(pt)	00–05–76		110	(pt)	00–26–00
	111	1	00–05–40		111	(pt)	00–08–00
	112	2	00–36–00		112	(pt)	00–33–00
	113	4	00–13–50				
	113	2	00–05–04		113	(pt)	00–27–00
	96	2					
	113	3	00–01–35				
	114	(pt)	00–06–12		114	(pt)	00–01–00
	80	(pt)	00–10–80		80	(pt)	00–14–00
	85	9	00–10–80				
	85	7	00–08–10				
	85	5	00–04–05		85	(pt)	00–49–00
	85	11	00–08–10				

PART-II

Village	S. No.	H. No.	Area
Mundhavare		(pt)	
	93	(pt)	00-13-00
	94	(pt)	00-01-00
	125	(pt)	00-01-00

PART I

Read (Col-II)				For (Col-I)			
Village	S. No. G.No.	H. No.	Area	Village	S. No. G. No.	H. No.	Area
Valak	86	(pt)	00-13-50	Valak	86	(pt)	00-14-00
	87	(pt)	00-10-80		87	(pt)	00-26-00

PART-II

Nil

PART-I

Road (Col-II)					For (Col.-I)		
Village	S. No. G. No.	H. No.	Area	Village	S. No. G. No.	H. No.	Area
Wadivale	10	1	00-03-60	Wadivale	10	(pt)	00-23-00
	10	2	00-03-60				
	10	3	00-03-96				
	10	4	00-03-60				
	10	6	00-21-60				
	15	1+2+3	00-18-72		15	(pt)	00-20-00
	17	(pt)	00-23-94		17	(pt)	00-23-00
	18	4	00-03-60		18	(pt)	00-03-00
	23	2	00-01-80		23	(pt)	00-03-00
	24	4	00-29-52		24	(pt)	00-21-00
	25	4	00-15-30		25	(pt)	00-37-00
	25	1+2+3	00-06-84				
	28	4	00-26-46		28	(pt)	00-19-00
	28	2	00-17-10				

PART-II

Village	S. No.	H. No.	Area
Wadivale	16	(pt)	00-16-00
	27	(pt)	00-05-00

PART - I

Read (Col-II)					For (Col-I)		
Village	G. No. H. No.	Old S. No.	Area	Village	S. No.	H. No	Area
Naigaon	273	(86)	00-49-14	Naigaon	86	(pt)	00-54-00
	282	(86)	00-11-52				
	323	(86)	00-10-80				
	281	(87)	00-06-48		87	(pt)	00-12-00
	300	(87)	00-03-28				
	326	(88)	00-21-00		88	(pt)	00-16-00
	325	(89)	00-10-08		89	(pt)	00-26-00
	324	(89)	00-19-62				
	322	(135)	00-11-70		135	(pt)	00-43-00
	422	(135)	00-10-62				
	423	(136)	00-16-20		136	(pt)	00-08-00
	424	(136)	00-11-34				
	425	(148)	00-10-80		148	(pt)	00-22-00

PART—II

Village	S. No.	H.No.	Area
Naigaon	81	(pt)	00-06-00
	149	(pt)	00-21-00

[No. O-12016/32/82-Prod.-I]

का०आ० 3742:—भारत सरकार के राजपत्र भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) दिनांक 5 फरवरी 1983 पृष्ठ क्रमांक 681 का०आ० संख्या क्रमांक O-12016/32/82-प्रोड-II के अंतर्गत भारत सरकार उर्जा मंत्रालय (पेट्रोलियम विभाग) की अधिसूचना संख्या क्रमांक 782 दिनांक 5 फरवरी 1983 के अंतर्गत पेट्रोलियम और खनिज पाईप लाईन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम 1962 की धारा 6 उपधारा (i) के अधीन वर्णित गांव - शिलाटणे तहसील - मावल जिला - पुणे महाराष्ट्र के अंतर्गत अधिसूचना में वर्णित भूमि में खसरा नं०, हिस्सा नम्बर, क्षेत्रफल कालम 1 के बदले अनुसूची में खसरा नं० हिस्सा नं०, क्षेत्रफल कालम 2 में दी गई अनुसूची को पढ़ें ।

निम्नलिखित अनुसूची के भाग में वर्णित भूमि में पाईप लाईन बिछाने का प्रयोजन अलाईनमेंट बदलने से अब न रहा है, अब अतः निम्नलिखित अनसूची के भाग 2 में वर्णित भूमि धारा 6 उपधारा (i) के अधिसूचना को अनुसूची से कम कर दी गई है ।

अनुसूची

भाग - I

कालम II पढ़ें				कालम 1 के लिए			
गांव सं	खसरा नम्बर	हिस्सा नम्बर	क्षेत्रफल	गांव	खसरा नम्बर	हिस्सा नम्बर	क्षेत्रफल
शिलाटणे	4	का भाग	00-27-00	शिलाटणे	4	का भाग	00-14-00
	5	,,	00-18-00		5	,,	00-19-00
	6	,,	00-09-00		6	,,	00-26-00
	7	,,	00-16-20		7	,,	00-15-00
	8	,,	00-30-60		8	,,	05-01-00
	10	,,	00-27-00		10	,,	00-03-00
	165	,,	00-06-48		165	,,	00-18-00
	187	,,	00-17-28		187	,,	00-18-00
	188	,,	00-09-72		188	,,	00-12-00
	189	,,	00-09-72		189	,,	00-09-00
	190	,,	00-09-90		190	,,	00-12-00
	192	,,	00-09-54		192	,,	00-09-00
	193	,,	00-10-80		193	,,	00-04-00
	195	,,	00-10-08		195	,,	00-21-00
	195 197	,,	00-40-32		197	,,	00-05-00
	198	,,	00-14-94		198	,,	00-17-00
	200	,,	00-10-80		200	,,	00-07-00
	201	,,	00-15-14		201	,,	00-16-00
	215	,,	00-14-76		215	,,	00-13-00
	216	,,	00-05-40		216	,,	00-04-00
	219	,,	00-11-88		219	,,	00-24-00

भाग - II

गाँव	खसरा नं	हिस्सा नं	क्षेत्रफल
शिलाटणे	199	का भाग	00-01-00
	200	,,	00-01-00

[सं O-12016/32/82-प्रोड -II]

S.O. 3742.—In the Notification of Government of India, Ministry of Energy (Department of Petroleum) No. O-12016]-32|82-Prod-II dated 5-2-1983, published under S.O. No.782 in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-Section (ii) at page 681 issued under Section 6 Sub-Secton (i) of the Petroleum & Minerals Pipe Lines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 in respect of villages Shilatane for S. Nos. and areas shown in the Column No. 1 of the Schedule appended to this corrigendum, read and S Nos and areas as shown in column No. 2 of the said schedule.

Lands mentioned in the Part II of the appended schedule, however do not come under the Pipe Line Project due to change in the alignment and therefore, they are deleted from the schedule appended to the Notification under section 6 Sub-Section (I) referred to above

Read (Col-II) For (Col-I)

PART-I

Village	S. No. G.No.	H. No.	Area	Village	S.No. G.No.	H. No.	Area
Shilatane	4	(pt)	00-27-00	Shilatane	4	(pt)	00-14-00
	5	(pt)	00-18-00		5	(pt)	00-19-00
	6	(pt)	00-09-00		6	(pt)	00-26-00
	7	(pt)	00-16-20		7	(pt)	00-15-00
	8	(pt)	00-30-60		8	(pt)	00-01-00
	10	(pt)	00-27-00		10	(pt)	00-03-00
	165	(pt)	00-06-48		165	(pt)	00-18-00
	187	(pt)	00-17-28		187	(pt)	00-18-00
	188	(pt)	00-09-72		188	(pt)	00-12-00
	189	(pt)	00-09-72		189	(pt)	00-09-00
	190	(pt)	00-09-90		190	(pt)	00-12-00
	192	(pt)	00-09-54		192	(pt)	00-09-00
	193	(pt)	00-10-80		193	(pt)	00-04-00
	195	(pt)	00-10-08		195	(pt)	00-21-00
	195 197		00-40-32		197	(pt)	00-05-00
	198	(pt)	00-14-94		198	(pt)	00-17-00
	200	(pt)	00-10-80		200	(pt)	00-07-00
	201	(pt)	00-15-14		201	(pt)	00-16-00
	215	(pt)	00-14-76		215	(pt)	00-13-00
	216	(pt)	00-05-40		216	(pt)	00-04-00
	219	(pt)	00-11-88		219	(pt)	00-24-00

PART-II

Village	Sl No.	H. No.	Area
Shilatane	199	(pt)	00-01-00
	205	(pt)	00-01-00

[No. O-12016/32/82-Prod. II]

का०आ० 3743.—भारत सरकार के राजपत्र भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) दिनांक 5 फरवरी 1983 पृष्ठ क्रमांक 682 और 683 का०आ० संख्या क्रमांक O-12016/32/82-प्रोड-1 के अंतर्गत भारत सरकार, उर्जा मंत्रालय (पेट्रोलियम विभाग) की अधिसूचना संख्या क्रमांक 783 दिनांक 5 फरवरी 1983 के अंतर्गत पेट्रोलियम और खनिज पाईप लाईन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम 1962 की धारा 6 उपधारा (i) के अधीन वर्णित गांव-1, मुंढावरे 2. वलक 3. वडिवलें 4. नायगांव तहसील-मावल जिला-पुणे महाराष्ट्र के अंतर्गत अधिसूचना में वर्णित भूमि में खसरा नम्बर, हिस्सा नम्बर, क्षेत्रफल कालम 1 के बदले अनुसूचा में खसरा नम्बर, हिस्सा नम्बर क्षेत्रफल कालम 2 में दी गई अनुसूची को पढें।

निम्नलिखित अनुसूची के भाग 2 में वर्णित भूमि में पाईप लाईन बिछाने का प्रयोजन अलाईनमेंट बदलने से अब न रहा है। अब अतः निम्नलिखित अनुसूची के भाग 2 में वर्णित भूमि, धारा 6 की उपधारा (1) अधिसूचना को अनुसूची से कम कर दी गई है

अनुसूची

भाग - I

कालम II पढ़ें

कालम I के लिए

गांव	खसरा नम्बर	हिस्सा नम्बर	क्षेत्रफल	गांव	खसरा नम्बर	हिस्सा नम्बर	क्षेत्रफल
मुंढावरे	77	का भाग	00-45-00	मुंढावरे	77	का भाग	00-45-00
	91	1	00-10-80		91	,,	00-21-00
	96	4	00-21-60		96	,,	00-11-00
	102	2	00-02-88				
	102	3	00-06-30		102	,,	00-22-00
	102	4	00-07-20				
	101	2—2	00-05-40				
					101	,,	00-28-00
	101	2—1	00-07-38				
	101	1	00-15-30				
	110	का भाग	00-05-76		110	,,	00-26-00
	111	1	00-05-40		111	,,	00-08-00
	112	2	00-36-00		112	,,	00-33-00
	113	4	00-13-50				
	114	2	00-05-04		113	,,	00-27-00
	96	2					
	113	3	00-01-35				
	114	का भाग	00-06-12		114	,,	00-01-00
	80	,,	00-10-80		80	,,	00-14-00
	85	9	00-10-80				
	85	7	00-08-10		85	,,	00-49-00
	85	5	00-04-05				
	85	11	00-08-10				

भाग - II

गांव	खसरा नं०	हिस्सा नं०	क्षेत्रफल
मुंढावरे			
	93	का भाग	00-13-00
	94	,,	00-01-00
	125	,,	00-01-00

अनुसूची

भाग -I

कालम II पढ़ें. कालम I के लिए

गांव	खसरा नम्बर	हिस्सा नम्बर	क्षेत्रफल	गांव	खसरा नम्बर	हिस्सा नम्बर	क्षेत्रफल
धलाख	86	का भाग	00-13-50	धलाख	86	का भाग	00-14-00
	87	,,	00-10-80		87	,,	00-23-00

भाग - II

कुछ नहीं

अनुसूची

भाग - I

कालम II पढ़ें. कालम I के लिए

गांव	खसरा नम्बर	हिस्सा नम्बर	क्षेत्रफल	गांव	खसरा नम्बर	हिस्सा नम्बर	क्षेत्रफल
वाडिवले	10	1	00-03-60	वाडिवले	10	का भाग	00-23-00
	10	2	00-03-60				
	10	3	00-03-96				
	10	4	00-03-60				
	10	6	00-21-60				
	15	1+2+3	00-18-72		15	,,	00-20-00
	17	का भाग	00-23-94		17	,,	00-23-00
	18	4	00-03-60		18	,,	00-03-00
	23	2	00-01-80		23	,,	00-03-00
	24	4	00-29-52		24	,,	00-21-00
	25	4	00-15-30		25	,,	00-37-00
	25	1+2+3	00-06-84				
	28	4	00-26-46				
					28	,,	00-19-00
	28	2	00-17-10				

भाग - II

गांव	खसरा नं	हिस्सा नं	क्षेत्रफल
वाडिवले	16	का भाग	00-13-00
	27	,,	00-05-00

अनुसूची

भाग - I

कालम II पढ़ें				कालम I के लिए			
गांव	खसरा नम्बर	जुना नम्बर	क्षेत्रफल	गांव	खसरा नम्बर	हिस्सा नम्बर	क्षेत्रफल
नायगांव	273	86	00-49-14	नायगांव	86	का भाग	00-54-00
	282	86	00-11-52				
	323	86	00-10-80				
	281	87	00-06-48				
					87	,,	00-12-00
	300	87	00-03-28				
	326	88	00-21-00		88	,,	00-16-00
	325	89	00-10-08		89	,,	00-26-00
	324	89	00-19-62				
	322	135	00-11-70		135	,,	00-43-00
	422	135	00-10-62				
	423	136	00-16-20				
					136	,,	00-08-00
	424	136	00-11-34				
	425	148	00-10-80		148	,,	00-22-00

भाग - II

गांव	खसरा नं	हिस्सा नं	क्षेत्रफल
नायगांव	81	का भाग	00-06-00
	149	,,	00-21-00

ह०/-

[सं O-12016/32/82-गैस-III]

S.O. 3743.—In the Notification of Government of India, Ministry of Energy (Department of Petroleum) No. O-12016/32/82-Prod-I dated 5-2-1983, published under S.O. No. 783 in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-Section (ii) at page 682 & 683 issued under Section 6 Sub-Section (i) of the Petroleum & Minerals Pipe Lines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 in respect of village (1) Mundhaware (2) Valakh (3) Wadiwale (4) Naigaon for S. Nos. and areas shown in the Column No. 1 of the Schedule appended to this corrigendum, read and S. Nos. and areas as shown in column No. 2 of the said schedule.

Lands mentioned in the Part II of the appended schedule, however, do not come under the Pipe Line Project due to change in the alignment and therefore, they are deleted from the schedule appended to the Notification under section 6 Sub-Section (i) referred to above.

PART-II

Read (Col-II)				For (Col-I)			
Village	S. No. G. No.	H. No.	Area	Village	S.No. G. No.	H.No.	Area
Mundhavare.	77	(pt)	00–45–00	Mundhavare.	77	(pt)	00-45-00
	91	1	00–10–80		91	(pt)	00–21–00
	96	4	00–21–60		96	(pt)	00–11–00
	102	2	00–02–88				
	102	3	00–06–30		102	(pt)	00–22–00
	102	4	00–07–20				
	101	2–2	00–05–40				
	101	2–1	00–07–38		101	(pt)	00–28–00
	101	1	00–15–30				
	110	(pt)	00–05–76		110	(pt)	00–26–00
	111	1	00–05–40		111	(pt)	00–08–00
	112	2	00–36–00		112	(pt)	00–33–00
	113	4	00–13–50				
	113	2	00–05–04		113	(pt)	00–27–00
	96	2					
	113	3	00–01–35				
	114	(pt)	00–06–12		114	(pt)	00–01–00
	80	(pt)	00–10–80		80	(pt)	00–14–00
	85	9	00–10–80				
	85	7	00–08–10				
	85	5	00–04–05		85	(pt)	00–49–00
	85	11	00–08–10				

PART II

Village	S.No.	H.No.	Area
Mundhavare	93	(pt)	00-13-00
	94	(pt)	00-01-00
	125	(pt)	00-01-00

Read (Col-II) For (Col-I)

PART I

Village	S.No. G.No.	H.No.	Area	Village	S.No. G.No.	H.No.	Area
Valak.	86	(pt)	00-13-50		86	(pt)	00-14-00
	87	(pt)	00-10-80		87	(pt)	00-26-00

PART II

--NIL--

Read (Col-II) For (Col-I)

PART II

Village	S.No.	H.No.	Area	Village	S.No.	H.No.	Area
Wadivale.	10	1	00-03-60	Wadivale.	10	(pt)	00-23-00
	10	2	00-03-60				
	10	3	00-03-96				
	10	4	00-03-60				
	10	6	00-21-60				
	15	1+2	3 00-18-72		15	(pt)	00-20-00
	17	(pt)	00-23-94		17	(pt)	00-23-00
	18	4	00-03-60		18	(pt)	00-03-00
	23	2	00-01-80		23	(pt)	00-03-00
	24	4	00-29-52		24	(pt)	00-21-00
	25	4	00-15-30		25	(pt)	00-37-00
	25	1+2	3 00-06-84				
	28	4	00-26-46		28	(pt)	00-19-00
	28	2	00-17-10				

PART II

Village	S.No.	H.No.	Area
Wadivale.	16	(pt)	00-16-00
	27	(pt)	00-05-00

Read (Col-II) For (Col-I)

PART I

Village	S.No. H. No.	Old No	Area	Village	S.No.	H.No.	Area
Naigaon	273	86	00-49-14	Naigaon			
	282	86	00-11-52		86	(pt)	00-54-00
	323	86	00-10-80				
	281	87	00-06-48		87	(pt)	00-12-00
	300	87	00-03-28				
	326	88	00-21-00		88	(pt)	00-16-00
	325	89	00-10-08		89	(pt)	00-26-00
	324	89	00-19-62				
	322	135	00-11-70				
					135	(pt)	00-43-00
	422	135	00-10-62				
	423	136	00-16-20				
					136	(pt)	00-08-00
	424	136	00-11-34				
	425	148	00-10-80		148	(pt)	00-22-00

PART-II

Village	S.No.	H. No.	Area
Naigaon	81	(pt)	00-06-00
	149	(pt)	00-21-00

[No. O-12016/32/82-Prod. III]

का.आ. 3744.—यतः पैट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना का. आ. सं. 2765 तारीख 23-7-86 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे, यतः केन्द्रीय सरकार उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब, अतः अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइप लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने की बजाय तेल और प्राकृतिक गैस आयोग में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

अनुसूची

ऐस.एन.सी.टी. से ऐस.एन.ऐ.ओ. (47) तक पाइप लाइन बिछाने के लिए।

राज्य : गुजरात जिला व तालुका : मेहसाना

गांव	ब्लाक नं.	हैक्टेयर	आरे.	सेन्टीयर
कसलपुरा	623	0	00	60
	620	0	05	28
	616	0	06	60
	615	0	04	80
	614	0	01	92

[सं. O-12016/111/86-ओ एन जी डी 4]

S.O. 3744.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum & Natural Gas S.O. 2765 dated 23-7-86 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that Notification for the purpose of laying pipeline.

And whereas the Competent Authority has under Sub-Section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of the section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Oil & Natural Gas Commission free from encumbrances.

SCHEDULE

Pipeline from SNCT to SNAO (47)

State : Gujarat District & Taluka : Mehsana

Village	Block No.	Hectare	Are	Centiare
Kasalpura	623	0	00	60
	620	0	05	28
	616	0	06	60
	615	0	04	80
	614	0	01	92

[No. O—12016/111/86-ONGD 4]

का.आ. 3745.—यतः पैट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन अधिनियम 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना का.आ.सं. 2764 तारीख 23-7-86 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे, यत: केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब अत: उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद् द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद् द्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने की बजाय तेल और प्राकृतिक गैस आयोग में, सभी बाधाओं से मुक्त रूप में, घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

अनुसूची

एन.के.ई.यू. से रेलवे क्रोसिंग तक पाइप लाइन बिछाने के लिए।

राज्य : गुजरात जिला : अहमदाबाद तालुका : विरमगाम

गांव	सर्वे नं.	हेक्टेयर	आरे.	सेन्टीयर
बाल सासन	398	0	19	80

[सं. O-12016/112/86-ओ एन जी-डी 4]

पी. के. राजगोपालन, डैस्क अधिकारी

S.O. 3745.—Whereas by Notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum & Natural Gas S.O. 2764 dated 23-7-86 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of User in the lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline.

And whereas the Competent Authority has under Sub-Section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of the section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Oil & Natural Gas Commission free from encumbrances.

SCHEDULE

Pipe Line from NKEU to RLY. Crossing

State : Gujarat District : Ahmedabad Taluka : Viramgam

Village	Survey No.	Hect-are	Are	Centi-are
Balsasan	398	0	19	80

No. O—12016/112/86-ONG-D4]

P.K. RAJAGOPALAN, DESK OFFICER

ऊर्जा मंत्रालय

(कोयला विभाग)

नई दिल्ली, 15 अक्तूबर, 1986

का०आ० 3746:—केन्द्रीय सरकार, कोयला भविष्य निधि स्कीम, 1948 के पैरा 9 के साथ पठित कोयला खान भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1948 (1948 का 46) की धारा 3क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय (कोयला विभाग) की अधिसूचना सं० का०आ० 2723, तारीख 8 अगस्त, 1984 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात :—

उक्त अधिसूचना में, क्रम सं 12, 14 और 17 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात :—

"12. श्री ए. बी. ग्रहूजा, निदेशक (कार्मिक और औद्योगिक संबंध) कोल इंडिया लिमिटेड,
10 नेताजी सुभाष रोड, कलकत्ता-700001"
"14. श्री जे० शरण, निदेशक (कार्मिक),
ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड,
संकतोड़िया, डाकखाना दिशेरगढ़,
जिला—बर्दवान-713333" और
"17. श्री डी० एन० मोहन मूर्ती, निदेशक (कार्मिक),
सिंगरेनी कोलियरीज कम्पनी लिमिटेड,
कोठागुडम, कोलियरीज,
जिला—खमाम-पिन 507101"

[सं 7(3)/80-प्रशा०I(भा०नि०) (जिल्द-II)]

MINISTRY OF ENERGY

(Department of Coal)

New Delhi, the 15th October, 1986

S.O. 3746.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the Coal Mines Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act, 1948 (46 of 1948), read with paragraph 9 of the Coal Mines Provident Fund Scheme, 1948 the Central Government hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Energy (Department of Coal) No. S.O. 2723, dated the 8th August, 1984, namely :—

In the said notification, for serial numbers 12, 14 and 17 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely :—

"12. Shri A. V. Brahma, Director (Personnel & Industrial Relations), Coal India Limited, 10-Netaji Subhash Road, Calcutta-700001.";

"14. Shri J. Sharan, Director (Personnel), Eastern Coalfields Limited, Sanctoria, P.O. Disergarh, District Burdwan-713333."; and

"17. Shri D. N. Mohana Murthi, Director (Personnel), Singareni Collieries Company Limited, Kothagudem Collieries, District Khamam Pin-507101".

[No. 7(3)/80-Adm. I(PF)(Vol. II)]

नई दिल्ली, 16 अक्तूबर, 1986

का आ 3747:—केन्द्रीय सरकार ने, कोयला धारक क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 (1957 का 20) की धारा 4 की उप-धारा (1) के अधीन, भारत के राजपत्र, भाग 2, खंड 3, उप-खंड (ii) तारीख 25 मई, 1985 में प्रकाशित भारत सरकार के तत्कालीन इस्पात, खान और कोयला मंत्रालय (कोयला विभाग) की अधिसूचना सं० का०आ० 2238 तारीख 8 मई, 1985 द्वारा, उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट परिक्षेत्र में 2123.50 एकड़ (लगभग) या 859 34 हैक्टर (लगभग) भूमि में कोयले का पूर्वेक्षण करने के अपने आशय की सूचना दी थी;

और केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो गया है कि उक्त भूमि के भाग में कोयला अभिप्राप्य है;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इससे उपाबद्ध अनुसूची में वर्णित 107.00 एकड़ (लगभग या 43.30 हैक्टर (लगभग) माप की उक्त भूमि के भाग के अर्जन करने के अपने आशय की सूचना देती है;

टिप्पण 1 : इस अधिसूचना के अधीन आने वाले क्षेत्र के रेखांक का निरीक्षण उपायुक्त, हजारीबाग (बिहार) के कार्यालय में या कोयला नियंत्रक, 1, काउंसिल हाउस स्ट्रीट, कलकत्ता-1 के कार्यालय में अथवा सैन्ट्रल कोलफील्ड्स लि० (राजस्व अनुभाग), दरभंगा हाउस, रांची (बिहार) के कार्यालय में किया जा सकता है ।

टिप्पण 2 : कोयला धारक क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 (1957 का 20) की धारा 8 के उपबंधों की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है जिसमें निम्नलिखित उपबंध हैं :—

"8 (1) किसी ऐसी भूमि में, जिसकी बाबत धारा 7 के अधीन अधिसूचना जारी की गई है, हितबद्ध कोई भी व्यक्ति, अधिसूचना जारी किए जाने के तीस दिन के भीतर सम्पूर्ण भूमि या उसके किसी भाग या ऐसी भूमि में या उस पर के किन्हीं अधिकारों का अर्जन किए जाने के बारे में आक्षेप कर सकेगा ।

स्पष्टीकरण : इस धारा के अर्थान्तर्गत किसी व्यक्ति की ओर से यह कहना आक्षेप नहीं माना जाएगा कि वह स्वयं भूमि में कोयला उत्पादन के लिए खनन संक्रियाएं करना चाहत है और ऐसी संक्रियाएं केन्द्रीय सरकार या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा नहीं की जानी चाहिए ।

(2) उपधारा (1) के अधीन प्रत्येक आक्षेप सक्षम प्राधिकारी को लिखित रूप में किया जाएगा और सक्षम प्राधिकारी आक्षेपकर्ता को व्यक्तिगत रूप में सुने जाने का या विधि व्यवसायी द्वारा सुनवाई का अवसर देगा और ऐसे सभी आक्षेपों को सुनने के पश्चात् और ऐसी अतिरिक्त जांच, यदि कोई है, करने के पश्चात् जो वह आवश्यक समझे, या तो धारा 7 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचित भूमि में या ऐसी भूमि में या उस पर के अधिकारों के संबंध में एक रिपोर्ट या ऐसी भूमि के विभिन्न टुकड़ों या ऐसी भूमि में या उस पर के अधिकारों के संबंध में आक्षेपों पर अपनी सिफारिशों और उसके द्वारा की गई कार्रवाई के अभिलेख सहित, विभिन्न रिपोर्टें केन्द्रीय सरकार को उसके विनिश्चय के लिए देगा।

(3) इस धारा के प्रयोजनों के लिए वह व्यक्ति किसी भूमि में हितबद्ध समझा जाएगा जो प्रतिकर में हित का दावा करने का हकदार होता यदि भूमि या ऐसी भूमि में या उस पर के किन्हीं अधिकारों को इस अधिनियम के अधीन अर्जित कर लिया जाता है ।

टिप्पण 3 : केन्द्रीय सरकार ने, कोयला नियंत्रक, 1, काउंसिल स्ट्रीट, कलकत्ता को उक्त अधिनियम के अधीन सक्षम प्राधिकारी नियुक्त किया है ।

अनुसूची

मांडू ब्लाक–उप ब्लाक II

पश्चिम बोकारो कोयला क्षेत्र

जिला हजारीबाग, बिहार

रेखांक सं. राजस्व/19/86

तारीख 21-4-1986

(जिसमें अर्जित की जाने वाली भूमि दर्शित की गई है)

सभी अधिकार

क्र.सं.	ग्राम	थाना	थाना सं.	जिला	क्षेत्र	टिप्पणियां
1.	कुजू	मांडू	154	हजारीबाग	40.00	भाग
2.	पोखरियां	मांडू	121	"	67.00	भाग
				कुल –क्षेत्र :	107.00 एकड़ (लगभग)	
				या	43.30 हैक्टर (लगभग)	

कुजु ग्राम में अर्जित किए जाने वाले प्लाट सं.

50 (भाग), 53 (भाग), 54 से 73, 74 (भाग), 75 (भाग), 76 (भाग), 77 (भाग), 78 (भाग), 79 (भाग), 93 (भाग), 94, 95 (भाग), 96 (भाग), 97 (भाग), 107 (भाग), 122 (भाग), 123 (भाग), 125 से 145, 146 (भाग), 147 148, 149, 150, 151 (भाग), 152 (भाग), 153 (भाग), 154, 155 (भाग), 156 (भाग), 157 (भाग), 158 (भाग), 160 (भाग), 163 (भाग), 164 (भाग), 165 (भाग), 166, 167 (भाग), 174 (भाग), 175 (भाग), 176 (भाग), 177 (भाग), 178 (भाग), 179, 180, 181 (भाग), 182 (भाग), 183 से 187 और 188 (भाग), 207 (भाग) और 256 (भाग)

पोखरिया ग्राम में अर्जित किए जाने वाले प्लाट सं.

1 से 9, 10(भाग), 11, 12 (भाग), 18 (भाग), 32 (भाग), 33, 34, 35 (भाग), 36 से 40, 41 (भाग), 42 (भाग) 45 (भाग) और 46 (भाग)

सीमा वर्णन :

ङ–ङ रेखा, कुजु ग्राम में प्लाट सं. 164 (नदी), 55, 53, 50, 79, 78, 77, 76, 75, 74, 93, 47, 96, 95 107, 123, 151, 122 152, 153, 152, 165 और 207 से होकर जाती है (जो कुजु कोयला खान के साथ सम्मिलित सीमा बनाती है) और बिन्दु "ङ" पर मिलती है।

ङ-ग-त रेखा, कुजु ग्राम से प्लाट सं. 201 256, 207, 165, 156, 155, 157, 158, 50, 160, 50, 146, 50, 163, 50, 165, 188, 182, 181, 173, 172, 176, 175, 174 और 167 से होकर जाती है और फिर पोखरिया ग्राम में प्लाट सं. 46, 10, 18, 12, 18, 12 32, 41, 42, 35 और 45 से होकर जाती है (जो मूरपा कोलियर के साथ भागतः सम्मिलित सीमा बनाती है) और बिन्दु "त" पर मिलती है।

त-थ रेखा नाले को मध्य रेखा के भाग के साथ-साथ जाती है (जो आरा और पोखूरिया ग्रामों की भागतः सम्मिलित सीमा बनाती है) और बिन्दु 'क' पर मिलती है।

थ-द रेखा नदी की मध्य रेखा के साथ-साथ जाती है (जो पोखरिया और नोंगहारा ग्रामों की सम्मिलित सीमा बनाती है) और बिन्दु "द" पर मिलती है।

द-ङ रेखा नदी की भागतः मध्य रेखा के साथ-साथ जाती है (जो कुजु और हेसागारा ग्रामों की और हेसागारा कोलियरी सीमा के भाग के साथ-साथ सम्मिलित सीमा बनाती है) और आरंभिक बिन्दु "ङ" पर मिलती है।

[फा.सं. 43015/8/85–सी.ए.]

MINISTRY OF ENERGY

(Department of Coal)

New Delhi, the 16th October, 1986

S.O. 3747.—Whereas by notification of the Government of India in the then Ministry of Steel, Mines and Coal (Department of Coal) No. S.O. 2238, dated the 8th May, 1985, under sub-section (1) of section 4 of the Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957 (20 of 1957), published in the Gazette of India, Part-II-Section 3-Sub-section (ii), dated the 25th May, 1985, the Central Government gave notice of its intention to prospect for coal in lands measuring 2123.50 acres (approximately) or 859.34 hectares (approximately) in the localities specified in the Schedule appended to that notification;

And whereas the Central Government is satisfied that coal is obtainable in the part of the said lands;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 7 of the said Act, the Central Government hereby gives notice of its intention to acquire the part of said lands measuring 107.00 acres (approximately) or 43.30 hectares (approximately) described in the Schedule appended hereto.

Note 1 .—The plan of the area covered by this notification may be inspected in the office of the Deputy Commissioner, Hazaribagh (Bihar) or in the office of the Coal Controller, 1, Council House Street, Calcutta-1 or in the office of the Central Coalfields Limited (Revenue Section), Darbhanga House, Ranchi (Bihar).

Note 2 :—Attention is hereby invited to the provisions of section 8 of the Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957 (20 of 1957), which provides as follows :—

"8(1) Any person interested in any land in respect of which a notification under section 7 has been issued may, within thirty days of the issue of the notification, object to the acquisition of the whole or any of the land or of any rights in or over such land.

Explanation :—It shall not be an objection within the meaning of this section for any person to say that he himself desires to undertake mining operations in the land for the production of coal and that such operations should not be undertaken by the Central Government or by any other person.

(2) Every objection under sub-section (1) shall be made to the competent authority in writing, and the competent authority shall give the objector an opportunity of being heard either in person or by a legal practitioner and shall, after hearing all such objections and after making such further inquiry, if any, as he thinks necessary, either make a report in respect of the land which has been notified under sub-section (1) of section 7 or of rights in or over such land, or make different reports in respect of different parcels of such land or rights in or over such land, to the Central Government, containing his recommendations on the objections, together with the record of the proceedings held by him, for the decision of that Government.

(3) For the purposes of this section, a person shall be deemed to be interested in land who would be entitled to claim an interest in compensation if the land or any rights in or over such land were acquired under this Act".

Note 3.—The Coal Controller, 1, Council House Street, Calcutta has been appointed by the Central Government as the competent authority under the said Act.

SCHEDULE
MANDU BLOCK—SUB SBLOCK II
WEST BOKARO COALFIELD
DISTT. HAZARIBAGH
BIHAR

Drg. No. Rev/17/36
Dated : 21-4-86
(Showing lands to be acquired)

All Rights

Sl. No.	Village	Thana	Thana Number	District	Area	Remarks
1.	Kuju	Mandu	154	Hazaribagh	40.00	Part
2.	Pokharia	,,	121	,,	67.00	,,

Total Area:—107.00 acres (approximately)
or 43.30 Hectares (approximateiy)

Plot numbers to be acquired in village Kuju :—

50 (Part), 53 (Part), 54 to 73, 64 (Part) 75 (Part), 75 (Part), 77 (Part), 68 (Part), 79 (Part), 93 (Part), 94 95 (Part), 86 (Part) 97 (Part), 107 (Part), 122 (Part), 123 (Part), 125 to 145 146 (Part) 147, 148, 149, 150, 161 (Part), 152 (Part), 153 (Part), 154, 155 (Part), 156 (Part), 157 (Part), 158 (Part), 160 (Part), 163 (Part), 164 (Part), 165 (Part), 166, 167 (Part), 174(Part), 175 (Part), 176 (Part), 177 (Part) 178 (Part), 179, 180. 181 (Part), 182 (Part), 183 to 187, and 188 (Part), 207 (Part) and 256 (Part).

Plot numbers to be acquired in village Pokharia :—

1 io 9, 10 (Part), 11, 12 (Part), 18(Part), 32(Part), 33, 34, 35 (Part), 36 to 40, 41 (Part), 42 (Part,), 45 (Part) and 56 (Part).

Boundary description :—

M—N line passes through plot numbers 164 (River) 50, 53, 50, 79, 78, 79, 76, 75, 74, 93, 47, 96, 95, 107, 123, 151, 122, 152, 153, 152, 165, and 207 in village Kuju (which forms common boundary with Kuju Colliery) adad meets at point 'N'.

N–O–P lines pass through plot numbers 207, 256, 207, 165, 156, 155, 157, 158, 50,160, 50, 146, 50, 163, 50, 165, 183, 182, 181, 178, 177, 176, 175, 175, and 167 in village Kuju then through plot numbers 45, 10, 18, 12, 19, 12, 32, 41, 42, 35 and 45 in village Pokharia (which forms part common boundary with Murpa Colliery) and meets at point 'P'.

P—Q line passes along the part Central line of nala (which forms part common boundary of villages Area and Pokharia and meets 8t point 'Q'.

Q—R line passes along the Central line of the River (which forms common boundary(of villages Pokharia and Bongahara) and meets at point 'B'.

R—M line passes along the part central line of the River (hich oforms part common boundary of village Kuju and Hesagara and also along part Hesagara Colliery boundary) and meets at starting point 'BM'.

[No. 43015/3/55-CA]

का.आ. 3748.—केन्द्रीय सरकार ने, भारत सरकार के तब इस्पात खान और कोयला मंत्रालय (कोयला विभाग) की अधिसूचना सं. का. आ. 2237 तारीख 8 मई, 1985 द्वारा जो भारत के राजपत्र, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) तारीख 25 मई 1985 में प्रकाशित की गई थी, उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट परिक्षेत्र 270.00 एकड़ (लगभग) या 109.26 हेक्टर (लगभग) के माप की भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की सूचना, कोयला धारक क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम 1957 (1957 का 20) की धारा 7 की उपधारा (1) के अधीन दी थी ;

और सक्षम प्राधिकारी ने, उक्त अधिनियम की धारा 8 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

और केन्द्रीय सरकार को पूर्वोक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात तथा बिहार सरकार से परामर्श करने के पश्चात यह समाधान हो गया है कि इससे संलग्न अनुसूची में वर्णित 270.00 एकड़ (लगभग) या 109.26 हेक्टेयर (लगभग) माप की भूमि का अर्जन कर लिया जाना चाहिए

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में वर्णित, 270.00 एकड़ (लगभग) या 109.26 हेक्टेयर (लगभग) माप की भूमि का अर्जन किया जाता है।

2. इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र के रेखांक का निरीक्षण उपायुक्त हजारीबाग (बिहार) के कार्यालय में या कोयला नियंत्रक, 1, काउंसिल हाउस स्ट्रीट कलकत्ता-1 के कार्यालय में या सेन्ट्रल कोलफील्डस लिमिटेड (राजस्व अनुभाग), दरभंगा हाउस, रांची (बिहार) के कार्यालय में किया जा सकता है।

अनुसूची
लापंगा विस्तार –II
(दक्षिण करनपुरा कोयला क्षेत्र)
जिला हजारीबाग (बिहार)

आरेखन सं. राजस्व/2/86
तारीख 6-11986
(अर्जित की गई भूमि दर्शित)

सभी अधिकार

क्र. सं.	ग्राम	थाना	थाना सं.	जिला	क्षेत्र	टिप्पणियां
1.	बुंडु	मांडू	39	हजारीबाग	270.00 भाग	
				कुल क्षेत्र :	270.00 एकड़ (लगभग)	
				या	109.26 हेक्टर (लगभग)	

बुंडु ग्राम में अर्जित किए गए प्लाट सं.

560, 562 से 570, 571 (भाग), 576 (भाग) और 649 (भाग)

सीमा वर्णन :

क-ख रेखा, दामोदर नदी के बांए किनारे के भाग के साथ-साथ जाती है ।

ख-ग रेखा, ग्राम बुंडु और सिरका की सम्मिलित सीमा के भाग के साथ-साथ जाती है ।

ग-घ-ङ रेखा, बुंडु ग्राम में प्लाट सं. 649 571 और 576 से होकर जाती है (जो सिरका कोयला खान विस्तार के लिए कोयला अधिनियम की धारा 9(1) के अधीन अर्जित क्षेत्र 102.00 एकड़ क्षेत्र की सम्मिलित सीमा बनती है)

ङ-क रेखा, बुंडु ग्राम में प्लाट सं. 576 और प्लाट सं० 562 और 560 की उत्तरी सीमा से होकर जाती है और आरंभिक बिन्दु "क" पर मिलती है ।

[सं. 43015/3/86-सी. ए.]

S.O.3748—Whereas by the notification of the Government of India in the then Ministry of Steels Mines and Coal (Department of Coal) No. S.O. 2237 dated the 8th May 1985, under sub-section (1) of Section 7 of the Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act 1957 (20 of 1957) published in the Gazette of India Part II-Section 3-Sub-section (ii) dated the 25th May, 1985, the Central Government gave notice of its intention to acquire the lands measuring 270.00 acres (approximately) or 109.26 hectares (approximately) in the locality specified in the Schedule appended to that notification;

And whereas the competent authority, in pursuance of section 8 of the said Act, has made his report to the Central Government;

And whereas the Central Government, after considering the report aforesaid and after consulting the Government of Bihar, is satisfied that the lands measuring 270.00 acres (approximately) or 109.26 hectares (approximately) described in the Schedule appended heteto;

should be acquired.

Now, therefore, in exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 9 of the said Act, the Central Government hereby declares that the lands measuring 270.00 acres (approximately) or 109.26 hectares (approximately), described in the schedule appended hereto;

are hereby acquired.

The plans of the area covered by this notification may be inspected in the office of the Deputy Commissioner, Hazaribagh (Bihar) or in the office of Coal Controller, 1, Council House Street, Calcutta-1 or in the office of the Central Coalfields Limited (Revenue Section), Darbhanga House, Ranchi (Bihar).

SCHEDULE
LAPANGA EXTN. II
(SOUTH KARANPURA COALFIELD)
DIST. HAZARIBAGH (BIHAR)

Drg. No. Rev/2/86
Dated 6-1-1986
(Showing the lands acquired)

All Rights

Serial Number	Village	Thana	Thana Number	District	Area	Remarks
1	Bundu	Mandu	39	Hazaribagh	270.00	Part

Total area 270.00 acres (approximately)
or 109.26 hectares (approximately)

Plot numbers acquired in village Bundu :—
560, 562 to 570, 571 (Part), 576 (Part) and 649 (Part).

BOUNDARY DESCRIPTION :

A–B line passes along the part left bank of river Damodar.
B–C line passes along the part common boundary of villages Bundu and Sirka.
C–D–E lines pass through plot numbers 649, 571 and 576 in village Bundu (which forms common boundary of the area acquired u/s 9(1) of the Coal Act area 102.00 acres for Sirka Colliery Extension).
E–A line passes through plot number 576 and nothern boundary of plot numbers 562 and 569 in village Bundu and meets at starting point 'A'.

[No. 43015/3/86-CA]

नई दिल्ली, 21 अक्तूबर, 1986

शुद्धि पत्र

का० आ० 3749.—भारत के राजपत्र दिनांक 14 जून, 1986 के भाग-2, खण्ड 3, उप खंड (ii) में पृष्ठ 2478 पर प्रकाशित भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय, (कोयला विभाग) की अधिसूचना का० आ० सं० 2297, दिनांक 28 मई, 1986 में—

पृष्ठ 2478 पर—अनुसूची में ।

(1) आई बी ब्लाक-1,
आई बी घाटी कोयला क्षेत्र के स्थान पर "इब ब्लाक-1
इब घाटी कोयला क्षेत्र" पढ़े ।

(2) सीमा वर्णन में—

(अ) रेखा च 4 से च 6 में "कुटापालि" के स्थान पर "कटापालि" पढ़ें ।
(ब) रेखा च 6 से च 10 में बालपर के स्थान पर "बालपुट" पढ़े ।
(क) रेखा "घ 1ङ-च1" के स्थान पर "घ 1-ङ 1-च 1" पढ़ें ।

[सं० 43015/1/86-सी० ए०]

का० आ० 3750.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में उल्लिखित भूमि में कोयला अभिप्राप्त किए जाने की संभावना है;

अतः, अब केन्द्रीय सरकार, कोयला धारक क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 (1957 का 20) की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उस क्षेत्र में कोयले का पूर्वेक्षण करने के अपने आशय की सूचना देती है;

इस अधिसूचना के अधीन आने वाले क्षेत्र के रेखांक सं राजस्व /70/82 तारीख 5 अक्तूबर, 1982 का निरीक्षण सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड, राजस्व अनुभाग, दरभंगा, हाउस, रांची-834001 (बिहार) के कार्यालय में या उपायुक्त हजारीबाग (बिहार) के कार्यालय में, या उपायुक्त, पलामू (बिहार) के कार्यालय में अथवा कोयला नियंत्रक, 1-काउन्सिल हाउस स्ट्रीट, कलकत्ता-700001 के कार्यालय में किया जा सकता है।

इस अधिसूचना के अधीन आने वाली भूमि में हितबद्ध सभी व्यक्ति उक्त अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (7) में निर्दिष्ट सभी नक्शों, चार्टों और अन्य दस्तावेजों को, इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से नब्बे दिन के भीतर, राजस्व अधिकारी केन्द्रीय कोलफील्ड्स लिमिटेड, दरभंगा, रांची-834001 (बिहार) को भेजेंगे ।

अनुसूची

मगध ब्लाक

(उत्तरी करणपुरा कोयला क्षेत्र)

(जिसमें पूर्वेक्षण करने के लिए भूमि दर्शित की गई है)

क्र०सं०	ग्राम	थाना	थाना सं०	जिला	क्षेत्र	टिप्पणियां
1.	आरा	बालुमठ	55	पलामू	1056 00	भाग
2.	चामटू	,,	56	,,	2220 80	भाग
3.	कुर्लोगा	टांडवा	26/183	हजारीबाग	665 00	भाग
4.	कुंडी	,,	27/184	,,	314 47	पूर्ण
5.	देवलगारा	,,	28/185	,,	120 44	,,
6.	सराधू	,,	29/186	,,	3377 00	भाग
7.	हेचावालिया	,,	30/187	,,	25 00	,,
8.	मासीलोंगा	,,	61/218	,,	192 00	,,
9.	रेहम	,,	62/219	,,	128 00	,,
10.	सिदूपा	,,	64/221	,,	205 00	,,
11.	दाहू	,,	65/222	,,	96 29	,,

कुल क्षेत्र 8400.00 एकड़ (लगभग)

या 3399 31 हेक्टर (लगभग)

सीमा वर्णन :

क-ख रेखा जिला हजारीबाग के कुर्लोगा ग्राम और जिला पलामू के बनालत ग्राम में भागतः जिला सीमा के साथ-साथ जाती है और बिन्दु "ख" पर मिलती है ।

ख-ग रेखा जिला हजारीबाग के कुर्लोगा ग्राम से होकर जाती है और जिला सीमा पर बिन्दु "ग" पर मिलती है ।

ग-घ-ङ रेखाएं जिला पलामू के चामटू ग्राम से होकर जाती है और जिला सीमा पर बिन्दु "ङ" पर मिलती है ।

ङ-च रेखा ग्राम कुर्लोगा से होकर जाती है और बिन्दु "च" पर मिलती है।

च-छ रेखा आरा और चामटू ग्रामों से होकर जाती है और बिन्दु "छ" पर मिलती है ।

छ-ज रेखा चामटू और फूलबसिया या अमरवाडीह, चामटू और गणेशपुर ग्रामों की भागतः सम्मिलित सीमा के साथ-साथ जाती है (जो उक्त अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (1) के अधीन अर्जित पिंडरूम ब्लाक के साथ सम्मिलित सीमा बनाती है) और बिन्दु "ज" पर मिलती है ।

ज-झ रेखा ग्राम चामटू से होकर जाती है और बिन्दु "झ" पर मिलती है ।

झ-ट रेखाएं दाहू और सिदूपा ग्रामों से होकर जाती हैं और बिन्दु "ट" पर मिलती है ।

ट-ठ रेखा सिदूपा, सराधू, रेहम और मसीलोंग ग्रामों से होकर जाती है और बिन्दु "ठ" पर मिलती है ।

ठ-ड-ढ रेखाएं मसीलोंग और सराधू ग्रामों से होकर जाती हैं और बिन्दु "ढ" पर मिलती हैं ।

ढ-ण-त रेखाएं सराधू और हैचरबलिया ग्रामों से होकर जाती है और बिन्दु "त" पर मिलती हैं ।

त-थ-द रेखाएं हैचरबलिया और सराधू ग्रामों से होकर जाती हैं और बिन्दु "द" पर मिलती हैं ।

द-क रेखा कुर्लोगा और बरकुट ग्रामों से होकर जाती है और आरम्भिक बिन्दु "क" पर मिलती है ।

[सं 19/95/82-सी० एल०/सी० ए०]

S O 3750.—Whereas it appears to the Central Government that coal is likely to be obtained from the land mentioned in the schedule hereto annexed;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957 (20 of 1957), the Central Government hereby gives notice of its intention to prospect for coal therein

The plan No. Rev/70/82 dated the 5th October, 1982 of the area covered by this notification may be inspected in the office of the Central Coalfields Limited, Revenue Section, Darbhanga House, Ranchi—834001(Bihar) or in the office of the Deputy Commissioner, Hazaribagh (Bihar) or in the office of the Deputy Commissioner, Palamau (Bihar) or in the office of the Coal Controller, I, Council House Street. Calcutta-700001.

All persons interested in the land covered by this notification shall deliver all maps, charts and other documents referred to in sub-section(7) of section 13 of the said Act to the Revenue Officer, Central Coalfields Limited, Darbhanga House, Ranchi-834001 (Bihar) within ninety days from the date of publication of this notification.

SCHEDULE

Magadu Block

(North Karanpura Coalfield)

(Showing land notified for prospecting)

Serial number	Village	Thana	Thana number	District	Area	Remarks
1.	Ara	Balmumath	55	Palamau	1056.00	Part
2.	Chamatu	—do—	56	—do—	2220.80	—do—
3.	Kurlonga	Tandwa	26/183	Hazaribagh	665.00	—do—
4.	Kundi	—do—	27/184	—do—	314.47	Full
5.	Davalgara	—do—	28/185	—do—	120.44	—do—
6.	Saradhu	—do—	29/186	—do—	3377.00	Part
7.	Hechabalia	—do—	30/187	—do—	25 00	—do—
8.	Masilaung	—do—	61/218	—do—	192.00	—do—
8.	Raham	—do—	62/219	—do—	128.00	—do—
10.	Sidpa	—do—	64/221	—do—	205.00	—do—
11.	Dahu	—do—	65/222	—do—	96.29	—do—

Total area : 8400.00 acres (approximately)
or 3399.31 hectares (approximately)

Boundary description :—

A B line passes along part district boundary in villages Kurlonga of District Hazaribagh and Banalat of Dist. Palamau and meets at point 'B'.

B-C line passes through village Kurlonga of district Hazaribagh and meets at point 'C' on the district boundary.

C-D-E lines pass through village Chamatu of district Palamau and meets at point 'E' on the district boundary.

E-F line passes through village Kurlonga and meets at point 'F'.

F-G line passes through village Ara and Chamatu and meet at point 'G'.

G-H line passes along part common boundary of villages Chamatu and Phulbasia or Ambarwadih, Chamatu and Ganeshpur (which forms common boundary with Pindercom Block acquired under sub-section (1) of section 9 of the said Act and meets at point 'H'.

H-I line passes through village Chamatu and meets at point 'I'.

I-J-K lines pass through villages Dahu and Sidpa and meets at point 'K'.

K-L line passes through villages Sidpa, Saradhu, Raham and Masilaung and meets at point 'L'.

L-M-N lines pass through villages Masilaung and Saradhu and meets at point 'N'.

N-O-P lines pass through villages Saradhu and Hechabalia and meets at point 'P'.

P-Q-R lines pass through village Hechabalia and Saradhu and meets at point 'R'.

R-A line passes along part common boundary of villages, Kurlonga and Barkute and meets at starting point 'A'.

[No. 19/95/82-CL/CA]

का० आ० 3751.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि इससे उपाबद्ध अनसूची में उल्लिखित परिक्षेत्र की भूमि में कोयला अभिप्राप्त किए जाने की संभावना है;

अतः, केन्द्रीय सरकार, कोयला धारक क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 (1957 का 20) की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उस क्षेत्र में कोयले का पूर्वेक्षण करने के अपने आशय की सूचना देती है;

इस अधिसूचना के अधीन आने वाले क्षेत्र के रेखांक सं० राजस्व/12/83 तारीख 23-2-1983 का निरीक्षण, सेन्ट्रल कोलफील्डस लि०, (राजस्व अनुभाग); दरभंगा हाउस, रांची के कार्यालय में या उपायुक्त पलामू (बिहार) के कार्यालय में अथवा कोयला नियंत्रक, 1, काउंसिल हाउस स्ट्रीट, कलकत्ता के कार्यालय में किया जा सकता है ।

इस अधिसूचना के अधीन आने वाली भूमि में हितबद्ध सभी व्यक्ति उक्त अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (7) में निर्दिष्ट सभी नक्शों, चार्टों और अन्य दस्तावेजों को, इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से नब्बे दिन के भीतर, राजस्व अधिकारी, सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लि., दरभंगा हाउस, रांची को भेजेगा।

अनुसूची

मैदिनी राय ब्लाक

(हुसार कोयला क्षेत्र)

(जिसमें पूर्वेक्षण के लिए अधिसूचित भूमि दर्शित की गई है)

क्र सं	ग्राम	अंचल	राजस्व	थाना सं	जिला	क्षेत्र	टिप्पणियां
1.	मोरवाई खुर्द	मर्वाडीह	लातेहार	35	पलामू	450.00	भाग
2.	मोरवाई कलां	,,	,,	39	,,	2630.00	भाग
3.	बेरीचटन (बी) पी एफ	,,	,,	—	,,	65.00	भाग
4.	जारगढ़	,,	,,	52	,,	270.00	भाग
5.	सैंदूप	,,	,,	53	,,	5.00	भाग

कुल क्षेत्र : 3420.00 एकड़ (लगभग)

या : 1384.00 हैक्टर (लगभग)

सीमा वर्णन :

क-ख रेखा, मोरवाई कलां ग्राम से होकर जाती है (जो कोयला अधिनियम की धारा 9(1) के अधीन होरीलोंग ब्लाक की भागतः सम्मिलित सीमा बनाती है) और बिन्दु "ख" पर मिलती है।

ख-ग रेखा, मोरवाई कलां और मोरवाई खुर्द ग्रामों से होकर जाती है और बिन्दु "ग" पर मिलती है।

ग-घ रेखा, मोरवाई खुर्द और मोरवाई कलां ग्रामों से होकर जाती है और और बिन्दु "घ" पर मिलती है।

घ-ङ रेखा, मोरवाई कलां, जारगढ़ और सैंदूप ग्रामों से होकर जाती है और बिन्दु "ङ" पर मिलती है।

ङ-च-छ-ज रेखा, सैंदूप, जारगढ़, बेरी चटन (बी) पी एफ और मोरवाई कलां से होकर जाती है (जो कोयला अधिनियम की धारा 9(1) के अधीन मचेरकुंड ब्लाक की भागतः सम्मिलित सीमा बनाती है) और बिन्दु "ज" पर मिलती है।

ज-क रेखा बेरीचटन (ए) आरक्षित वन और मोरवाई कलां ग्रामों की भागतः सम्मिलित सीमा से होकर जाती है (जो हुसार कोयला खान की सीमा की भागतः सम्मिलित सीमा है) और आरंभिक बिन्दु "क" पर मिलती है।

समय सिंह, अवर सचिव

[फा सं 19/83-सी एल/सी ए]

S.O. 3751—Whereas it appears to the Central Government that coal is likely to be obtained from the land in the locality mentioned in the Schedule hereto annexed;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957 (20 of 1957), the Central Government hereby gives notice of its intention to prospect for coal therein;

The plan No. Rev/12/83 dated 23-2-83 of the area covered by the notification can be inspected at the Office of the Central Coalfields Limited (Revenue Section), Darbhanga House, Ranchi or the office of the Deputy Commissioner, Palamau (Bihar) or at the office of the Coal Controller, 1, Council House Street, Calcutta.

All persons interested in the land covered by this notification shall deliver all maps, charts and other documents referred to in sub-section (7) of section 13 of the said Act to the Revenue Officer, Central Coalfields Limited, Darbhanga House, Ranchi within 90 days from the date of the publication of this notification in the Official Gazette.

SCHEDULE

Medeni Rai Block

(Hutar Coalfield)

(Showing land notified for prospecting)

Serial number	Village	Anchal	Revenue	Thana number	District	Area	Remarks
1.	Morwai Khurd	Barwadih	Latehar	35	Palamau	450.00	Part
2.	Morwai Kalan	,,	,,	39	,,	2630.00	,,
3.	Barichatan (B) P.F.	,,	,,	—	,,	65.00	,,
4.	Jargarh	,,	,,	52	,,	270.00	,,
5.	Saidup	,,	,,	53	,,	5.00	,,

Total Area : 3420.00 acres (approximately)

or 1384.00 hectares (approximately)

Boundary description :

A—B line passes through village Morwai Kalan (which form part common boundary of Horilong block U/S 9(1) of the Coal Act and meets at point 'B'

B—C line passes through villages Morwai Kalan and Morwai Khurd and meets at point 'C'

C—D line passes through villages MorwaiKhurd and Morwai Kalan and meets at point 'D'

D—E line passes through villages Morwai Kalan, Jargarh and Saidup and meets at point 'E'

E-F-G-H lines pass through villages Saldup, Jargarh, Barichatan and Morwai Kalan (which forms part common boundary of Macherkunda Block U/s 9(1) of Coal Act and meet at point 'H'

H—A line passes part common boundary of village Barichatan (A) reserved forest and Morwai Kalan (which forms part common boundary of Hutar Colliery boundary) and meets at starting point 'A'

[No 19/1983-CL/CA]

SAMAY SINGH, Under Secy.

दिल्ली, 20 अक्तूबर, 1986

का.आ. 3752 :—मैसर्स सेशासाई पेपर एण्ड बोर्ड लि., पालीपालियम, इरोड-638007 सालेम जिला (टी.एन. 4028) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का सन्दाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की जीवन जोता स्कीम को सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में जो फायदा उठा रहे हैं वे ऐसे कर्मचारियों को उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो उन्हें कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन अनुदेय हैं;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 4672 तारीख 28-11-1983 के अनुसरण में और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए उक्त स्थापन को 24-12-1986 से तीन वर्ष की अवधि के लिए जिसमें 23-12-1989 भी सम्मिलित है, उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजन प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त तामिलनाडु को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर सन्दाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खण्ड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का सन्दाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों का सन्दाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों को बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम, के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजक किया जाता है तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को सन्दत्त करेगा ।

6. यदि सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाये जाते हैं, तो, नियोजक उक्त स्कीम से अधीन कर्मचारियों की उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम के किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन सन्देय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में सन्देय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का सन्दाय करेगा ।

8. सामूहिक स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्यनिधि आयुक्त तमिलनाडु के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम को उन सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है, अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं तो यह छूट रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा नियत तारीख के भीतर प्रीमियम का सन्दाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के सन्दाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में, उन मृत सदस्यों के नाम-निर्देशियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अंतर्गत होते, बीमा फायदों के सन्दाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर भारतीय जीवन बीमा निगम बीमाकृत राशि के हकदार नामनिर्देशिती/विधिक वारिसों को इस राशि का सन्दाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में हर प्रकार से पूर्व नामे की प्राप्ति के एक मास के भीतर सुनिश्चित करेंगे ।

[संख्या एस-35014/273/83-पी.एफ. 2/एस एस-2]

New Delhi, the 20th October 1986

S.O. 3752.—Whereas Messrs Seshasayee Paper and Boards Limited Pallipalayam, Erode-638007 Salem District (TN) 4028) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act).

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution of payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of Section 17 of the said Act and in Continuation of the notification of the Government of India in the Ministry of Labour, S.O. 4672 dated the 28-11-1983 and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a further period of three years with effect from 24-12-1986 upto and inclusive of the 23-12-1989.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Tamil Nadu and maintain such accounts and provide such facilities for inspection as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of Section 17 of the said Act within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employees, who is already a member of the Employees' Provident Fund of an establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Nowithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Tamil Nadu and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects.

[No. S-35014/273/83-PF. II-SS. II]

का. आ. 3753.—मैसर्स-दी जामनगर जिला को-आपरेटिव बैंक लि. साहाकार भवन, रणजीत रोड, जामनगर (जी. जे/4658) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की जीवन बीमा स्कीम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में जो फायदा उठा रहे हैं वे ऐसे कर्मचारियों को उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो उन्हें कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन अनुज्ञेय हैं;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ. 4044 तारीख 5-10-1983 के अनुसरण में और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए उक्त स्थापन को, 29-10-131 से तीन वर्ष की अवधि के लिए जिसमें 28-10-1989 भी सम्मिलित है, उक्त स्कीम के सभी उपबंधों के प्रवर्तन से छूट देती है।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त गुजरात को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार समय-समय पर निर्दिष्ट करें।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप-धारा (3क) के खंड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करें।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की की प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा।

6. यदि सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाये जाते हैं तो, नियोजक उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नामनिर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा।

8. सामूहिक स्कीम के उपबंधों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त गुजरात के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है, अधीन नहीं रह जाते हैं, या

इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा नियत तारीख के भीतर प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्ययगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में, उन मृत सदस्यों के नामनिर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह, छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर भारतीय जीवन बीमा निगम, बीमाकृत राशि के हकदार नामनिर्देशिती/विधिक वारिसों को उस राशि का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में हर प्रकार से पूर्ण दावे की प्राप्ति के एक मास के भीतर सुनिश्चित करेगा।

[संख्या एस-35014/185/83-पी.एफ-2/एस. एस-2]

S.O. 3753.—Whereas Messrs The Jamnagar District Co-operative Bank Limited, Sahakar Bhavan, Ranjit Road, Jamanagar (GJ|4658) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act).

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution of payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of Section 17 of the said Act and in Continuation of the notification of the Government of India in the Ministry of Labour, S.O. 4044 dated the 5-10-1983 and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a further period of three years with effect from 29-10-1986 upto and inclusive of the 28-10-1989.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Gujarat and maintain such accounts and provide such facilities for inspection as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of Section 17 of the said Act within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employees who is already a member of the Employees' Provident Fund of an establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6 The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding any thing contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir[nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Gujarat and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point, of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee| legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects.

[No. S-35014[185|83-PF. II-SS II]

का. आ. 3754.—मैसर्स सुप्रीम रबर रिक्लेमर्स प्राइवेट लि., कारगंलपेड़ी, मंगलौर-3, (के.एन/7751) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2-क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी किसी पृथक् अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की जीवन बीमा स्कीम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में जो फायदा उठा रहे हैं वे ऐसे कर्मचारियों को उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो उन्हें कर्मचारी

निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन अनुज्ञेय हैं;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ. 3963 तारीख 1-10-83 के अनुसरण में और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए उक्त स्थापन को, 22-10-86 से तीन वर्ष की अवधि के लिए जिसमें 21-10-89 भी सम्मिलित है, उक्त स्कीम के सभी उपबंधों के प्रवर्तन से छूट देती है।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजन प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, कर्नाटक को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप-धारा (3क) के खंड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा।

6. यदि सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाये जाते हैं तो, नियोजक उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नामनिर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा।

8. सामूहिक स्कीम के उपबंधों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त कर्नाटका के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है, अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा नियत तारीख के भीतर प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में, उन मृत सदस्यों के नामनिर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह, छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर भारतीय जीवन बीमा निगम, बीमाकृत राशि के हकदार नामनिर्देशिती/विधिक वारिसों को उस राशि का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में हर प्रकार से पूर्ण दावे की प्राप्ति के एक मास के भीतर सुनिश्चित करेगा।

[संख्या एस-35014/155/83-पी.एफ-2/एस.एस-2]

S.O. 3754.—Whereas Messrs. Supreme Rubber Reclaimers Private Limited, Karangal Pady, Mangalore-3(KN|7751) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act).

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establisnment are, without making any separate contribution of payment of premiums, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme):

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of Section 17 of the said Act and in Continuation of the notification of the Government of India in the Ministry of Labour, S.O. 3963 dated the 1-10-1983 and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto the Central Government hereby

exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a further period of three years with effect from 22-10-1986 upto and inclusive of the 21-10-1989.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Karnataka and maintain such accounts and provide such facilities for inspection as the Central Government may direct from time to time

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of Section 17 of the said Act within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee who is already a member of the Employees' Provident Fund of an establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Karnataka and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/ legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects.

[No. S-35014/155/83-PF. II-SS. II]

का. आ. 3755.—मैसर्स मैटल बोक्स इन्डिया लि०, बोर्ड हाऊस-59 सी, चौरंगी रोड़, कलकत्ता-700020 (डब्ल्यू. बी/7931), (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी किसी पृथक् अभिदाय या प्रीमियम का सन्दाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की जीवन बीमा स्कीम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में जो फायदा उठा रहे हैं वे ऐसे कर्मचारियों को उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो उन्हें कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन अनुज्ञेय है ;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का० आ० 2003 तारीख 14-4-1983 के अनुसरण में और इससे उपाबद्ध अनसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए उक्त स्थापन को, 30-4-86 से तीन वर्ष की अवधि के लिए जिसमें 29-4-89 भी सम्मिलित है, उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है ।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, पश्चिम बंगाल को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर सन्दाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप-धारा (3क) के खण्ड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का सन्दाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों का सन्दाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति

तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो नियोजक सामूहिक बीमा-स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को सन्दत्त करेगा ।

6. यदि सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाये जाते हैं तो, नियोजक उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनकूल हो, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन सन्देय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में सन्देय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नामनिर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का सन्दाय करेगा ।

8. सामूहिक स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त पश्चिम बंगाल के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है, अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा नियत तारीख के भीतर प्रीमियम का सन्दाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो, छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के सन्दाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में, उन मृत सदस्यों के नामनिर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के सन्दाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की होने पर भारतीय जीवन बीमा निगम, बीमाकृत राशि के हकदार नामनिर्देशिती/विधिक वारिसों को उस राशि का सन्दाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में हर प्रकार से पूर्ण दावे की प्राप्ति के एक मास के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

[संख्या एस-35014/60/83-पी एफ-2/एस एस-2]

S.O. 3755.—Whereas Messrs Metal Box India Limited, Barlow House, 59C, Chowringhee Road, Calcutta-700020 (WB|7931) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution of payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of Section 17 of the said Act and in Continuation of the Notification of the Government of India in the Ministry of Labour, S.O. 2003 dated the 14-4-1983 and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a further period of three years with effect from 30-4-1986 upto and inclusive of the 29-4-1989.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, West Bengal and maintain such accounts and provide such facilities for inspection as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of Section 17 of the said Act within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employees who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding any thing contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under

the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, West Bengal and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point. of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/ legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects.

[No. S-35014/60/83-PF. II-SS. III]

का.आ. 3756.—मैसर्स इन्डियन आक्सीजन लि०, 7/1 बैथ्यानाथनम मुलादी गली तोन्दिमारपैर, मद्रास-600081 (टी एन/825) और इन्डियन आक्सीजन लि० 13 इन्डस्ट्रियल एस्टेट, मद्रास-58 (टी एन/4014), (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का सन्दाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की जीवन बीमा स्कीम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदा उठा रहे हैं व ऐसे कर्मचारियों को जो उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो उन्हें कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन अनुज्ञेय हैं;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का० आ० 1335 तारीख 10-2-1983 के अनुसरण में और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए उक्त स्थापन को, 26-2-1986 से तीन वर्ष की अवधि के लिए जिसमें 25-2-1989 भी सम्मिलित है, उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है ।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजन प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त तमिल नाडु को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर सन्दाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप-धारा (3क) के खण्ड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना बीमा प्रीमियम का सन्दाय लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों का सन्दाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को सन्दत्त करेगा ।

6. यदि सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाये जाते हैं तो, नियोजक उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिस से कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन सन्देय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में सन्देय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नामनिर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का सन्दाय करेगा ।

8. सामूहिक स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त तमिल नाडु के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना

हो वहां, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है, अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा नियत तारीख के भीतर प्रीमियम का सन्दाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्ययगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के सन्दाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में, उन मृत सदस्यों के नामनिर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह, छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के सन्दाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर भारतीय जीवन बीमा निगम, बीमाकृत राशि के हकदार नामनिर्देशिती/विधिक वारिसों को उस राशि का सन्दाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में हर प्रकार से पूर्ण दावे की प्राप्ति के एक मास के भीतर सुनिश्चित करेगा।

[संख्या एस-35014/68/82-पी एफ-2/एस एस-2]

S.O. 3756.—Whereas Messrs Indian Oxygen Limited 7/1 Vaithianathan Tondiarpat, Madras-600081 (TN/825) and India Oxygen Limited, 13, Industrial Estate, Madras-58 (TN/4014) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act).

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution of payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under, the Employees Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of Section 17 of the said Act and in continuation of the notification of the Government of India in the Ministry of Labour, S.O. 1335 dated the 10-2-1983 and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a further period of three years with effect from 26-2-1986 upto and inclusive of the 25-2-1989.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Tamil Nadu and maintain such accounts and provide such facilities for inspection as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of Section 17 of the said Act within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishments, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Tamil Nadu and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner, shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects.

[No. S-35014/68/82-PF. II-SS-III

नई दिल्ली, 21 अक्तूबर, 1986

का० आ० 3757—मैसर्स एस० के० एम० पोल्ट्री सर्विस, मार्किटिंग सैन्टर, एडमन-स्ट्रेटिव आफिस, 49/सी, गांधी जी रोड, पोस्ट बोक्स नं 415, इरोड-638002 (टी०एन०/10725) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिये जाने के लिये आवेदन किया है ।

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का सन्दाय किये बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की जीवन बीमा स्कीम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में जो फायदा उठा रहे हैं वे ऐसे कर्मचारियों को उन फायदों से अधिक अनुकूल है जो उन्हें कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन अनुज्ञेय है;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का०आ० 3403 तारीख 30-7-1983 के अनुसरण में और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए उक्त स्थापन को, 27-8-1989 से तीन वर्ष की अवधि के लिये जिसमें 26-8-1989 भी सम्मिलित है, उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है ।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजन प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त तामिलनाडु को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिये ऐसी सुविधायें प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर सन्दाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप-धारा (3क) के खण्ड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का सन्दाय लेखाओं का अन्तरण निरीक्षण प्रभारों का सन्दाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जायेगा।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाये, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को सन्दत्त करेगा।

6. यदि सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाये जाते हैं, तो, नियोजक उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिये सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन सन्देय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में सन्देय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नामनिर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का सन्दाय करेगा ।

8. सामूहिक स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त तामिलनाडु के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जायगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है, अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा नियत तारीख के भीतर प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्ययगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के सन्दाय में किये गये किसी व्यतिक्रम की दशा में, उन मृत सदस्यों के नामनिर्देशितियों या विधिक वारिसों की जो यदि यह, छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के सन्दाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर भारतीय जीवन बीमा निगम, बीमाकृत राशि के हकदार नामनिर्देशिती/विधिक वारिसों को उस राशि का सन्दाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में हर प्रकार से पूर्ण दावे की प्राप्ति के एक मास के भीतर सुनिश्चित करेगा।

[संख्या एस-35014/111/83-पी०एफ०-2/एस एस-2]

New Delhi, the 21st October, 1986

S.O. 3757.—Whereas Messrs SKM Poultry Services, Marketing Centres Administrative Office 49/C, Gandhiji Road, Post Box No. 415, Erode-638002 (TN/10725) (hereinafter referred to the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident

Funds and Miscellaneous Provisions Act 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act).

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of Section 17 of the said Act and in continuation of the notification of the Government of India in the Ministry of Labour, S.O. 3403 dated the 30-7-1983 and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a further period of three years with effect from 27-8-1986 upto and inclusive of the 26-8-1989.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Tamil Nadu and maintain such accounts and provide such facilities for inspection as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of Section 17 of the said Act within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishments a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Tamil Nadu and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner, shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects.

[No. S-35014/111/83-PF. II-SS-II]

का.आ. 3758:—मैसर्स पंजाब ट्रैक्टर लि०, फेस-4, साहिबाबाद अजीत सिंह नगर, रोपड़ (पंजाब) (पी एन / 3095) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952(1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिये जाने के आवेदन किया है ।

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिये ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय है।

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 2क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिये उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, पंजाब को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिये ऐसी सुविधायें प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 3क के खण्ड क के अधीन समय समय पर निर्दिष्ट करे।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जायेगा।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्म-

चारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापन के सूचनापट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि किए जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हो जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय है।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नामनिर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, पंजाब के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जायेगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश स्थापन के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाता है या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश नियोजक उस नियत तारीख के भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो, छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो, उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते । बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के एक मास के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

[संख्या एस-35014/250/86-एस एस -2]

S.O. 3758.—Whereas Messrs Punjab Tractors Limited, Phase-IV, Sahibzada Ajit Singh Nagar, Ropar (Punjab (PN/3095) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees that the benefits admissible under the Employees Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Punjab and maintain such accounts and provide such facilities for inspection as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of Section 17 of the said Act within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Punjab and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner, shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects.

[No. S-35014/250/86-SS-II]

का. आ. 3759.—मैसर्स मोहन मेकिंग लि. (जो पहले मोहन मेकिंग इन्डिया के नाम से जाना जाता था) सोलन ब्रेवरी, पोस्ट आफिस-शिमला हिल्स (हि. प्र.) (एच. एल./4) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 17) जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिये जाने के लिए आवेदन किया है।

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किये बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं।

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा-2क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, पंजाब को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधायें प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा-17 की उपधारा 3-क के खण्ड-क के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाये, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापन के सूचनापट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाये जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, पंजाब के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश स्थापन के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं तो यह छूट रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश नियोजक उस नियत तारीख के भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो, छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किये गये किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो, उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते। बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के एक मास के भीतर सुनिश्चित करेगा।

[संख्या एस-35014/251/86-एस एस-2]

S.O. 3759.—Whereas Messrs Mohan Meaking Limited, (Formerly known as Mohan Meaking India) Solan Brewery, P.O. Shimla Hills (H.P.) (HL/4) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act).

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution of payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life

Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Punjab and maintain such accounts and provide such facilities for inspection as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of Section 17 of the said Act within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts submission of returns, payment of insurance premium, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishments, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8 No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Punjab and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner, shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects.

[No. S-35014/251/86-SS-II]

का.आ. 3760.—मैसर्स-बंगलौर को-आपरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर्स सोसाएटीज, यूनियन, हुचर रोड़, बंगलौर-560029 (के. एन./6737) (जिसे, इसमें इसके पश्चात उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध, अधिनियम 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की जीवन बीमा स्कीम को सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में जो फायदा उठा रहे हैं वे ऐसे कर्मचारियों को उन फायदों से अधिक अनुकूल है जो उन्हें कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन अनुज्ञेय हैं;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 4659, तारीख 25-11-82 के अनुसरण में और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए उक्त स्थापन को, 24-12-1986 से तीन वर्ष की अवधि के लिए जिसमें 23-12-1989 भी सम्मिलित है, उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजन प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त कर्नाटक को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार समय समय पर निर्दिष्ट करे।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खण्ड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा।

6. यदि सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाये जाते हैं तो, नियोजक उक्त स्कीमके अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूपसे वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे के अधीन अनुज्ञेय हैं।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम

है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नामनिर्देशिती की प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तरण के बराबर रकम का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त कर्नाटका के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है, अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा नियत तारीख के भीतर प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में, उन मृत सदस्यों के नामनिर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह, छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर भारतीय जीवन बीमा निगम, बीमाकृत राशि के हकदार नामनिर्देशिती/विधिक वारिसों को उस राशि का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में हर प्रकार से पूर्ण दावे की प्राप्ति के एक मास के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

[संख्या एस-35014/260/83/पी. एफ.-2/एस. एस.-2]

S.O. 3760.—Whereas Messrs Bangalore Co-operative Milk Producers Union, Hosur Road, Bangalore-560029 (KN/6737) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act).

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution of payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of Section 17 of the said Act and in continuation of the notification of the Government of India in the Ministry of Labour, S.O. 4659 dated the 25-11-1983 and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a further period of three years with effect from 24-12-1986 upto and inclusive of the 23-12-1989.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund commissioner, Karnataka and maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of Section 17 of the said Act within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employees, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India,

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Karnataka and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the members covered under the Subscription Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects.

[No. S-35014/260/83-PF. II-SS-II]

नई दिल्ली, 22 अक्तूबर, 1986

का.आ. 3761.—मैसर्स पंजाब इलैक्ट्रोनिक कम्पोनैन्टस लि., एस. ए. एस. नगर रोपड़, पंजाब (पी. एन./5104) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध 1952 (1952 का 19) जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है (की धारा 17 की उपधारा 2क) के अधीन छूट दिये जाने के लिए आवेदन किया है ।

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किये बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा-(2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त पंजाब को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधायें प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा-17 की उपधारा (3क) के खंड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा दिया जाएगा।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाये, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापन के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाये जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि किये जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, पंजाब के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश स्थापन के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है, अधीन नहीं रह जाते हैं या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं तो, यह रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश नियोजक उस नियत तारीख के भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है और पॉलिसी को व्ययगत हो जाने दिया जाता है तो, छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किये गये किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो, उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते। बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के एक मास के भीतर सुनिश्चित करेगा।

[संख्या एस-35014/249/86/-एस. एस.-2]

New Delhi, the 22nd October, 1986

S.O. 3761.—Whereas Messrs Punjab Electronic Components Limited, SAS Nagar, Ropar, Punjab, (PN/5104) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act).

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of Section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund commissioner, Punjab and maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of Section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employees, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment, the employer shall immediately enrol him

as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Punjab and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects.

[No. S-35014/249/86-SS-II]

का.आ. 3762.—कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 1 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा पहली नवम्बर, 1986 को उस तारीख के रूप में नियत करती है, जिसको उक्त अधिनियम के अध्याय 4 (धारा 44 और 45 के सिवाय जो पहले ही प्रवृत्त की जा चुकी है) और अध्याय 5 और 6 (धारा 76 की उपधारा (1) और धारा 77, 78, 79 और 81 के सिवाय जो पहले ही प्रवृत्त की जा चुकी है) के उपबन्ध आंध्र प्रदेश राज्य के निम्नलिखित क्षेत्र में प्रवृत्त होंगे, अर्थात् :—

"जिला वारंगल में वारंगल राजस्व मण्डल के अन्तर्गत गोरेकुण्टा राजस्व ग्राम, घीसकोण्डा राजस्व मण्डल के अन्तर्गत स्थम्बाम्पल्ली, प्रगति औद्योगिक सम्पदा, गोरेकुण्टा और वारंगल के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र ।"

[सं. एस-38013/35/86-एस. एस-1]

S.O. 3762.—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 1 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), the Central Government hereby appoints the First November, 1986 as the date on which the provisions of Chapter IV (except sections 44 and 45 which have already been brought into force) and Chapters V and VI (except sub-section (1) of section 76 and Sections 77, 78, 79 and 81 which have already been brought into force] of the said Act shall come into force in the following areas in the State of Andhra Pradesh, namely :—

"The area within the revenue village of Gorrekunta under Warangal revenue Mandal, Sthambampally, Pragathi Industrial Estate, Gorrekunta and Warangal under Gheeskonda revenue mandal in Warangal District."

[No. S-38013/35/86-SS-I]

नई दिल्ली, 23 अक्तूबर, 1986

का.आ. 3763.—मैसर्स-गैस्ट कीन विलियम्स लि., 76, पैन्थोन रोड, एग्मोरे, मद्रास-600 008 (टी एन/3768) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है ;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की जीवन बीमा स्कीम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में जो फायदा उठा रहे हैं वे ऐसे कर्मचारियों को उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो उन्हें कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन अनुज्ञेय हैं ;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 3386 तारीख 30-8-82 के अनुसरण में और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए उक्त स्थापन को, 25-9-1985 से तीन वर्ष की अवधि के लिए जिसमें 24-9-1988 भी सम्मिलित है, उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है ।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, तमिलनाडु को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप-धारा (3क) के खण्ड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा ।

4. नियोजक केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6. यदि सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाये जाते हैं तो, नियोजक उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा

जाते कि कर्मचारियों के लिए, सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन सन्देय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में सन्देय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस नामनिर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का सन्दाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, तमिलनाडु के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल, प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है, अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा नियत तारीख के भीतर प्रीमियम का संन्दाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के सन्दाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में, उन मृत सदस्यों के नामनिर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह, छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के सन्दाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर भारतीय जीवन बीमा निगम, बीमाकृत राशि के हकदार नामनिर्देशिती/विधिक वारिसों को उस राशि का सन्दाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में हर प्रकार से पूर्ण दावे की प्राप्ति के एक मास के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

[संख्या एस-35014/74/82/पी. एफ2/एस एस-2]

New Delhi, the 23rd October, 1986

S.O. 3763.—Whereas Messrs Guest Keen Williams Limited 76, Pantheon Road, Egmore, Madras-600008 (TN/3768) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act).

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are without making any separate contribution of payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of Section 17 of the said Act and in Continuation of the notification of the Government of India in the Ministry of Labour, S.O. 3386 dated the 30-8-1982 and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a further period of three years with effect from 25-9-1985 upto and inclusive of the 24-9-1988.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Tamil Nadu and maintain such accounts and provide such facilities for inspection as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of Section 17 of the said Act within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishments, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available ot the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Premium etc. within the due date as fixed by the Life Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that the employees than the benefits admissible under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Tamil Nadu and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the 7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption shall be that of the employer.

12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects.

[No. S-35014/74/82-PF. II-SS.II]

का.आ. 3764:--मैसर्स रामरतन प्राइवेट लि., न्यू विनोद सिल्क मिल्स एस्टेट, चक्रावर्ती अशोक रोड, अशोक नगर, कान्डीवली, बम्बई-400101 (एम एच/11551) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन

कहा गया है) के कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है ;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का सन्दाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की जीवन बीमा स्कीम को सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में जो फायदा उठा रहे हैं वे ऐसे कर्मचारियों को उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो उन्हें कर्मचारी निक्षेप संबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन अनुज्ञेय हैं ;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ. 1334 तारीख 28-12-1982 के अनुसरण में और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए उक्त स्थापन को, 26-2-1986 से तीन वर्ष की अवधि के लिए जिसमें 25-2-1989 भी सम्मिलित है, उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजन प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त महाराष्ट्र को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर सन्दाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप-धारा (3क) के खण्ड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का सन्दाय लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों का सन्दाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को सन्दत्त करेगा ।

6. यदि सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाये जाते हैं तो, नियोजक उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन सन्देय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में सन्देय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नामनिर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का सन्दाय करेगा ।

8. सामूहिक स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त महाराष्ट्र के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है, अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश नियोजक भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा नियत तारीख के भीतर प्रीमियम का सन्दाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के सन्दाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में, उन मृत सदस्यों के नामनिर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के सन्दाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर भारतीय जीवन बीमा निगम, बीमाकृत राशि के हकदार निर्देशिती/विधिक वारिसों को उस राशि का सन्दाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में हर प्रकार से पूर्ण दावे की प्राप्ति के एक मास के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

[संख्या एस-35014/470/82/पी. एफ-2/एस. एस 2]
ए. के. भट्टाराई, अवर सचिव

S.O. 3764.—Whereas Messrs Ramanlal Private Limited New Vinod Silk Mills Estate, Chakravarti Ashok Road, Ashom Nagar, Kandivli (East Bombay-400101) (MH|11551) (hereinafter referred to as the said estaolishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act).

And whereas the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution of payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of Section 17 of the said Act and in Continuation of the notification of the Government of India in the Ministry of Labour, S.O. 1334 dated the 28-12-1982 and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a further period of three years with effect from 26-2-1986 upto and inclusive of the 25-2-1989.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner Maharashtra and maintain such accounts and provide such facilities for inspection as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of Section 17 of the said Act within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishments, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employees, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Maharashtra and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where for any reason, the employer fails to pay the premium etc. Within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects.

[No. S-35014/470/82-PF.II-SS.III]

A. K. BHATTARAI, Under Secy.

नई दिल्ली, 20 अक्तूबर, 1986

का.आ. 3765—औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार, देना बैंक के प्रबंधतंत्र से संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में औद्योगिक अधिकरण बंगलौर के पंचाट को प्रकाशित करती है जो केन्द्रीय सरकार को 6-10-86 को प्राप्त हुआ था।

977 GI/86—10

New Delhi, the 20th October, 1986

S.O. 3765.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Industrial Tribunal, Bangalore as shown in the Annexure in the Industrial dispute between the employers in relation to the Dena Bank and their workmen, which was received by the Central Government on the 6th October, 1986.

BEFORE THE INDUSTRIAL TRIBUNAL IN KARNATAKA, BANGALORE

Dated this the 25th day of September 1986

PRESENT :

Sri R. Ramakrishna, B.A.B.L., Presiding Officer.
Central Reference No. 4 of 1985

I PARTY

The President, Dena Bank Employees Union, C/o Dena Bank, Kempegowda Road, Bangalore-560009.

Vs

II PARTY

The Regional Manager, Dena Bank Regional Office, 103, Mungambakkam High Road, Hotel Ganapeth Building, Madras-34.

APPEARANCES :

For the I Party :—Sri N. Sampath Kumar, Advocate, Bangalore.

For the II Party :—Sri K. R. D. Karanth, Advocate Bangalore.

REFERENCE :

(Government Order No. L-12011/46/84-D.II(A) dated 13th February, 1985)

AWARD

The Central Government in exercise of the power conferred by clause (d) of sub-section (1) of Section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947, shortly called Act, has referred the above dispute for adjudication as per the Schedule below :—

SCHEDULE

"Whether the action of the management of Dena Bank, Madras Regional in terminating the services of Shri Muniyellappa, budlee sub-staff from April, 1984 and not considering him for further employment while engaging fresh hand is justified ? If not, to what relief is the workman concerned entitled ?"

2. The I Party being represented by the President of the Union has filed his claim statement contending that he is the member of the I Party Union and he was appointed as sub-staff in the year 1975 and posted to work in the II Party-Bank at Jigani Branch, Anekal Taluq, Bangalore District. He has discharged his duties from 1975 to March 1984 and he was not allowed to work with effect from April 1984.

3. He has further contended that during the above said period he was working as a Delivery Peon and his nature of duties was that of unskilled office work. He was in continuous service from 1975 to April 1984 and during this period he has not been discharged or terminated from the service and he has been orally informed that his service had been terminated with effect from April 1984. He has further contended that his termination without an order in writing is illegal and even assuming that it would be a valid termination order without complying with the mandatory provisions of Section 25(F) of the I.D. Act is illegal, void and not binding on the workman.

4. He has further contended that he was duly qualified and eligible for regular appointment and though there were vacancies of sub-staff, the II Party deliberately did not appoint him on lame excuse that the II Party had to comply with the Employment Exchange Act, 1959 which is not applicable

to this workman. He has also alleged that the II Party has violated the provisions of 25(H) of the Act and further contended that he belonged to Schedule Caste and the II Party has not maintained the ratio of employment and that ever-since the date of termination he is unemployed. Hence he prayed for an award to set aside the order of termination with a direction for reinstatement with all back wages or alternatively to direct the II Party to re-appointment the workman against the clear vacancy of sub-staff.

5. The II Party in their counter statement have contended that they are a Banking Company incorporate under the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970. Its branch office at various places including in Anekal Taluk.

6. They have further contended the reference is incompetent as there is no industrial dispute between the parties and the claim of the I Party workman is not an industrial dispute as he is not an employee of the II Party and he is also not a member of the I Party. The I Party has no competence to represent this workman as the membership of the I Party is confined to only the employees who are appointed to posts in the Bank and under the standing instructions of the I Party the membership subscriptions is deducted from the salary and hence the workman is put to strict Rule of the allegations made by him.

7. They have further contended that Sri Muniyellappa was never appointed as Sub-staff employee nor he worked from 1975 to March 1981. They have further contended that Muniyellappa was only casually employed on specific days on daily wages as set out in the schedule and other than the above days he has not worked on any other days. No person can be appointed by a Branch Manager and the claim of the I Party is not substantiated by any letter of appointment by a competent authority nor any records of payment by monthly by the Bank. Casual employment on a daily wage basis does not make a person a staff member of the Bank. Therefore, there is no appointment as a subordinate staff nor there is no question of being discharged. To have the status of an employee he should be appointed by the competent authority.

8. They have further contended that the I Party as a responsible trade union cannot be allowed to make false and frivolous allegations. As per the satements this workman had totally worked for 249 days in the course of 10 years and never more than 55 days in any calendar year. The II Party as a Bank owned by the Government of India is bound by the directions according to which persons proposed by the Employment Exchange are to be considered for employment. The name of Muniyellappa was not sponsored and therefore he could not be appointed. Further, under the Bipartite Settlement dated 19-10-1966 temporary appointment caused by the absence of a workman shall never be extended for a period beyond 3 months. He was never in continuous service nor he can be deemed to be in service and there is no question of terminating his service. There is no violation of Section 25(H) and the averment of the workman that he has no income is also false. Sri Muniyellappa is a joint borrower with his father under D.R.I. Dairy loan and is a defaulter. The reply sent to the Assistant Commissioner of Labour should be read as part and parcel of this counter statement and the workman is not entitled to any relief claimed by him.

9. On the basis of the above pleadings, one additional issue has been framed as follows :—

(1) Whether the II Party proves that this reference is incompetent as contended in para 2 of their statement ?

10. Since the burden of proof as per the order of reference is placed on the II Party they have been directed to lead their evidence in support of contentions raised by them in their counter statement. Accordingly, they have examined the Branch Manager of Jigani Branch. The I Party workman in spite of several opportunities given by this Tribunal has not chosen to place any evidence on record and his advocate also remained absence, hence after hearing the arguments of the learned counsel for the II Party the dispute is posted to pass an award or 16-8-86 Ever thereafter the I Party workman and his counsel have not made any representation orally or by means of an application to re-open this case to give them an opportunity, hence I am compelled to pass an award on the basis of the materials placed by the parties.

11. The Branch Manager has deposed in his evidence that he is working in this capacity at Jigani Branch from June 1981 and before he took charge one Mr. R. S. Patil was the Manager. He has further deposed that Mr. Muniyellappa was not a staff member of their branch and they have maintained a register for staff members where the name of this workman has not been shown. The contributions to the Union will be deducted by the Bank in respect of staff members and they have not deducted any amount for Union contributions from this workman. This workman was working as a casual employee on daily wages and the number of days worked by him is as per the schedule enclosed to the claim statement. The payment to the casual employee will be made against a debit voucher and in respect of this workman there are 139 vouchers marked as Ext. M-1. In the month of April 1984 he has worked for about 6 days and received the payment and he has not been prevented to attend the work in that month and the payment by vouchers will be made only to casual employees.

12. The Branch Managers are not competent to make appointment and only the Regional Office make appointments. The payment for the sub-staff post will be made among the candidates sent by the Employment Exchange. Mr. Muniyellappa is a debtor to the Bank as he has borrowed Rs. 1800 along with his father who is owning agricultural land. No termination notice is issued to this workman and it is not possible to re-instate this workman.

13. The II Party have initially contended that it is not an Industrial Dispute and the Union have no competence to represent this workman as he was not the member of the said union. On this point, the II Party have elicited in the evidence of their witness that the procedure to pay the union subscription and the said procedure was not followed in the case of this workman. This Tirbunal initially placed the burden on the II Party to prove this respect of the matter. As a rebuttal evidence the I Party have not placed any material that they had the authority to represent this workman to raise this Industrial Dispute.

14. In Deepak Industries Ltd. Vs. State of West Bengal, (1975 Lab. I.C. 1153). Their Lordships of the Calcutta High Court, when such a question arose have held in paras 7, 10 of the judgement in the following words:

> "But when the dispute is espoused or sponsored by a union it seems to have been uniformly held that when the authority of the union is challenged by the employer it must be proved by production of material evidence before the Tribunal, to which such a dispute has been referred, that the union has been duly authorised either by a resolution of its members or otherwise that it has the authority to represent the workman whose cause it is espousing. Mere fact, tnat the said Union is registered under the Indian Trade Unions Act is not conclusive proof of its real existence or the authority to represent the workmen. Mere negotiations by some official of the Union with the employers for conciliation or executing certain documents on behalf of the workmen prior to the reference are not conclusive to give the alleged dispute character of an industrial dispute within S. 2(k). It is also not conclusive of the authority of the Union to represent the workman whose dispute it is alleged to be espousing before the Tribunal. It is immaterial whether the said Union is a gentral union of the workmen of a particular industry or it is a Union of the particular establishment relating to which the dispute has arisen between it and its workmen".

15. Admittedly, the I Party Union has not made any efforts to satisfy this Tribunal that it has got the authority to espouse the cause of this workman. Hence the additional issue is held in the affirmative.

16. Now coming to the main points of dispute, except Ext. W-1 dated 20-9-78 on which a temporary employment

was provided to this workman for a period of 19 days in the place of another temporary badli sepoy, there is no other material available before this Tribunal to find out the nature of employment offered to this workman prior to this date and after this date. There is also no dispute that this workman has not woked for a period of 240 days in any given year and the total number of working days is about 249 days spreading a span of 9 years. Since he has not been appointed as a temporary sub-staff against the vacancy of any permanent sub-staff, his claim cannot be considered under Clause 20.8 of the First Bipartite Settlement 1966. Since the above two conditions are not fulfilled by this workman there is absolutely no obligation on the part of the II Party to follow the procedure laid down in Chapter V (a) of the Industrial Disputes Act. Added to this, there is evidence by the II Party that any appointment to the post of sub-staff on a permanent basis the names of such persons should be sponsored by the Employment Exchange and they have no power to appoint the permanent sub-staff suo moto to fill up any vacancy. The nature of work provided to this workman is of a very casual nature which does not call for any efficiency test or the educational qualification. During the span of 9 years the work of this workman has been stopped on several occasions when there was no scope for giving any work to this workman. When such being the case, not considering him for employment from April 1984 does not amount to termination. The workman has not alleged any mala fides on the part of the II Party to discontinue his service and there is also no allegation that in his place some other person has been appointed to carry out the job which this workman was doing all these years. As I stated earlier this workman continuously remained absent when the case is posted for his evidence and his advocate also not evinced any interest for concluding this case. In view of these the materials placed by the management is sufficient to determine the points at dispute. Hence I pass the following Award:—

AWARD

The action of the management of Dena Bank, Madras Region in terminating the services of Sri Munivelappa, badli sub-staff from April 84 and not considering him for further employment while engaging fresh hand is justified. Parties shall bear their own costs.

(Dictated to the Stenographer, transcribed and typed by him and corrected by me).

R. RAMAKRISHNA, Presiding Officer

[No. L-12011/46/84-D.II(A)]

का.आ. 3766—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार, मगध ग्रामीण बैंक के प्रबंधतंत्र से सम्बद्ध नियोजकों और अनके कर्मकारों के बीच अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण नं. 2, धनबाद के पंचाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 6-10-86 को प्राप्त हुआ था ।

S.O. 3766.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal No. 2, Dhanbad as shown in the Annexure in the industrial dispute between the employers in relation to the Magadh Gramin Bank and their workmen, which was received by the Central Government on the 6th October, 1986.

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL (NO. 2) AT DHANBAD

Reference No. 124 of 1986

In the matter of industrial dispute under Section 10(1)(d) of the I.D. Act. 1947

PARTIES :

Employers in relation to the management of Magadh Gramin Bank and their workmen.

APPEARANCES :

On behalf of the workmen—Shri J. P. Singh, Advocate.
On behalf of the employers—None.

STATE : Bihar INDUSTRY : Banking.

Dated, Dhanbad, the 25th September, 1986

AWARD

The Government of India, Ministry of Labour in exercise of the powers conferred on them under Section 10(1)(d) of the I.D. Act, 1947 has referred the following dispute to this Tribunal for adjudication vide their Order No. L-12012/206/85-D.II(A), dated, the 6th March, 1986.

SCHEDULE

"Whether the action of the management of Magadh Gramin Bank, Gaya in dismissing Shri Ram Binod Sharma, Messenger from service with effect from 9-5-85 is justified? If not, to what relief is the workman entitled to?"

The sponsoring union filed their W.S. and document in the reference. Notice was sent to the management i.e. the Chairman, Magadh Gramin Bank, Gaya. The General Manager, Magadh Gramin Bank, Gaya filed appearance after receiving the notice sent by this Court and also filed W.S. on behalf of the management. Thereafter the management did not appear. When the management did not subsequently appear in the case the case was taken exparte for hearing.

The case of the workmen is that the concerned workman Shri Rambinod Sharma was appointed as Sweeper with effect from 20-12-77 in the Branch Office of Magadh Gramin Bank, Gaya. He had completed continuous service of more than 240 days in each calendar year. In 1981 he was promoted to the post of Messenger and even in that capacity he completed more than 240 days of attendance in a calendar year and he had obtained permanency in the job of Messenger. His services were terminated with effect from 9-5-85 without giving him any reason. The concerned workman and his union placed demand to the management to reinstate the concerned workman but it was not conceded. Thereafter an industrial dispute was raised before the ALC (C), Hazaribagh who held the conciliation proceeding which ended in failure and thereafter the present reference was made. The plea of the management before ALC(C) was that the concerned workman was appointed as a Sweeper and Messenger as casual labour and that his appointment was not on the regular basis. It was further stated that his services were not satisfactory as he was involved in an act of illegal gratification during the period he was working as a Messenger. The concerned workman therefore could not have been discharged summarily except on the ground of misconduct for which a domestic proceeding was necessary. The management had held no domestic enquiry against the concerned workman for the misconduct alleged against him and as such his termination was bad. On the above plea it has been prayed that the concerned workman is entitled to be reinstated in job with continuity of service and back wages with effect from 9-5-85 the date on which his services were terminated.

The case of the management is that the concerned workman was engaged for sweeping the rural office premises of Teusa branch of the Bank. It was a part time job. No appointment letter was issued to the concerned workman for working as a Messenger. There was no provision for appointment of a full time Messenger on regular basis in the Branch. The concerned workman had indulged in corrupt practices and as such the Bank was justified in terminating his services. The concerned workman was a casual part time labour and hence no domestic enquiry was required for the misconduct.

The only point for consideration is whether the dismissal of the concerned workman was justified with effect from 9-5-85.

The concerned workman Rambinod Sharma has examined himself as WW-1 and he has exhibited documents Ext. W-1 to W-6. WW-1 has stated that he was appointed as a sweeper in Magadh Gramin Bank on 20-12-77 and was posted in Teusa Branch of Magadh Gramin Bank on a monthly salary of Rs. 25 per month. He has further stated that on 11-12-82 he was promoted as Messenger and continued working as such till 9-5-85. He has stated that no reason was stated as to why his services were terminated. Ext. W-1 dated 11-12-82 is a letter by Shri R. K. Sharma,

Acting Manager of Teusa Branch of Magadh Gramin Bank, Gaya. It will appear from this letter that according to the letter of the Head Office dt. 7-12-82 and direction made therein the concerned workman Rambinod Sharma, Sweeper was apopinted as a Messenger from 9-12-82 on daily wage basis as casual labour. Ext. W-2 is a letter from the General Secretary of the Gramin Bank employees association, Gaya dt. 24-7 by which the General Secretary had demanded to reinstate the concerned workman. Ext. W-3 dt. 30-9-85 is a photo copy of the failure report submitted by the AL(C) Hazaribagh to the Secretary, Government of India, Ministry of Labour regarding the industrial dispute raised by the union on behalf of the concerned workman. Ext. W-4 dated 5-9-85 is the comment of the Chairman submitted before the ALC(C) Hazaribagh in the industrial dispute raised on behalf of the concerned workman. It will appear from para-2 of the comment that the management alleged that the work of the concerned workman was not satisfactory as he was involved in the act of illegal gratification during his working as Messenger. Ext. W-5 is a letter from the General Secretary to the management demanding the reinstatement of the concerned workman It appears therefore from the comment of the management in Ext. W-4 that there was allegation of taking illegal gratification against the concerned workman and he has been dismissed on that account without holding any domestic enquiry. As this allegation is an act of misconduct an enquiry was a must. As no enquiry was made into the allegation of misconduct the termination of the services of the concerned workman does not appear to be justified. The management therefor to reinstate the concerned workman from the date his services was terminated and to pay all back wages to him.

Award is passed accordingly.

I. N. SINHA, Presiding Officer
[No. L-12012/206/85-D.II(A)]

नई दिल्ली, 21 अक्तूबर, 1986

का.आ. 3767—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार यूनाइटेड कामर्शियल बैंक के प्रबंधतंत्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण जबलपुर के पंचाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 7-10-86 को प्राप्त हुआ था।

New Delhi, the 21st October, 1986

S.O. 3767.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal, Jabalpur as shown in the Annexure in the industrial dispute between the employers in relation to the United Commercial Bank and their workmen, which was received by the Central Government on the 7th October, 1986.

BEFORE SHRI V. S. YADAV, PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT, JABALPUR (M.P.)

Case No. CGIT/LC(R)(83)/1984

PARTIES :

Employers in relation to the management of United Commercial Bank, Nagpur and their workman, Shri M. B. Deshpande, represented by the UCO Bank Employees Union, C/o V.B.E.F. Behind Super Market, Sitabuldi, Nagpur-440012.

APPEARANCES :

For Union—Shri M. B. Deshpande, workman concerned.

For Management—Shri R. C. Srivastava, Advocate.

INDUSTRY : Bank DISTRICT : Nagpur (M.S.)

AWARD

Dated : September 22, 1986

This is a reference made by the Central Government vide Notification No. L-12012/59/84-D.II(A) dated 19th October, 1984, for adjudication of the following dispute :—

"Whether the action of the management of United Commercial Bank, Mount Road Extension Branch, Nagpur in refusing special leave to Shri M. P. Deshpande, Asstt. Secretary of Vidarbha Bank Employees Federation, Nagpur (A State Body of N.O.B.W.) in contravention of para 13.39 of Bipartite Settlement is justified. If not, to what relief the workman is entitled?"

2. On receipt of the reference order parties were noticed to file their pleadings, documents etc. But the parties took time to file the same. After the pleadings were filed the case was fixed for evidence of parties on 2-9-1986 on which parties appeared and sought adjournment on the ground that they are negotiating for a mutual settlement. Thereafter the case was fixed for filing settlement on 18-9-1986.

3. On 18-9-1986 parties filed an application incorporating therein the following terms of settlement and prayed that an award be recorded in terms of the settlement arrived at between them :—

"The management agreed that Shri M. B. Deshpande may be granted leave for total period of 7 days in 1983 i.e. from 24-3-83 to 30-3-83 or 31-3-83 to 6-4-83, as he is entitled to the maximum of 7 days per year only as his name was noticed by IBA as a Union Office bearer. It is submitted that Shri M. B. Deshpande is prepared to accept the management's offer."

The above settlement is duly signed by the workman concerned, Shri M. P. Deshpande and the maangement. I have gone through the above mentioned terms of settlement which appear to be fair, reasonable and in the interest of the workman and therefore, I record my award in terms of the settlement. No order as to costs.

V. S. YADAV, Presiding Officer
[No. L-12012/59/84-D.II(A)]

का.आ. 3768—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक के प्रबंधतंत्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण नई दिल्ली के पंचाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 8-10-86 को प्राप्त हुआ था।

S.O. 3768.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal, New Delhi as shown in the Annexure in the industrial dispute between the employers in relation to the Reserve Bank of India and their workmen, which was received by the Central Government on the 8th October, 1986.

BEFORE SHRI G. S. KALRA, PRESIDING OFFICER CENTRAL GOVT. INDUSTRIAL TRIBUNAL NEW DELHI

I.D. No. 63/80

In the mattter of dispute between

Shri L. N. Aggarwal and Shri Shyam Sunder-II through Joint Secretary,
Reserve Bank Employees' Association,
C/o. Reserve Bank of India,
6, Parliament Street,
New Delhi.

Versus

Reserve Bank of India,
New Delhi,

APPEARANCES :

Shri Harish Sharma—for the workmen.

Shri S. R. Hegde—for the Management.

AWARD

The Central Government in the Ministry of Labour vide its notification No. L-12011/50/79-D.IIA dated 2nd July, 1980 has referred the following industrial dispute to this Tribunal for adjudication.

"Whether the action of the management of Reserve Bank of India New Delhi in holding Shri L. N. Aggarwal, Clerk and Shri Shyam Sunder-II, Coin Note Examiner Grade II responsible for shortage of a ten rupee denomination note in a ten rupee denomination notes packet bearing seal Delhi dated 19th December, 1973 and calling upon them to deposit an amount of Rs. 5 each with the Reserve Bank is justified ? If not, to what relief are the workmen concerned entitled ?"

2. There is a cash department in the Reserve Bank of India at each Centre, which handles both cash notes i.e. notes received from the government currency printing press, as also soiled notes. In the present controversy we are concerned with the soiled notes. In the present case so far as the soiled notes are concerned, they may either be received at the public counters and/or at the large tender counters or in the note examination sections, direct from banks, railways and government departments. The soiled notes are also received back in the Reserve as remittance from currency chest. The Examiners and Recounters undertake detailed examination of these notes in accordance with the procedure set forth in paragraphs 24 to 29 of Chapter III of the Issue Department Manual Third Edition (hereinafter referred to as the Manual). The notes are then sorted out into reissueable notes i.e. notes which can be put back into circulation; and non-issuable notes i.e. notes which cannot be put back into circulation. The packets are made up of 100 pieces each. The Examiner puts labels on the packets in form CD-25 in case of reissuable notes and in form CD-26 in the case of non-issuable notes. The label is placed over the first note in each packets and the packets are secured with suitable rubber bands. The labelled packets are then got wire stitched in the stitching machine in the immediate presence of the examiner who prepared the packet. The Examiner then places his seal on the last note in each packet in the case of reissuable and on the front of the first and on the back of the last note in each packet in the case of nonissuable notes. The packets are then issued for recounting by some other Cashier who is called the Recounter. It is the duty of the Recounter to verify that the number of pieces is one hundred in each packet. The packets so prepared then passed on to the Verificaton Section. Where they are verified in terms of Chapter VI of the Manual. The duty of the verification Section is to ensure that the Cash Department staff responsible for examination and cancellation of notes received in the cash department exercised the necessary checks as regards their genuineness admissibility for payment and the Section also exercised a detailed scrutiny of all notes passed for payment at the defective note counters and in the claim section to see that the instructions and the rules in this regard are duly observed by the officials concerned. The Verification of cancelled notes comprises of quality and quantity checks. The staff responsible for verifying the notes has to further check that the notes paid at the defective note counters and in the claim section have been made into packets separately from other notes cancelled in the ordinary course and have not been defaced; that the notes cancelled in the ordinary course have been defaced in the manner prescribed; that duly completed labels in Form CD26 or CD30 as the case may be are attached to all note packets and that the packets are properly stitched. The packets are verified by the checkers under the supervision of the verifier and the verified notes are further checked by the sub-accountant. He checks all notes paid at the defective note counters and in the claim section to see whether payments have been ordered in accordance with the standing instructions and the note Refund and a few of the packets selected at random are subjected to quantity check. The labels of defective note packets are stamped by him as 'Verified under his authentication. He has to select at random not less than 50 per cent of the packets from the remaining notes verified in the section and subject them to quality or quantity check as may be appropriate. The currency officer is also required to depute atleast once in every week duly authorised officials not below rank of staff Officer Gr. II to exercise surprise checks of atleast 250 packets out of the receipts in the section to be selected at random from the verified as well as relaxed portions. After verification the packets are then transferred to the cancelled note valt. At the stage of verification the notes are kept in the joint custody of two officers one of which is cash department official whereas after the process of the verification is over the verified notes are transferred to the single custody of one sub Accountant.

3. In the present case Shri L. N. Aggarwal and Shri Shyam Sunder-II were employed as Clerk Gr. II and Coin Note Examiner Gr. II respectively and while attached to the defective/claims counter of the Reserve Bank of India New Delhi (hereinafter referred to as the Bank) on 19th December 1973 and they prepared a note packet of Rs. 10 denomination (hereinafter referred to as the packet) bearing seal No. Delhi/L dated 19-12-73 which was verified on 6-9-74 but at that time no shortage was noticed. It was also subjected to random check by the staff officer Verification Section who also did not find any deficiency in the packet. Sometime in January 1975 the Inspection Department of the Bank during the course of inspection detected that the packet contained 99 pieces instead of 100 pieces as indicated on the label thereon. The bank vide its memo dated 15-9-77 held S/Shri L. N. Aggarwal and Shyam Sunder-II as resopnsible for the shortage of one note in the packet and they were called upon to deposit Rs. 5 each to make good the deficiency.

4. The case of the workmen is that once the packet had been found to be correct during the course of verification as a result of detailed scrutiny and random checks provided in Chapter VI of the Manual the responsibility of the Cash Department ceased in accordance with the para 1 of Chapter VII of the Manual and hence the two workmen S/o Shri L. N. Aggarwal and Syam Sunder II cannot be held responsible for the deficiency detected by the Inspection Department. The workman further pointed out that during the process of verification the representatives of Cash Staff are also present but no representative of the cash department was asked to be present during the re-verification carried out by the inspection department. It was further pointed out that the packet was not prepared in the examination section but was a result of defective notes in claim section where some notes were passed for payment and some are rejected and had there been any discrepancy in respect of the notes in this packet on 19-12-73 when it was prepared there must have been corresponding discrepancy in the rejected notes which are also the subject matter of checks at various levels in the claim section itself. It also indicated that there was no discrepancy in the packet when it was prepared on 19-12-73 It was also pointed out that even on the basis of precedent available when some shortage was detected under the scheme of annual verification of balances in the bank it was only the verifying officials who were held responsible and not those who initially examined the note packets in question.

5. The case of the Management is that it is primary duty of the examiner to make a packet of 100 pieces and it is primary duty of the recounter to ensure that the packet contained 100 pieces. If it is established that a packet contained less than 100 pieces it would necessarily follow that both the examiner and the recounter were negligent in the discharge of their duties. The mere fact that this act of negligence was not detected by the verification section which may be due to human error would not absolve the examiners and the recounters of their primary responsibilities to the bank, as the packet was not broken open at any stage and as such remained in the same condition as it was when the packet was first prepared by the examiner concerned in the cash department. It was further pointed out that absolving the examiner and the recounter would have disasterous consequences for the bank as a official responsibility for ensur-

ing that each packet contained 100 pieces is on the Examiner and the Recounter and if these persons are not held responsible for their lapses and escape responsibility on the ground that the shortage was not detected by the Verification Section, apart from other things this would give room for abstraction of notes. As a matter of fact the packet has not been tempered with but was in fact with shortage of one note and it could have occurred only at the time when the packet was prepared and it could not have occurred later on. Therefore, the responsibility for the shortage has to be fixed on the examiner and the recounter and the Verification Section cannot be held responsible as they do not make note packets.

6. Para 1 of Chapter VII of the Manual is reproduced below for facility of reference :

> "The Cash Department ceases to be responsible for cancelled notes after the notes are verified in the manner prescribed in Chapter VI. The only exception is in regard to cancelled registered notes; since registered notes are subjected only to quantity check in the Verification Section, the Cash Department will continue to be responsible for their genuineness even after their verification. Subject to what is stated above, the responsibility for cancelled and verified notes, both registered and unregistered until their destruction inaccordance with the instructions contained hereunder, is that of the Sub-Accountant who holds immediate charge of the Cancelled Note Vault. The Sub Accountant is also responsible for the safe custody of indemnity bonds, letters of undertaking etc. executed by claimants in connection with payments made in Claims cases."

7. The note packet which is the subject of dispute in this case relates to cancelled unregistered notes. In respect of unregistered notes the para 1 of the Manual clearly states that the cash department ceases to be responsible after the notes are verified in the manner prescribed in Chapter VI and that the responsibility for such notes until their destruction is that of the Sub-Accountant who holds immediate charge of the cancelled note vault (CNV). The words of para 1 of the Manual are precise and unambiguous and leave no room for doubt. This para makes it clear unambiguously that after the cancelled notes have been verified in the manner prescribed in Chapter VI of the Manual the Cash Department ceases to be responsible. Not only that it further makes it clear that thereafter the responsibility for such notes until their destruction is that of the Sub-Accountant who holds immediate charge of the cancelled note Vault. One of the basic rules of interpretation of statutes is that if the words of a statute are precise and unambiguous, they must be accepted as declaring the express intentions of the Legislature. (C.I.T. Vs. Ajax Products Ltd., (1965) 1 SCR 700 AIR 1965 SC 1358, 1362). If the stand taken by the Management was to be accepted, it would mean adding a proviso to para 1 of Chapter VII of the Manual that notwithstanding what has been stated in para 1, the Cash Section shall continue to be responsible for the cancelled unregistered notes even after verification in the manner prescribed in Chapter VI if subsequently but before the destruction of those notes it is found that any packet is deficient and there is no evidence to suggest that the packet has been tampered with. Alternatively if the stand of the Management was to be accepted that the Cash Department continues to be responsible even after the cancelled notes have been verified in accordance with the procedure laid down in Chapter VI of the Manual, then provisions of para 1 of the Manual is rendered redundant. Both these propositions are repugnant to the Rules of Interpretation of Statute. It is a rule of Interpretation of Statutes that the true meaning of a section must be gathered from the express intention of the legislature. Maxwell in his book "On the Interpretation of Statutes" 10th Edition at page 2 has rightly pointed out that if the words of the statute are in themselves precise and unambiguous no more is necessary than to expound those words in the natural and ordinary sense, the words themselves in such case best declare the intention of the legislature". In the authority New Piece Goods Bazar Co. Ltd. vs. C.I.T. AIR 1950 SC 165, 168 it was held that "a primary duty of a Court is to give effect to the intention of the Legislature as expressed in the words used by it and no outside consideration can be called in aid to find that intention." Again in Amalgamated Electricity Co. (Belgaum) Ltd. vs. Municipal Committee (1969) SC 227, 234 it was held: "That the intention of the Legislature or its delegate has to be gathered from the language of the statutory provisions and not from what it failed to say." Again in Ram Ram Narain Medhi Vs. State of Bombay, AIR 1959 SC 459, 470 it was held : "That if the language of the enactment is clear and unambiguous it would not be legitimate for the Courts to add any words thereto and evolve therefrom some sense which may be said to carry out the supposed intentions of the legislature. The intention of the Legislature is to be gathered only from the words used by it and no such liberties can be taken by the Courts for affecting a supposed intention of the Legislature." Again in Balabhagas Bulaschand vs. State of Orissa 1976 (2) SCC 44-52 the Hon'ble Supreme Court held "that there is a presumption against redunancy and that the Legislature does not waste words or introduce useless or redundant provisions."

8. Even otherwise, if we look at the provisions of the Manual, it is seen that a number of checks and counter checks have been provided to ensure the accuracy of the operations and to avoid any pilferage. First of all the notes are counted and made into a packet by the Examiner. Then the notes in each packet are recounted by the Recounter. The packets are then verified in the Verification Section and both quality and quantity checks are applied. Then those packets are subjected to random check by the Sub-Accountant and to surprise checks by the Staff Officer Gr. II. So long as the notes remain at the stage of verification they are kept in the joint custody of two officers one of which is Cash Department Official and it is after the verification process is over that the notes are transfered to the single custody of one Sub-Accountant. This joint custody of the notes has apparently been provided because the cash section is still responsible till the Verification process is over. Once these notes have passed on to the single custody of the Sub-Accountant after verification, it would appear unreasonable to keep the sword of democles hanging over heads of the Cash Department staff, even after that, for there has been an end to the accountability at some stage.

9. The workmen have also led evidence to prove that there have been precedents that when any deficiency was detected even after the verification process is over, the cash department staff was not held responsible. WW1 Shri Dharam Pal Sharma has stated that in the year 1959 he was working in the Cash Department as Coin/Note Examiner and out of the notes examined by him on 6-4-59 a shortage of Rs. 700 in one of the packets of one hundred denomination was detected. Although initially he was asked to make good the deficiency, on his representation, the bank relented and he was not compelled to make good the deficiency and the shortage was made good by the concerned officer. The veracity of the statement of this witness has not been disputed.

10. With regard to the particulars note packet produced in this case it is seen that the label on the top of the packet has been pasted on it with glue. Not only that even the label itself which seems to have been torn has been reinforced by pasting a separate sheet of paper of same size on the blank side of the label. Para 32 to 35 of the Manual lay down the procedure of making, stitching and labelling of the packets. According to para 32 of the Manual packet containing non-issuable notes will be distinguished by attaching to them labels in form CD 26 in white colour. The Note Examination Staff will fill up the blanks relating to the denomination and number of pieces in the labels and sign legibly at the appropriate place. The label will be placed over the first note in each packet and the packets secured with suitable rubber bands. Para 34 provides that the labelled packets will be got wire stitched on stitching machines in the immediate presence of the staff who prepared the packets. Thus according to these instructions the label is already placed on the packet and then it is got wire stitched. In other words the label which

is now found pasted on the packet in question should have been wire stitched and not pasted. Thus it appears that the packet had been tampered with subsequently and it follows that on merits of the particular case also the Management has got no case.

11. In view of the discussions made above, it is held that the action of the Management of Reserve Bank of India, New Delhi in holding Shri L. N. Aggarwal and Shri Shyam Sunder-II Coin/Note Examiner Gr II responsible for shortage of a ten rupee denomination note in a ten rupee packet bearing seal Delhi dated 19-12-73 and calling upon them to deposit an amount of Rs. 5 each with the Reserve Bank of India is not justified. The Management is directed not to recover the shortage from these workmen and if the recovery has already been made the amount recovered shall be refunded to these workmen. The Management shall also pay costs of Rs. 1,000 to the Union of the workmen.

Further it is ordered that the requisite number of copies of this Award may be forwarded to the Central Government for necessary action at their end.

G. S. KALRA, Presiding Officer
[No. L-12011/56/79-D.II(A)]
N. K. VERMA, Desk Officer

नई दिल्ली, 20 अक्तूबर, 1986

का. आ. 3769—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार मैंगनीज ओर (इण्डिया) लिमिटेड नागपुर, की डोंगरी बुजुर्ग मैंगनीज माईन्स के प्रबंधतंत्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, जबलपुर के पंचाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 7-10-86 को प्राप्त हुआ था।

New Delhi, the 20th October, 1986

S.O. 3769.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal, Jabalpur, as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Dongri Buzurg Manganese Mines of M/s. Manganese Ore (India) Ltd., Nagpur and their workmen, which was received by the Central Government on the 7th October, 1986.

BEFORE SHRI V. S. YADAV, PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVT. INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT, JABALPUR (M.P.)
Case No. CGIT/LC(R)(1)/1984.

PARTIES :

Employers in relation to the management of Dongri Buzurg Manganese Mines of M/s. Manganese Ore (India) Ltd. Mount Road Extension, Sadar, Nagpur (M.S.) and their workmen represented through the Rashtriya Manganese Mazdoor Sangh C/o. MOIL, Nagpur (MS) & Bhartiya Manganese Mazdoor Sangh, Tirodi, Distt. Balaghat (MP).

APPEARANCES :

For Workmen—1. Shri S. S. Shakarwar, Advocate for B.M.M.S. 2. Shri S. K. Rao, Advocate for R.M.M Sangh.

For Management—Shri P. S. Nair, Advocate.

INDUSTRY : Manganese Ore DISTRICT : Nagpur (M.S.)

AWARD

Dated, September, 30, 1986

In exercise of the powers conferred by Clause (d) of Sub-section (1) of Sec 19 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947) the Central Government has referred the following dispute for adjudication, vide Notification No. L-27012/11/83/D-III-B dated 28th December, 1983.

"Whether the action of the management of Dongari Buzurg Manganese Mine of Manganese Ore (India) Ltd., Nagpur in refiring the workers of the erstwhile management of C.P. Manganese Ore Co. Ltd. at the age of 58 years is justified ? If not, to what relief the workmen are entitled ?"

2. The facts relevant for the purpose of this reference which are no longer in dispute are that Dongri Buzurg Mine was owned and controlled by C.P.M.O. Limited, a private concern. On 23rd October, 1977 the mine was taken over by the Manganese Ore (India) Limited in which the Union of India and States of M.P. and Maharashtra owned the shares. The C.P.M.O. Ltd. had their own Standing Orders which did not specify the age of retirement. But it was the practice to retire employees at the age of 60 years. The services of the workers of the C.P.M.O. Ltd. were governed by those Standing Orders. At that time Manganese Ore (India) Limited (M.O.I.L.) had no Standing Orders. There was an agreement between the C.P.M.O. Ltd. and M.O.I. Ltd. at the time of taking over. After taking over of mines by M/s. M.O.I. Ltd. a fresh appointment letters were issued to all the workers of Dongri Buzurg Mines and as per Clause 12 of appointment letter the retiring age was laid down as 60 years. However, M/s. M.O.I. Ltd. got their Standing Orders certified after 28th June 1979. In accordance with the procedure laid down under the Industrial Disputes Act i.e. after notice to registered union and certifying office i.e. the R.L.C. (Central) Jabalpur and R.L.C. (Central) Bombay considered their reasonableness and fairness and certified the same. Relevant provision regarding the superannuation of the said Standing Orders of M/s. M.O.I. Ltd. i.e. Cl. 25(Ka) & 25(Kha) are as under :—

"25 सेवानिवृत्ति

(क) प्रत्येक कामगार 58 वर्ष की उम्र प्राप्त होने पर प्रबन्धक की सेवा से निवृत्त हो जाएगा। आयु के सामान्य प्रमाण की अनुपस्थिति में, अर्थात् जालांत प्रमाणपत्र अथवा नगरपालिका के जन्म प्रमाणपत्र के न होने पर, कामगार के भविष्य निधि अभिलेख के नामांकन प्रपत्र से लिखित आयु को ही उसकी सेवा निवृत्ति की आयु निर्धारित करने का आधार माना जावेगा जिन कामगारों की जन्मतिथि प्रबन्धक के अभिलेख ने सिर्फ वर्ष में दिखाई गई है और जनमें तिथि या माह नहीं दिया गया है तो ऐसा कामगार उस वर्ष से 58 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर पहली जुलाई से सेवानिवृत्ति होगा।

(ख) प्रबन्धक को अपने हितों में यह स्वतंत्रता रहेगी कि वे कामगार को आयु के 58 वर्ष पूरे करने के पश्चात् भी सेवा में रखे, परन्तु 60 वर्ष की आयु के पश्चात् नहीं रखा जायेगा।"

There is a Saving Clause (44) which is as under :—

44. बचाव

"इन स्थायी आदेशों में निहित कोई भी बात किसी अधिनियम या सेवा समझौता के लिखित करार के अंतर्गत प्राप्त अधिकार या तत्कालीन दिये गए पंचाट या नियोक्ता और कामगार के मध्य किये गये करार के अंतर्गत प्राप्त अधिकारों के विपरीत नहीं होंगे और न ही उस पर दुष्प्रभाव डालेंगे।

In view of the above provision the management of M/s. M.O.I. Ltd. started retiring employees at the age of 58 years.

3. It is alleged that some of them have been retired and some are likely to be retired in near future. Hence this reference.

4. The short question for determination before me is that whether this order of superannuating of the former workmen of C.P.M.O. Ltd. at the age of 58 years is justified or not ?

5. In this regard the first contention of the workmen and the unions representing them before me is that these workmen of C.P.M.O. Ltd. were given fresh appointments under the Agreement that their age of superannuation will be 60 years which was in fact mentioned in their order of appointment. Secondly in view of the Saving Clause 44 the management could not have retired them at the age of 58 years. Thirdly even the retiring Clause 25(Kba) gives the directions to the management to notice its workmen at the age of 60 years. Therefore in view of the Agreement

and facts and circumstances and in exercise of the proper discretion at least these former workmen of C.P.M.O. should have been made to retire at the age of 60 years. On the other hand, management has contended that there can never be two different conditions of service for different employees depending on the point of time when they came to be employed. In this regard reliance has been placed on U.P. State Electricity Board and another Vs. Hari Shanker Jain and others (AIR 1979 SC 65); Western India Match Co. Vs. Workmen (1973 LIC SC 1601); Agra Electric Supply Co. Vs. Alladin (AIR 1970 SC 512); Salem-Erode Electricity Distribution Co. Vs. Employees Union (1966-I-LLJ 443). On the other hand, learned Counsel for the workmen relied on Guest, Keen, Williams Private Ltd., Calcutta Vs. P.J. Sterling and others (1959 AIR SC 1279); Also in the case of Agra Electricity Co. Ltd. (supra); Navnit Lal Manilal Bhat Vs. Union of India and others [1973 S.C.C. (L & S) 319]; Kashinath Sahoo Vs. Orissa State Electricity Board (1977 Lab. I.C. 336) and United Provinces Electric Supply Co. Ltd. Vs. T. N. Chatterjee and others (AIR 1972 SC 1201) wherein their Lordships of the Supreme Court held as under :—

> "The scheme and object of the Act clearly show that it was not intended by the legislature that different sets of conditions should apply to employees depending on whether a workman was employed before the standing orders were certified or after. If the intention was otherwise it would lead to industrial unrest and not industrial peace, the latter being the principal object of the legislation. After the amendment of the law in 1956 the Certifying Officer and the appellate authority are duty bound to examine the question of fairness of the standing orders and there can be no justification now not to give effect to the principle of uniformity of conditions of service which is clearly contemplated by the provisions of the Act [AIR 1966 SC 808 and 1970 SC 512 2 Lab. LJ 146(SC) Explained and Distinguished]"

I have gone through the above authorities and I find that their Lordships considered various authorities and held as above relying on AIR 1966 SC 808 and AIR 1970 SC 512 and they explained AIR 1959 SC 1219 and 1964-II-LLJ 146 SC. In para 7 their Lordships further held as under :—

> "It was considered that Guest Keen Williams Pvt. Ltd. (1960) 1 SCR 348=(AIR 1959 SC 1279) could afford no assistance because that matter came to this Court from an industrial dispute which was the subject matter of industrial adjudication and all that this Court did was to fix the age of superannuation for workmen who had been employed prior to the date of the certification of the relevant Standing Orders. That course was adopted in the special and unusual circumstances of that case."

In view of the pronouncement of the above authorities one thing is clear that there can be no different conditions of service for different employees depending upon the point of time when they were employed. Further as has been held in the case of U.P. Co-operative Spinning Mills Ltd., Etawah Vs. State of U.P. and others (1978 LIC p. 1137) that Standing Orders prevailed over contract. Thus the contention of learned Counsel for the management appears to be correct.

6. Coming to the second limb of the contention of the workmen and the unions on the basis of similar Saving Clause in the case of the Steel Workers Union Vs. Chief Labour Commissioner (Central) and Appellate Authority, New Delhi and others (1971 Lab I.C. p. 448)=(AIR 1971 MP 93) it has been held as under :—

> "Uniformity in application to all workmen is the essential attribute of standing orders. Therefore where in the certification proceedings, the authorities under the Act added a saving clause to preserve larger leave benefits to the workmen who were appointed before certain date, that would bring about a differential treatment between the workmen appointed before that date and those appointed after it. Such a clause being destructive of uniformity and therefore not permissible under the Act an application under Section 10(2) for modification of standing orders so as to bring them in uniformity is maintainable."

Similar view was also reiterated in the case of K. A. Abraham Vs. Bhilai Steel Plant of M|s. Hindustan Steel Pvt. Ltd., Bhilai (M.P.) (1979 MPLJ p. 50) and S. A. Waheb and others Vs. Union of India and others (1981 Lab. I.C. 1144). Thus on the basis of Saving Clause workmen and the unions cannot have the age of superannuation as 60 years on the ground of uniformity of service conditions.

7. Coming to the last contention of the workmen and the unions I find that it has some substance. Clause 25 of the Standing Orders reproduced above goes to show that though the retiring age has been fixed at 58 years but the management has been given the discretion to retain the services and retire a person at the age of 60 years. On behalf of the management it has been contended that this discretion is given so that looking to the efficiency and the fitness of the person two years extension may be given.

8. On the other hand, on behalf of the workmen and the unions it has been contended that this clause itself gives two conditions i.e. two age of retirement for the workman, therefore firstly this should be struck off under Sec. 13-A of the Industrial Employment (Standing Orders) Act, 1946 or as violating the principle of natural justice and the clause destructive of principle of uniformity which is not permissible under the Act. I am of the opinion that Sec. 13-A give the Labour Court jurisdiction as to the application or interpretation of Standing Orders. It does not empower this Tribunal to struck out any provision thereof.

9. As for natural justice on that ground also this Court cannot struck it out. It is only the courts having constitutional powers or writ jurisdiction can do so. But I am of the opinion that since there are two age given for retirement of the workmen in the discretion of the management this Court can certainly see whether the principle of natural justice and parity has been violated.

10. In the instant case, the management has not shown that they have laid down any norms for exercising the discretion. The Unions have filed the retirement orders of one Shri M. N. Bawanker dated 7th November, 1982 (Ex. W/1) and 26th February, 1983 (Ex. W/12). These orders give no reason for exercising the discretion or retiring him at the age of 58 years. These orders have been filed as an illustration of other orders also. These orders do not go to show that the management have exercised the jurisdiction on some well established principle, norms or reasons.

11. In the case of these workmen of C.P.M.O. Ltd. it is not disputed on behalf of the management that they were given orders by the M|s. M.O.I. Ltd., agreeing to retire them at the age of 50 years. Perhaps in view of this Saving Clause 44 also incorporated in the Standing Orders for the benefit of these workmen. In such circumstances discretion, if any, should have been exercised in favour of the superannuating these workmen at the age of 60 years. I am also further of the opinion that this discretionary power having not been exercised on a proper discretion violate the principles of natural justice and parity. Therefore the retirement of these workers of C.P.M.O. Ltd. at the age of 58 years cannot said to be justified and proper. Consequently I answer the reference as under :—

1. That the Action of the management of Dongri Buzurg Manganese Mine of Manganese Ore (India) Ltd., Nagpur in retiring the workers of the erstwhile management of C. P. Manganese Ore Co. Ltd. at the age of 58 years is not justified. Consequently they are entitled to the reliefs as under :—

(a) Those of the workmen of C.P.M.O. Co. Ltd. who have already been retired and have not completed the age of 60 years be reinstated with all back wages and all ancillary reliefs till they reach the age of 60 years ;

(b) Those of the workmen who have not been retired so far will continue to be in the service of M|s. M.O.I. Ltd. upto the age of 60 years ;

(c) Those of the workmen who have been retired but died after retirement before they attained the age of 60 years be given their back wages with all ancillary reliefs and other retirement benefits upto the period of their death.

(d) No order as to costs.

V. S. YADAV, Presiding Officer.
[No. L-27012|11|83-D. III(B)]

का० आ० 3770—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार, मै० परशवा माईनिंग एण्ड ट्रेडिंग कं. लिमिटेड, डालमिया नगर, रोहतास के प्रबंधतंत्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, नं. 2 धनबाद के पंचाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 6-10-1986 को प्राप्त हुआ था।

S.O. 3770.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal (No. 2), Dhanbad, as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Ms. Parshva Mining and Trading Co. Ltd., Dalmiyanagar, Rohtas and their workmen which was received by the Central Government on the 6th October, 1986.

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL (NO. 2) AT DHANBAD.

Reference No. 84 of 1986

In the matter of industrial dispute under Section 10(1)(d) of the I.D. Act, 1947.

PARTIES :

Employers in relation to the management of M|s. Parshva Mining and Treding Company Limited and their workmen.

APPEARANCES :

On behalf of the workmen—None.

On behalf of the employers—None.

STATE : Bihar. INDUSTRY : Cement.

Dated, Dhanbad, the 25th September, 1986.

AWARD

The Government of India, Ministry of Labour in exercise of the powers conferred on them under Section 10(1)(d) of the I.D. Act, 1947 has referred the following dispute to this Tribunal for adjudication vide their Order No. L-29011(56)| 84-D.III(B) dated the 16th April, 1985.

THE SCHEDULE

"Whether the action of the management of M|s. Parshva Mining and Trading Co. Ltd., P.O. Dalmianagar, Distt. Rohtas is not making the following piece rated workmen permanent in time rated jobs w.e.f. 1920 is justified ?

1. Shri Murat Bin, Hammerman.
2. Shri Sudama Singh, T. Man.
3. Shri Ram Ugrah, Beldar.
4. Shri Bhola Singh, Beldar.
5. Shri Mandeo Dusadh, T. Man.
6. Shri Kunj Behari, Beldar.
7. Shri Jivnath Bin, T. Man.
8. Shri Chaturgun, Beldar.
9. Shri Budhram, Beldar.
10. Shri Bigum Kumar, 'Raja'.
11. Shri Chandradhan Gareri, 'Raja'.

977 GI/86—11

Inspite of notice being to the sponsoring union by Regd. Post thrice the sponsoring union did not either appear or filed any W. S. in the case. More than 6 months have elapsed from the date of the reference and as such it appears that the sponsoring union is now not at all interested in proceeding with the reference. I hold therefore that the union has no case to present before this Tribunal in this reference.

In the result I hold that the action of the management of M|s. Parshva Mining and Trading Co., Rohtas in not making the concerned wokmen who are piece rated workmen permanent in the time rated job with effect from 1980 is justified and the Award is passed accordingly.

I. N. SINHA, Presiding Officer.
[No. L-29011|56|84-D. III(B)]

का. आ. 3771—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार, वैस्टर्न कोलफील्डस लिमिटेड, गुगुस कालरीज आर. आई.—1 सब ऐरिया नं. 2, जिला चन्द्रापुर के प्रबंधतंत्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, जबलपुर के पंचाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 7-10-1986 को प्राप्त हुआ था।

S.O. 3771.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal, Jabalpur, as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Western Coalfields Limited, Gugus Collieries, R.I. 1, Sub Area No. 2, Distt. Chandrapur and their workmen, which was received by the Cental Government on the 7th October, 1986.

BEFORE SHRI V. S. YADAV, PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVT. INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT, JABALPUR (M.P.).

Case No. CGIT|LC(R)(91) of 1985

PARTIES :

Employers in relation to the management of Western Coal Fields Limited, Gugus Colliery R.I. 1, Sub Area No. 2, Distt. Chandrapur (M.S.) and their workman Shri Devendra Gopal Chatti, Badli Workman represented through the Lal Zanda Coal Mine Mazdoor Union, Machhi Nala, Bangali Camp, P.O. & Distt. Chandrapur (M.S.).

APPEARANCES :

For Union—Shri S. R. Pendre, Genl. Secretary.
For Management—Shri Bal Bir Singh, Personnel Manager.

INDUSTRY : Coal DISTRICT : Chandrapur (MS).

AWARD

Dated, September 24, 1986.

This is a reference made by the Central Government vide Notification No. L-22012|74|84-D. V dated 3rd October, 1985 for adjudication of the following dispute :—

"Whether the action of the management of M|s. Western Coalfields Limited, Sub-Area No. 2, Gugus Collieries, R. I. No. 1, P.O. Gugus, District Chandrapur in stopping from duty and denying wages to Shri Devendra Gopal Chatti, Badli Workman for the period from 12-8-1984 to 31-8-1984 is justified ? If not to what relief the workman was entitled ?"

2. On receipt of the reference order parties were noticed to file their statements of claims, rejoinder documents etc. Parties filed their pleadings and documents and the case was fixed for evidence on 1-9-1986. But on this date parties appeared and filed a compromise petition duly signed by Shri S. R. Pendre, General Secretary, L. C. M. M. U. (CITU) Chandrapur and Shri Balbir Singh, Personnel Manager, The

terms of Settlement as incorporated in the aforesaid compromise petition are as under :—

"1. It has been decided to make 50 per cent payment of the wages for the period from 12-8-1984 to 30-8-1984 (16 days).

2. The Union will not claim any other relief and treat this settlement as full and final settlement of all their claim.

3. The parties shall submit the copies of the settlement to the Tribunal and pray for an award in terms of the settlement."

3. I have gone through the above tems of settlement which appear to be fair, reasonable and in the interest of the workman concerned, Shri Devendra Gopal Chatti, Badli Workman. I therefore record my award in terms of the aforementioned settlement. No order as to costs.

V. S. YADAV, Presiding Officer.
[No. L-22012/74/84-D. V]

नई दिल्ली, 21 अक्तूबर, 1986

का. आ. 3772 —औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार, डब्ल्यू सी. एल, कोरबा की बंकी कालरी के प्रबंधतंत्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, जबलपुर के पंचाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 7-10-1986 को प्राप्त हुआ था।

New Delhi, the 21st October, 1986

S.O. 3772.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby pubilshes the award of the Central Government Industrial Tribunal, Jabalpur, as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Banki Colliery of W.C. Ltd., Korba and their workmen, which was received by the Central Government on the 7th October, 1986.

BEFORE SHRI V. S YADAV, PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT, JABALPUR (M.P.)

Case No. CGIT/LC(R)(18)/1984

PARTIES :

Employers in relation to the management of Banki Colliery of Western Coalfields Limited, Korba, District Bilaspur and their workmen S/Shri M. C. Ghosh, Ramakhya Rai and Pathiram, Electrical Fitter in Category IV represented through the Samyukta Khadan Mazdoor Sangh (AITUC) Bankimogra, Post Bankimogra, District Bilaspur, (M.P.)

APPEARANCES :

For Union—Shri K. R. N. Nair.

For Management—Shri P. S. Nair, Advocate.

INDUSTRY : Coal DISTRICT : Bilaspur (M P.)

AWARD

Dated : Septemebr 26, 1986

This is a reference made by the Central Government vide Notification No. L-22012/8/83-D.III(B)/D.IV(B) Dated 25th February, 1984 for adiudication of the following dispute :—

"Whether the action of the Sub-Area Manager, Banki Colliery of M/s. Western Coalfields Limited, Korba, in denying promotion to S/Shri M. C. Ghosh, Ramakhya Rai and Pathiram, Electrical Fitter in Category IV to the post of Electrical Fitter in Category V is justified? If not, to what relief the concerned workmen is entitled?"

2. It is not disputed that the workmen are working as Electrical Fitter Cat. IV from July 1971. There were some vacancies for promotion of Cat. V and for that D.P.C. was constituted and the workmen have faced D.P.C. but they were not promoted till 19-6-1984 inspite of representations through the Union.

3. The case of the workmen is that they have passed D.P.C. but they were not promoted on the flimsy ground that they are not possessing the electrical licence on four subjects viz. (1) Industrial (2) Domestic (3) Underground (4) Overhead. The General Manager, Korba, who is alleged to have passed such an order has no legal authority to frame new rules effecting change of service conditions of the workers. Since the collieries of Western Coalfields Limited are situated in three states i.e. Madhya Pradesh, Orissa and Maharashtra and their services are transferable from one to another colliery of other states hence this change of service conditions amounts to discrimination.

4. The case of the mangement is that the General Manager, Western Coalfields Limited, Korba, in consultation with the various Sub-Area Managers, Deputy Chief Engineers (E & M), Personnel Manager, Korba and the Head Quarters of Western Coalfields Limited has laid down such qualifications. The General Manager was thus competent to exercise his right of managerial function in relation to promotion to lay down certain qualifications in the interest of administrative functions and efficiency.

5. In support of their case the workmen examined Patiram (W.W. 1) and the management examined U. K. Panigrahi (M.W. 1) who proved Ex. M/1 and Ex. M/2 Ex. M/1 is the order of promotion of S/Shri M. C. Ghosh and Patiram and six others and Ex. M/2 is the office order dated 28th March, 1981 wherein the conditions of promotion were laid down.

6. The short question for decision before me is whether the General Manager was competent to lay down such a condition. If so, whether it amounts to discrimination?

7. On behalf of the management it has been contended that the General Manager is the head of the department as such he is entitled to lay down the conditions for promotion. While on the other hand, the case of the workmen is that Western Coalfields Limited is a national organisation and the workers are liable to be transferred from one unit to another. Western Coalfields Ltd. has got such unit in Orissa, Maharashtra and Madhya Pradesh and there is no licencing system in the Orissa Electricity Board. So it will amount to discrimination if certain conditions of promotion is put in one unit only. Shri U. K. Panigrahi (M.W. 1) who was examined on behalf of the management has admitted that Western Coalfields Limited is a big Multi-State Organisation and services of these workmen are transferable to any colliery. Looking to this admitted position I am of the opinion that if any change in the promotion policy is to be made it should be done by an authority whose orders are applicable to all the units of the management i.e. perhaps the Chairman-cum-Managing Director. In any case if minor change like requirement of particular qualification for certificate is made it could be done in consultation with all the General Managers of all units so that an uniform policy is adopted in all the collieries. Ex. M/2 dated 28th March, 1981 the order of General Manager, Korba goes to show that he has passed the order "After consultation with the Sub-Area Manager, Dy. Chief Engineer (E&M) and Personnel Manager, Korba Area and after discussions in Nagpur Co-ordination meeting of Sub-Area Managers and the Area Staff Officers on 26-3-81." This goes to show that he only consulted his subordinate officers and not any officer or General Managers equivalent to his rank or any superior authority so that the orders be made applicable to all the mines of the Western Coalfields Limited in all the three States. This having not been done it amounts to discrimination and will violate the principles of natural justice. Therefore the order dated 28-3-1981 cannot be sustained and any promotion withheld by D.P.C. or Sub-Area Manager on that account cannot be allowed to prevail. In view of my above findings I answer the reference as under :—

The action of the Sub-Area Manager, Banki Colliery of M/s. Western Coalfields Liimted, Korba, in denying pro-

motion to S/Shri M. C. Ghosh, Ramakhya Rai and Pathiram, Electrical Fitter in Category IV to the post of Electrical Fitter in Category V is not justified. Therefore they should have been deemed to be promoted from July 1971 or from which date their promotion first became due and they should be paid their difference of salary with effect from that date with all consequential benefits. No order as to costs.

V. S. YADAV, Presiding Officer
[No. L-22012/8/83-D.III(B)]
V. K. SHARMA, Desk Officer

नई दिल्ली, 20 अक्तूबर, 1986

का. आ. 3773.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार दूरदर्शन केन्द्र गुलबरगा के प्रबंधतंत्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में औद्योगिक अधिकरण बेंगलौर के पंचाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 3-10-86 को प्राप्त हुआ था ।

New Delhi, the 20th October, 1986

S.O. 3773.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Industrial Tribunal, Bangalore as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Doordarshan Kendra, Gulbarga and their workmen, which was received by the Central Government on the 3rd October, 1986.

BEFORE THE INDUSTRIAL TRIBUNAL IN KARNATAKA, BANGALORE

Dated this the 19th day of September 1986

PRESENT :

Sri R. Ramakrishna, B.A., B.L.—Presiding Officer
Central Reference No. 8 of 1984

I Party

Sri Shantrappa, S/o Sidramappa, C/o S. B. Hatti, Advocate, H. No. 3695, Gazipura, Gulbarga.

Vs.

II Party

The Station Engineer, Doordarshan Kendra, Opp. Vijaya Hotel, Khoba Plot, Gulbarga.

APPEARANCES :

For the I Party—Sri S. Krishnaiah, Advocate, Bangalore.

For the II Party—Sri R. A. Patil, Government Pleader, Gulbarga.

REFERENCE :

(Government Order No. L-42012(15)/83-D.II (B) dated 13-2-1984)

AWARD

The Central Government after forming an opinion that an Industrial Dispute exists between the above parties has referred the said dispute for adjudication under Section 7-A and clause (d) of sub-section (1) of Section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 on the following Schedule :—

SCHEDULE

"Whether the action of Doordarshan Kendra, Gulbarga in denying continuous employment from 15-10-82 to Shri Shantreppa is justified ? If not, to what relief is the workman entitled ?"

2. The I Party has filed his claim statement on 26-3-1984. He has filed an application on 1-2-86 for amendment of the claim statement by adding an additional para which was allowed by this Tribunal.

3. The gist and substance of the averments made by the I Party in his claim statement is that he has joined the service in the year 1977 and was discharging his duties honestly and deligently to the satisfaction of his superiors till he was denied his continuance employment from 15-10-82. He has put in more than 240 days of continuous service, hence the act of the II Party amounts to retrenchment within the meaning of Section 2(oo) of the Act. He has not been paid one month's wages in lieu of notice and compensation at the rate of 15 days for each year of service. Hence the act of the II Party is hit by Section 25-F (a) and (b) of the Act. He as a casual labourer was doing all kinds of work, such as, Mali, Gardener, Sweeper and Watchman. Though he has attained the status of a parmanent workman, he has been denied the benefits as per various labour laws.

4. He has further contended that he has worked from 1-9-77 to 1-2-79 and 1-4-79 to 14-10-82 continuously. Two months break given to him after 1-2-79 and he was again re-appointed from 1-4-79 to 14-10-82 on a daily wages of Rs. 7 per day. His latter service is borne out in the attendance Register which requires for verification by this Tribunal. From 15-10-82 he was taken on duty on alternative days and ultimately he was refused employment. Since he has crossed more than 30 years of age he is not able to get any Government job and as per natural justice and humanitarian ground he is entitled for reinstatement and for arrears of back wages.

5. The II Party in their statement have contended that this workman was engaged on daily wage basis without any appointment order with effect from 25-11-1977 to 1-2-1979 and again from 1-4-1979 to 14-10-1982 with breaks. The payment was made once in a month for the days worked and his nature of work is a casual miscellaneous. It is further contended since there was not much of a work from 15-10-82 the I Party was asked to come on alternate days. Accordingly, the I Party came for work from 18-10-82 to 7-11-82 on alternate days and thereafter he has abruptly abstained from duties without intimating the II Party and once again he came on 7-12-82 for receiving the wages.

6. Since there is no post of Mali existing with the II Party, the question of reinstatement of service or payment of back wages from 15-10-82 without I Party working as a casual labourer does not arise. While the I Party was engaged he was advised on several occasions to try for a regular job somewhere else and a certificate was issued by Sri H. L. Sitaramu in his personal capacity, with a view to help the I Party to seek the employment some where else and the same has not binding on the II Party. The I Party instead of reporting for duty on alternate days or as and when work is available absented himself and raised this dispute. Hence the claim of the I Party is liable to be rejected.

7. Since the points for adjudication does not call for framing of any additional issues, the parties have been directed to adduce their evidence in support of the contentions raised by them in their pleadings. Accordingly, the I Party has examined himself and closed his evidence and the II Party after examining the Station Engineer have closed their evidence.

8. Now the point that arises for determination is :

(1) Whether the II Party have denied the continuous employment from 15-10-82 ? If so, such denial amounts to retrenchment ?
(2) What order ?

9. Point No. 1.—The I Party has deposed in his evidence that he joined the II Party in the year 1977 and worked upto October 1982. He was doing the duties, such as, Sweeper, helper, cook and watchman. On 15-10-82 he was informed by the Head Clerk that he should not attend duty from that day onwards. Ext. W-1 is a certificate issued to him by one Sri Sitaramu. He prayed to pass an award declaring him as a permanent workman from 13-10-82 with all consequential benefits.

10. In the cross-examination, it is elicited that from the date of his joining he used to get the wages for the number of days worked by him. He used to do particular work due to the absence of a particular workman. He has not made any written representation to the Station Engineer or to any official the fact that the Head Clerk informed him not to attend duty from 15-10-82. The Station Engineer has not informed him either orally or in writing

that he should not attend duty from 15-10-82 on wards. The Employment Exchange has not sponsored his name at any time. Mr. Sitaramu gave a certificate when he requested him that the same is required for the purpose of getting employment in the University. He has denied the suggestion that the regular appointments will be made only to the persons whose names are sponsored by the Employment Exchange and since his name was not sponsored due to his age he has raised this dispute to get an employment.

11. Against this evidence, the witness for the II Party Sri Balaraman, the Station Engineer has deposed that he is the appointing authority from Class IV upto Head Clerk and the sanctioning authority is the Ministry of Information and Broadcasting. There was no post of Mali in Doordarshan Kendra and as per the norms no such post is existing even at present.

12. He has further deposed that the I Party workman was not appointed as a casual labourer but he used to do work on daily wages whenever there was scope for the work and some times he used to work as a casual labourer to held the Engineer and at some times he was asked to do the garden work. No appointment order was issued to him nor any termination order and he was asked to come to the Kendra whenever there was work. He has further deposed that the I Party-workman himself stopped coming to the Kendra and he never asked him not to come to the Kendra. The certificate Ext. W-1 from the Assistant Engineer is not a valid one as he had no power to issue and the procedure is that issue of any certificate should be entered in their records and sent through despatch.

13. In the cross-examination of this witness it was elicited that during 1982 the staff's strength of the II Party was around 40 including Engineers, Helpers, Security Guards, Messenger, Sweeper, etc. When this workman was appointed no appointment order was issued and he was working from 1977 as noted in the attendance registers Exts. M-1 and M-2 upto November 1982. It is further elicited that another 5 persons who are working as casual labourers have been appointed on regular basis who are juniors to the I Party-workman as their names have been sponsored by the Employment Exchange for the permanent post. It is further elicited that he is not aware of the request of the workman to regularise his work on 15-10-82 as he was not working at that time as he came on 22-10-82. He has not denied the certificate issued by one Assistant Engineer Sitaramu. kept maintained that he had no authority to issue. He has also admitted the fact of making permanent of some casual labourers when their names have been sponsored through Employment Exchange and he has got documents to show this fact.

14. On a scrutiny of the evidence by both the sides there is absolutely no contraversy that the I Party workman was initially engaged to do the work in the II Party on 1-9-77 and worked upto 15-10-82 with a break of 2 monhts from 1-2-79 to 1-4-79. It is also not denied that this workman worked in various capacities, such as gardener, watchman, helper, etc.

15. The contentions raised by the II Party to justify their case is that Doordarshan is not an industry, the workman has not been appointed as a casual labourer, the workman himself stopped attending his duties from 15-10-82 hence they are not obliged to follow the procedure under Section 2(oo) and the workman is not entitled for any relief. Their further contention is that they are governed under Articles 310 and 311 of the Constitution of India and any appointment for a permanent post should be sponsored by the Employment Exchange and since the name of this workman is not sponsored they are compelled to appoint some of his juniors whose names have been sponsored by the Employment Exchange. It should be noted at this juncture that MW-1 though stated that he is the appointing authority and 3 juniors to this workman have been appointed as their names have been sponsored by the Employment Exchange, no documents have been produced before this Tribunal though it is stated that they are available in the custody of the II Party. Passing for a moment these admitted facts, we have to discuss the various contenitons raised by the II Party to justify for the action taken by them in discontinuing the service of the I Party workman after 15-10-82. Though it is stated that he himself has stopped coming to the Kendra no materials are forth-coming to appreciate this aspect of the matter as generally this could have been found in the proceedings before the conciliation officer. The discussion so far made is based on the pleadings and evidence placed by the parties. In the background of these we have to discuss the law on these facts.

16. The learned counsel for the II Party, though has not pleaded the fact that the II Party is not an industry in his pleadings, he at a later stage has contended that the Doordarshan is not an industry. The learned counsel has relied on an Office Memorandum dated 26-6-85 issued by the Directorate General, Doordarshan Mandi House New Delhi. On a perusal of the extract from the notes recorded this conclusion is reached by the Ministry of Law, Justice and Company Affairs relying on the decision of the Supreme Court in Bangalore Water Supply vs. A. Rajappa reported in AIR 1978 SC 548. This Court is not bound by the reasons adopted in the extract submitted before this Tribunal, hence it is necessary to advert on the case laws presently available before this Tribunal.

17. Section 2(j) defines "industry" as follows :—

> "Industry" means any business, trade, undertaking, manufacture or calling of employers and includes any calling, service, employment, handicraft or industry occupation or avocation of workman."

18. The Hon'ble Supreme Court had the occasion to define the term industry in D. N. Banerjee vs. P. R. Mookerjee, (1953 I L.L.J. 159) where it is held :—

> "A public utility service such as railways, telephones and the supply of power, light or water to the public may be carried on by private companies or business corporation. Even conservancy or sanitation may be so carried on, though after the introduction of local self-Government this work has in almost every country been assigned as a duty to local bodies like our Municipalities or District Boards or Local Boards. A dispute in these services between employers and workmen is an industrial dispute and the proviso to S. 10 lays down that where such a dispute arises and a notice under S. 22 has been given, the appropriate Government shall make a reference under the sub-section. If the public utility service is carried on by a corporation like a Municipality which is the creature of a statute and which functions under the limitations imposed by the statute, does it cease to be an industry for this reason ? The only ground on which one could say that what would amount to the carrying on of an industry if it is done by a private person ceases to be so if the same work is carried on by a local body like a Municipality is that in the latter there is nothing like the investment of any capital or the existence of a profit-earning motive as there generally is in a business. But neither the one not the other seems a 'since quanon' or necessary element in the modern conception of industry".

19. Following the principle enunciated in the above judgment, a Full Bench of the Hon'ble Supreme Court in Bangalore Water Supply case has observed :

> "Where (i) systematic activity, (ii) organised by co-operation between the employer and employee (the direct and substantial element is chimerical), (iii) for the production and/or distribution of goods and services calculated to satisfy human wants and wishes (not spiritual or religious but inclusive of material things or services geared to calestial bliss, i.e. making, on a large scale prasad or food) prima facie, there is an 'industry' in that enterprise."

20. The above observations of the Hon'ble Supreme Court have been followed in Tapan Kumar Jana vs. Calcutta Telephones, reported in 1981 II L.L.J. 382, Their Lordships of the Calcutta High Court have held at para No. 13 as follows :

> "It is contended that as rules have been framed under Arts. 310 and 311 governing the conditions of service of the employees of the Calcutta, Telephones

it cannot be treated as an industry within the meaning of S. 2(j). This contention is fallacious. The said observation has been made by Bg. C.J. in regard to the governmental function only. In our opinion the observation cannot be read de hors that preceded and followed it. The observation will not apply to pubic utility services about which Beg, C.J. immediately after the said observation, observed that he was impressed by the argument that certain public utility services which were carried out by governmental agency or corporations were treated by the Act itself as within the sphere of industry. Further it was observed that the meaning of the term "industry" should be determined in the context of and for the purposes of matters provided for in the Act. In the circumstances we hold that the Calcutta Telephones is an industry within the meaning of S. 2(j) of the Act as rightly held by the learned Judge".

21. In view of the observations made in the above said decisions that Doordarshan Kendra is an industry within the meaning of Sec. 2(j) of the Act.

22. The next question is whether the I Party being only a casual labourer is a workman within the meaning of Sec. 2(s) of the Act. When similar question arose in Tapan Kumar Juna's case at page No. 15 of the judgment, Their Lordships have held :

"The definition has not provided for the exclusion of a casual labourer from the category of workman, nor has it laid down that only the permanent employees of an industry will be workmen. Certain employees have been excluded from the operation of the definition of "workman", but such exceptions also do not include a casual labourer. The primary condition that has to be fulfilled by an employee to bring him within the definition of "workman" is that he must be employed in an industry for hire or reward. The concept of permanent employment is not the only criterion of the definition of the term "workman". Any employee who satisfies the primary condition as stated above and who does not come within the exception contained in the definition will be a workman. If a casual labourer is employed in an industry for hire or reward, he will be a "workman" within the meaning of S. 2(s). There is nothing in the definition of terms ("workman") which excludes a casual labourer. On the contrary S. 25-C of the Act gives a sufficient indication that a badli-workman or a casual workman is a workman which it excludes them from the right to compensation for lay-off. In Digwadih Colliery v. Their Workman, (1965-II L.L.J. 118), the Supreme Court upheld the award of the Central Government Industrial Tribunal, Dhanbad, holding that the termination of the services of a badli-workman amounted to retrenchment within the meaning of S. 2(oo) of the Act. In other words, it was impliedly ruled by the Supreme Court that a badli-workman was a "workman" within the meaning of the definition of the term "workman". In Pilot Pen Company (India) Limited v. The Presiding Officer, Additional Labour Court, Madras (1971-I LLJ 241), it was held by the Madras High Court that there was no room for the contention that S. 2(s) incorporation into it the idea that only a permanent employee can be construed to be a workman. In P. Joseph v. Management of Gopal Textiles Mills, (1975 I LLJ 136), it has been observed that the definition of "workman" does not exclude even the casual employee or a substitute like "badli". The learned Judge has relied on the above two decisions and has come to the conclusion that the appellant who is a casual labourer is a "workman" within the meaning of S. 2(s) of the Act. In our view, the learned Judge is perfectly justified in holding that the appellant is a workman".

23. Now the important question that arises for determination is whether the stoppage of this workman amounts to retrenchment as contemplated under law. The workman has contended in his evidence that he was working continuously upto 15-10-82, then he was informed by the Head Clerk that he should not attend his duty from that day onwards. The name of the said head clerk was given by him as one Mr. Karambekar. Though this fact was denied by the witness of the II Party they have not made out a case that such Karambekar is not existing or alternatively have not made any effort to examine him to disprove the facts narrated by the I Party-workman. Admittedly, this workman has worked continuously from 1-9-77 to 31-1-79 and then from 1-4-79 to 15-10-82 more than 240 days in each calendar year. This bears testimony in the attendance register produced and marked as Exts. M-1 and M-2. Since the instructions given by the head clerk amounts to termination, now we have to look whether such an act falls within the ambit of Section 2(oo) of the Act. Section 2(oo) defines retrenchment as follows :

" 'Retrenchment' means the termination by the employer of the service of a workman for any reason whatsoever otherwise than as a punishment inflicted by way of disciplinary action, but does not include.

(a) a voluntary retirement of the workmen; or

(b) retirement of the workman on reaching the age of superannuation if the contract of employment between the employer and workman concerned contains a stipulation in that behalf ; or

(c) termination of the service of a workman on ground of continued ill-health."

24. On a reading of the above definition that except the four exceptions provided the termination of the service of a workman for any reason whatsoever will be retrenchment.

25. Admittedly, in this case the II Party has not followed the procedure laid down under Section 25-F and other clauses mentioned in Chapter V-A. It is also shown before this Tribunal that some of his junior casual labourers to that of the I Party workman were appointed as permanent workmen that is again a breach under Section 25-H of the Act. Hence I hold this point in the affirmative.

26. In the result, I make the following award :—

AWARD

The II Party-Management are not justified in denying the continuous employment to the I Party-workman from 15-10-82. Consequently, the workman is entitled for an order of reinstatement with continuity of service and back wages calculated at Rs. 7 per day from 15-10-82 to the date of this award. The workman is also entitled to the cost of this litigation qualified Rs. 250 from the II Party.

(Dictated to the Stenographer, transcribed and typed by him and corrected by me).

R. RAMAKRISHNA, Presiding Officer
[No. L-42012/15/83-D.II (B)]
HARI SINGH, Desk Officer

नई दिल्ली, 21 अक्तूबर, 1986

का. आ. 3774—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार, न्यू बैंक ऑफ इंडिया के प्रबंधतंत्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, नई दिल्ली के पंचाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 3 अक्तूबर, 1986 को प्राप्त हुआ था।

New Delhi, the 21st October, 1986

S.O. 3774.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947, the Central Government hereby published the award of the Central Government Industrial Tribunal, New Delhi as shown in the Industrial Disputes between the employers in relation to the New Bank of India and their workman, which was received by the Central Government on the 3rd October, 1986.

BEFORE SHRI G. S. KALRA, PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL, NEW DELHI

I. D. No. 178/81

In the matter of dispute between :

Shri Charan Dass, So Shri Phoolamal,
resident of 244 Goal Masit, Sharifura,
Amritsar.

Versus

The Management of New Bank of India, having its H.O. 1 Tolstoy Marg, New Delhi.

APPEARANCES :

Shri Vipin Gupta—for the workman.

Shri N. C. Sikri with Shri Inder Bir Singh—for Management.

AWARD

The Central Government in the Ministry of Labour vide its Notification No. L-12012/114/81-D.II (A) dated 9-12-1981 has referred the following industrial dispute to the Tribunal for adjudication :

"Whether the action of the management of New Bank of India in relation to their H.M.V. Extension Counter, Jullundur Branch in terminating the services of Shri Charan Dass, Peon, with effect from 1-4-1980 is justified ? If not, to what relief is the concerned workman entitled ?"

2. The case of the workman as set forth in the statement of claim, in short, is that he worked with the respondent bank for the period from 17-10-78 to 26-10-78 at Dhilwan branch District Kapurthala, from 7-11-78 to 21-2-79 at Hans Raj Mahilla Mahavidayala branch at G.T. Road, Jullundur and from 26-10-79 to 1-4-1980 at Hans Raj Mahilla Mahavidayala G.T. Road Jullundur. No letters of appointment or termination of services were issued except for his appointment in the third spell and final termination on 1-4-1980. It is further stated that the break in service from 22-2-79 to 25-10-79 was fictitious and illegal and that the post in the Hans Raj Mahila Mahavidayala branch was of a permanent nature and the workman should have been regularised on permanent basis against the said post. In this way there has been violation of the provisions of paras 5.22 of the Shastry Award and section 22(1) of the Punjab Shops and Commercial Establishments Act. After his removal a number of other persons had been appointed to the various posts in the bank and no opportunity was given to him for re-employment and hence there has been violation of section 25-H of the I. D. Act. Hence the workman has sought his reinstatement with continuity of service w.e.f. 7-11-78 with full back wages.

3. The Management in its written statement stated that the workman had worked intermittently in leave arrangements and/or as an additional hand purely on temporary basis and on fixed duration as per details given below :

Sr. No.	Name of the branch	Period	Days	Remarks
1	2	3	6	5
	Year 1978			
1.	Dhilwan	17-10-78 to 26-10-78	10	In leave arrangement in place of Chandan Singh. The total No. of days worked in 1978 is 63.
2.	G.T. Road Jullundur	7-11-78 to 6-12-78	30	
3.	G.T. Road Jullundur	9-12-78 to 8-1-79	23	(Addl) MM V
		Total :	63	
	Year 1979			
6.	G.T. Road Jullundur	10-1-79 to 8-2-79	30	Enganged on temporary basis on expediency of work.
5.	G.T. Road Jullundur	26-10- to 79 25-11-79	31	
6.	G.T. Road Jullundur	28-11-79 to 28-12-79	31	
		Total :	92	
	Year 1980			
7.	G.T. Road Jullundur	1-1-80 to 28-1-80	28	Total comes to 90 days intermittently
8.	G.T. Road Jullundur	30-1-80 to 28-2-80	30	
9.	G.T. Road Jullundur	1-3-80 to 1-4-80	32 days	
		Total :	90	

4. On every occasion the accounts of the workman were settled and he accepted the same without any protest or demur. In fact the workman was accommodated in a temporary arrangement at his own request after a lapse of more than 8 months after the cessation of his second assignment and that too intermittently. The workman as per his own admission has not worked for 240 days in a year and as per his own contention he had worked only for 152 days prior to 1-4-1980, and therefore the workman has no legal right to ask for permanent absorption. The provisions of the Bipartite Setlement dated 19-10-66 do not confer any right upon the workman and they are only recommendatory and not mandatory. The reference to para 5.22 of the Shastry Award is misconceived, and the claimant also cannot take any advantage of the provisions of Punjab Shops and Commercial Establishments Act. There was also no violation of the provisions of the Industrial Disputes Act. Management also raised preliminary objection that the appropriate government had made reference without application of mind and the Assistant Labour Commissioner had not provided any opportunity to the bank to represent its case and thus the reference is bad in law.

5. First of all the preliminary objection of the Management that the reference is bad in law is taken up. No evidence has been produced which could show that there was any denial of opportunity to the Management to represent its case before the Assistant Labour Commissioner Chandigarh or that there was no application of mind by appropriate government before making the reference. Rather the order of reference itself would show that it had been made after application of mind and forming opinion that an industrial dispute existed between the parties and it was a fit case for reference to this Tribunal for adjudication. Hence I do not find any merit in this objection and it is hereby rejected.

6. On merits, the workman's own case is that he had worked with the Management in broken periods. His contention that the break in service from 22-2-79 to 25-10-79 was artificial is unacceptable because it is of such a long duration and moreover it is the workman's own case and indeed of the Management also, that he had made number of representations and was provided re-employment. It is also clear from the statement of claim of the workman that he had not completed the requisite 240 days of service in

the year preceding to the date of termination 1-4-1980. Rather as per his own statement he had worked for the period from 26-10-79 to 1-4-80 which works out to 156 days, before his alleged termination on 1-4-80. Therefore, the provisions of section 25-F of the I.D. Act are clearly not attracted. The Ld. representative of the workman has relied upon the authority K. C. Co-operative Bank Limited Vs. Labour Court 1984 Lab. I.C. 974 Punjab and Haryana High Court but the said authority is not applicable to the facts of the present case in as much as in the said authority the workman had rendered 230 days, service with notional breaks and he was on the verge of completing 240 days' service when his services were terminated and hence it was held that it amounted to an unfair labour practice and his reinstatement was justified, whereas in the present case according to the workman himself he had put in only about 156 days of service before the date of his termination 1-4-80 and he was nowhere near to completing 240 days. The Ld. representative of the management has on the other hand produced a photostat copy of the Award of my ld. Predecessor Shri O. P. Singla dated 16-10-1984 in I.D. No. 237/83 Shri Murli Dhar Tewari Vs. New Bank of India wherein my ld. Predecessor had made an observation that Chapter VA of the I.D. Act does not seem to apply to the workman who did not work 240 days in a year and whose services being temporary were terminated. With due deference to my Ld. Predecessor I am inclined to differ from him in as much as the requirement of 240 days work in a year is not necessary for all the sections contained in Chapter VA. This requirement is confined only to section 25-F but is not necessary for the application of section 25-G and 25-H of the I.D. Act. All the same it is absolutely essential for a case to attract the provisions of section 25-G and 25-H that the termination should amount to retrenchment. Thus the crux of the present dispute is whether the termination of the services of the claimant amount to retrenchment or not. The Hon'ble High Court of Madras in S. Palani Vs. Indian Bank and another 1980 LLJ (1) 187, after detailed examination of the term "retrenchment" as exponded by the Hon'ble Supreme Court of India in Hari Persiad Shiv Shankar Shukla and ganther Vs. A. D. Divalkar and others AIR 1957 SC 121 and in N. Sundaramony Vs. State Bank of India, Kuzhithurai Branch (1973-II. LLJ 551) and State Bank of India Vs. N. Sundaramony, 1975-1 LLJ 453 has held that the word retrenchment in Section S-2(oo) of the I.D. Act has been understood in the ordinary sense namely discharge of surplus workman in an existing or continuing business or industry. The facts of the said Madras Authority are similar to the facts of the present case and the Hon'ble Madras High Court has further held as under :

> "25. Therefore, I hold that the ouster of the petitioner in this case who was working only in leave vacancies in broken periods in all for a period of 133 days during the period from 2-12-1974 to 2-3-1976 on the ground that the permanent incumbent had returned from leave, does not amount to retrenchment and S. 25-H of the Industrial Disputes Act and Rule 78(1) of the Industrial Disputes (Central) Rules are not attracted and the petitioner is not entitled to the relief claimed."

7. In the present case also the services of the workman were not terminated on the ground that he had become surplus but were terminated for the reasons that he was appointed against leave arrangements on purely temporary basis and his term came to an end by flux of time. Hence the provisions of section 25-H of the I.D. Act are not attracted in this case and the workman is not entitled to reinstatement.

8. In view of the discussion made above, the workman is not entitled to any relief and this reference is disposed of accordingly.

Further it is ordered that the requisite number of copies of this Award may be forwarded to the Central Government for necessary action at their end.

G. S. KALRA, Presiding Officer
[No. L-12012/114/81-D.II(A)/D.IV(A)]

September 19, 1986.

K. J. DYVA PRASAD, Desk Officer

नई दिल्ली 24 अक्तूबर 1986

का. आ. 3775—धातुमय खान विनियमन, 1961 के विनियम 11 के उप विनियम (2) और (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार श्री पी. सी. गुप्ता के स्थान पर श्री एम. ए. खान को खनन परीक्षा बोर्ड का सदस्य नियुक्त करती है और तत्कालीन श्रम तथा पुनर्वास मंत्रालय श्रम विभाग की दिनांक 21 अगस्त, 1984 की अधिसूचना संख्या का. आ. 2847 में निम्नलिखित संशोधन करती है।

2. उक्त अधिसूचना में, क्रमांक 6 में "सदस्य" शीर्षक में, वर्तमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात :—

श्री एम. ए. खान,
कार्यकारी निदेशक,
हिन्दुस्तान कापर लिमिटेड
10 कामक स्ट्रीट, कलकत्ता-7000 19

[संख्या बी-23012/2/84-एम.-1
राम कानूगा, अवर सचिव

New Delhi, the 24th October, 1986

S.O. 3775.—In exercise of the powers conferred by sub-regulations (2) and (3) of regulation 11 of the Metalliferous Mines Regulations, 1961, the Central Government hereby appoints Shri M. A. Khan, as a member of the Board of Mining Examinations vice Shri P. C. Gupta and makes the following amendments in the notification of the Government of India in the late Ministry of Labour and Rehabilitation, Department of Labour S.O. No. 2847, dated the 21st August, 1984.

2. In the said notification, against the heading 'Members', against serial number, for the existing entry, the following entry shall be substituted, namely :—

"Shri M. A. Khan,
Executive Director,
Hindustan Copper Limited,
10, Camac Street,
Calcutta 700017."

[No. V-23012/2/84-MI]
RAM KANUGA, Under Secy.

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

नई दिल्ली, 1 नवम्बर, 1986

का० आ० 3776:—केन्द्रीय सरकार, स्वापक औषधि और मन: प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (1985 का 61) की धारा 42 की उपधारा (1) और धारा 67 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं० का० आ० 822 (अ), तारीख 14 नवम्बर, 1985 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात :—

उक्त अधिसूचना में "आसूचना ब्यूरो" शब्दों के पश्चात "और स्वापक नियंत्रण ब्यूरो" शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे।

[संख्या 6/86-फा० सं० 664/75/86-अफीम]

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

New Delhi, the 1st November, 1986

S.O. 3776.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 42 and section 67 of the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 (61 of 1985), the Central Government hereby makes the following amendment in the notication of the Government in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. S.O. 822 (E) dated the 14th November, 1985 namely:—

In the said notification, after the words, "intelligence Bureau", the words, "and Narcotics Control Bureau" shall be inserted.

[No. 6/86-F. No. 664/75/86-OPIUM]

का०आ० 3777 :—केन्द्रीय सरकार, स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (1985 का 61) की धारा 53 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सभी राज्य सरकारों से परामर्श करने के पश्चात्, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं० का० आ० 823 (अ) तारीख 14 नवम्बर, 1985 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में "आसूचना ब्यूरों" शब्दों के पश्चात "और स्वापक नियंत्रण ब्यूरो" शब्द अंत: स्थापित किए जाएंगे ।

[सं० 7/86—फा० सं० 664/75/86—अफीम]

S.O. 3777.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 53 of the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 (61 of 1985), the Central Government, after consultation with all the State Governments, hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. S.O. 823 (E) dated the 14th November, 1985, namely:—

In the said notification, after the words, "Intelligence Bureau", the words, "and Narcotics Control Bureau" shall be inserted.

[No. 7/86-F. No. 664/75/86-OPIUM]

का०आ० 3778 :—केन्द्रीय सरकार, स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (1985 का 61) की धारा 41 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं० का० आ० 824 (अ) तारीख 14 नवम्बर, 1985 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में, "आसूचना ब्यूरों" शब्दों के पश्चात "और स्वापक नियंत्रण ब्यूरों शब्द अंत: स्थापित किए जाएंगे ।

[सं० 8/86-फा० सं० 664/75-86 अफीम]

वी० कण्णन, अवर सचिव

S.O. 3778.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 41 of the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 (61 of 1985), the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. S.O. 824 (E) dated the 14th November, 1985, namely:—

In the said notification, after the words, "Intelligence Bureau", the words, "and Narcotics Control Bureau" shall be inserted.

[No. 8/86-F. No. 664/75/86-OPIUM]

V. KANNAN, Under Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1986